फाल्गुन कृष्ण पक्ष दशमी 12:22 उपरांत एकादशी विक्रम संवत 2082

एक सम्पूर्ण दैनिक अखबार

अमृत विचार

बरेली

www.amritvichar.com

2 राज्य | 6 संस्करण

लखनऊ बरेली कानपुर मुरादाबाद अयोध्या हल्द्वानी

गुरुवार, 12 फरवरी 2026, वर्ष 7, अंक 79, पृष्ठ 14+4 मूल्य 6 रुपये

यूपी बजट 2026-27

9.12 लाख करोड़ कुल बजट

19.5% पूंजीगत व्यय

12.4% शिक्षा आवंटन

6% स्वास्थ्य आवंटन

9% कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र

23.1% ऋण-जीएसडीपी अनुपात लक्ष्य

योगी का बाहुबली बजट

नव निर्माण के 9 वर्ष

अहम बातें

₹18,290 करोड़ से सिंचाई परियोजना

2100 नए राजकीय नलकूप

₹3,04,321 करोड़ से अधिक का गन्ना भुगतान

₹14,997 करोड़ चिकित्सा शिक्षा विभाग

₹37,956 करोड़ चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाएं। (आयुष्मान टॉप-अप 500 करोड़)

₹5,000 करोड़ से औद्योगिक विस्तार

₹3,822 करोड़ एमएसएमई के लिए

₹27,103 करोड़ अवसंरचना मद में

₹22,676 करोड़ नमामि गंगे/ग्रामीण जल मिशन

200 करोड़ एमओयू रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर के लिए

65,926 करोड़ ऊर्जा क्षेत्र को

सुरेश कुमार खन्ना
वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश

बजटीय सौगात

49.86 लाख टैबलेट/स्मार्टफोन

₹400 करोड़ से मेधावी बेटियों को स्कूटी

10,00,000 युवाओं को रोजगार

₹1374 करोड़ से पुलिस भवन निर्माण

₹200 करोड़ फायर स्टेशन के लिए

₹25 करोड़ से महिला बीट कर्मियों के लिए वाहन

₹34,468 करोड़ सड़क-सेतु के लिए

₹225 करोड़ से एआई मिशन की शुरुआत

यूपी अब अनलिमिटेड पोटेंशियल के साथ बना राजस्व सरप्लस राज्य

9 साल में कोई नया टैक्स नहीं, तीन गुना बढ़ा बजट : मुख्यमंत्री

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में प्रदेश में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, फिर भी बजट का आकार तीन गुना से अधिक बढ़कर 9.12 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब "अनलिमिटेड पोटेंशियल स्टेट" के रूप में उभरा है और यह बजट उसी आत्मविश्वास का दस्तावेज है।

विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत होने के बाद बुधवार को मुख्यमंत्री योगी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह उनके नेतृत्व में सरकार का दसवां बजट है। उन्होंने बताया कि 43,565 करोड़ रुपये नई योजनाओं के लिए प्रस्तावित किए गए हैं, जबकि दो लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि पूंजीगत व्यय (कैपिटल एक्सपेंडिचर) के लिए रखी गई है। उनका कहना था कि परिसंपत्तियों के निर्माण और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास से ही रोजगार सृजन को गति मिलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 में प्रदेश में ऋण-जीएसडीपी अनुपात 30 प्रतिशत से अधिक था, जिसे घटाकर 27 प्रतिशत तक लाया गया। इस वित्तीय वर्ष में इसे 23 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक की 30 प्रतिशत सीमा के भीतर रहते हुए उत्तर प्रदेश ने वित्तीय अनुशासन का उदाहरण प्रस्तुत किया है और आज प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है।

स्टेट डेटा अथॉरिटी का होगा गठन

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में बेरोजगारी दर घटकर 2.24 प्रतिशत रह गई है। एमएसएमई, स्टार्टअप, ओडीओपी और स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के तहत एआई मिशन और डेटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना का प्रावधान किया गया है। स्टेट डेटा अथॉरिटी गठित की जाएगी, जो रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग के जरिए नीति निर्माण में मदद करेगी।

निवेश और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्रदेश में आए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी दूसरे स्थान पर पहुंचकर 'चीफ अचीवर स्टेट' बना है। डिजिटल इंटरप्रेन्योरशिप योजना को आगे बढ़ाया जाएगा और सिटी इकॉनमिक जोन विकसित किए जाएंगे।

कृषि और ग्रामीण विकास पर फोकस

योगी ने कहा कि 23 लाख डीजल ट्यूबवेल को सोलर से जोड़ने की घोषणा की गई है। एससी-एसटी, महिला और लघु सीमांत किसानों को 90 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा। दो लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त खाद्यान्न भंडारण क्षमता विकसित करने का लक्ष्य। गन्ना, दलहन-तिलहन, मत्स्य और पशुपालन क्षेत्र में विशेष प्रावधान किए गए हैं। पशुधन बीमा योजना में 85 प्रतिशत तक प्रीमियम सरकार वहन करेगी।

इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल हब

सीएम ने बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार, पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे और नए औद्योगिक क्लस्टर के लिए बजट में प्रावधान। हर जिले में स्किल डेवलपमेंट हब स्थापित किए जाएंगे। सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और हर हाथ को काम इस बजट की मूल भावना है, जो उत्तर प्रदेश को देश की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ा रहा है।

www.amritvichar.com

यूपी बजट 2026-27

बरेली, गुरुवार, 12 फरवरी 2026

यूपी बजट 2026-27 विधानसभा में पेश करने जाते मुख्यमंत्री योगी तथा वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना।

मेगा बजट

स्वच्छताकर्मियों को सीधे अकाउंट में मिलेंगे 16 से 20 हजार रुपये बजट में किया गया प्रावधान

बजट 2026-27 में पूंजीगत व्यय, शिक्षा-स्वास्थ्य और कृषि पर योगी सरकार का विशेष फोकस

नव निर्माण के नौ वर्ष की थीम पर 43,565 करोड़ की नई योजनाएं

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। अमृत विचार : विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए "नव निर्माण के नौ वर्ष" थीम के तहत 43,565 .33 करोड़ रुपये की नई योजनाओं का एलान किया। कुल बजट आकार 9,12,696 .35 करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष से लगभग 12 .9 % अधिक। सरकार का कहना है कि यह बजट विकास, वित्तीय अनुशासन और भविष्य की तैयारी का संतुलित खाका है। एलान किया कि स्वच्छताकर्मियों को सीधे अकाउंट में 16 से 20 हजार रुपये मिलेंगे, इसका बजट में प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सदन को बताया कि यह बजट राज्य की बढ़ती आर्थिक क्षमता, निवेश के अनुकूल माहौल और सुदृढ़ राजकोषीय प्रबंधन का परिणाम है। यह बजट न केवल राज्य की आर्थिक मजबूती को दर्शाता है, बल्कि दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और सतत विकास की स्पष्ट रूपरेखा भी प्रस्तुत करता है। बजट 2026-27 सरकार की उस सोच को प्रतिबिंबित करता है, जिसमें विकास, वित्तीय अनुशासन और भविष्य की तैयारी तीनों को समान महत्व दिया गया है। इस बजट में अन्नदाता किसान, युवा, महिला, छात्र-छात्राओं समेत हर वर्ग का ध्यान रखा गया है।

राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत की सीमा में

उन्होंने बताया कि 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटे की सीमा 3 प्रतिशत निर्धारित की गई है, जो वर्ष 2030-31 तक लागू रहेगी। सरकार ने स्पष्ट किया कि वह राजकोषीय अनुशासन से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा 1,18,480 .59 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो राज्य के अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 2 .98 प्रतिशत है। यह 3 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के भीतर है और वित्तीय अनुशासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। समग्र परिप्रेक्ष्य में, बजट 2026-27 में एक ओर जहां विकासोन्मुख नई योजनाओं का विस्तार है, वहीं दूसरी ओर राजस्व बचत और नियंत्रित राजकोषीय घाटे के माध्यम से वित्तीय स्थिरता बनाए रखने का स्पष्ट प्रयास किया गया है।

शिक्षकों और कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा

बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, शिक्षामित्रों, विशेष शिक्षकों, अनुदेशकों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के कार्मिकों तथा पीएम पोषण योजना की रसोइयों एवं उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के लिए 357 .84 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए 89 .25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को निशुल्क सैनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे स्वास्थ्य, स्वच्छता और स्कूल उपस्थिति में सुधार की उम्मीद है। स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रों के लिए एआई प्रमाणन शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के अंतर्गत मेधावी छात्रों के शिक्षा ऋण पर अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी के लिए 30 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं।

सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना

वाराणसी रीजन चयनित

केंद्रीय बजट 2026-27 के अंतर्गत सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना में 7 रीजन की पहचान की गई है, जिनमें वाराणसी रीजन भी शामिल है। नीति आयोग की जनवरी 2026 की रिपोर्ट में काशी-विन्ध्य क्षेत्र को 'इकोनॉमिक हब' के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है, जिसमें 34 प्राथमिकता परियोजनाओं के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल, पर्यटन, विनिर्माण, ऊर्जा और आवास क्षेत्रों में समेकित विकास किया जाएगा।

यूपी एआई मिशन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर

आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के तहत 'उत्तर प्रदेश एआई मिशन' (यूपीएआई मिशन) शुरू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत अगले तीन वर्षों में लगभग 2000 करोड़ रुपये के कार्यक्रम चरणबद्ध रूप से लागू किए जाएंगे। इसके लिए 225 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। स्टेट डाटा सेंटर 2 .0 के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके साथ नियोजन विभाग के अंतर्गत स्टेट डाटा अथॉरिटी की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए 53 विभागों में 'जन विश्वास सिद्धांत' लागू किया जाएगा। इसके लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

एमएसएमई और रोजगार को बढ़ावा

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के तहत सरदार वल्लभभाई पटेल इंप्लॉइमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन की स्थापना के लिए 575 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। एक जनपद एक व्यंजन (ओडीओसी) योजना के लिए 75 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जिससे स्थानीय खाद्य उत्पादों को पहचान और बाजार मिलेगा। इसके साथ ही, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के अंतर्गत इंटरनेशनल फिल्म सिटी परियोजना को आगे बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे प्रदेश में फिल्म उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि को प्राथमिकता

वित्त मंत्री ने बताया कि बजट में 19 .5 प्रतिशत पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है, जो आधारभूत ढांचे, औद्योगिक विकास, सड़क, ऊर्जा और शहरी-ग्रामीण अधोसंरचना को नई गति देगा। पूंजीगत निवेश से रोजगार सृजन होगा और आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी। योगी सरकार ने सामाजिक क्षेत्रों को बजट में प्रमुख स्थान दिया है। इसके अंतर्गत शिक्षा के लिए कुल बजट का 12 .4 प्रतिशत, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के लिए 6 प्रतिशत और कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं के लिए 9 प्रतिशत का आवंटन किया गया है। यह स्पष्ट संकेत है कि सरकार मानव संसाधन विकास और किसानों की आय बढ़ाने को विकास की धुरी मानकर चल रही है।

19.5
प्रतिशत पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान

अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष और एफपीओ को मजबूती

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किए जाने के मद्देनजर सरकार ने किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के लिए रिवॉल्विंग फंड योजना के अंतर्गत 150 करोड़ रुपये का कोष नाबार्ड की सहभागी संस्था 'नैब किसान' के साथ मिलकर स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसमें सरकार 75 करोड़ रुपये का अंशदान देगी। प्रत्येक पात्र एफपीओ को अधिकतम 50 लाख रुपये तक की ऋण सीमा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त, यूपी एग्रीज के अंतर्गत प्रदेश में एग्री एक्सपोर्ट हब की स्थापना के लिए 245 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना और किसानों को वैश्विक बाजार से जोड़ना है। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत 38 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। साथ ही प्रदेश में 2 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त खाद्यान्न भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी, जिसके लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, बजट में स्वच्छताकर्मियों को बड़ा तोहफा देते हुए उनके अकाउंट में सीधे 16 से 20 हजार रुपये भेजने का भी प्राविधान किया गया है। इसके लिए सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जल्द ही स्कीम का फायदा स्वच्छताकर्मियों को मिलेगा।

ऋण प्रबंधन में योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि

वित्त मंत्री ने बताया कि वर्ष 2016-17 में राज्य को 29 .3 प्रतिशत ऋण-जीएसडीपी की अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी, जिसे 2019-20 तक घटाकर 27 .9 प्रतिशत कर दिया गया। हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण यह अनुपात वर्ष 2021-22 में बढ़कर 33 .4 प्रतिशत हो गया था, लेकिन सुनियोजित राजकोषीय प्रबंधन के चलते वर्ष 2024-25 में इसे पुन: 27 प्रतिशत से नीचे लाया गया है। सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में ऋण-जीएसडीपी अनुपात को 23 .1 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य तय किया है। इतना ही नहीं, बजट के साथ प्रस्तुत मध्यकालीन राजकोषीय नीति में इसे चरणबद्ध रूप से 20 प्रतिशत से नीचे लाने का संकल्प भी दोहराया गया है। इसका उद्देश्य राज्य की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और सतत विकास सुनिश्चित करना है।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष जोर

यूपी बजट में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को उद्यमी बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके माध्यम से महिलाओं को आसान, ब्याज-मुक्त एवं चरणबद्ध पूंजी उपलब्ध कराकर 'लखपति दीदी' लक्ष्य को गति दी जाएगी। वहीं महिला उद्यमियों द्वारा उत्पादित सामान की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इस योजना के तहत रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट और बड़े बाजारों में महिलाओं द्वारा संचालित शोरूम व दुकानों की व्यवस्था की जाएगी, जिनका किराया शुरुआती तीन वर्षों तक राज्य सरकार वहन करेगी।

नई योजनाओं और सुदृढ़ वित्तीय संरचना की दिशा में बड़ा कदम

प्रदेश सरकार ने अपने बजट में 43,565 .33 करोड़ रुपये की नई योजनाओं को शामिल किया है, जिनका उद्देश्य अधोसंरचना विकास, सामाजिक क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण और उत्पादक निवेश को गति देना है। यह प्रावधान राज्य की दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि और समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राज्य की कुल प्राप्तियां 8,48,233 .18 करोड़ रुपये अनुमानित की गई हैं। इसमें से राजस्व प्राप्तियां 7,28,928 .12 करोड़ रुपये तथा पूंजीगत प्राप्तियां 1,19,305 .06 करोड़ रुपये निर्धारित हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का बड़ा हिस्सा 6,03,401 .76 करोड़ रुपये है। इसमें स्वयं का कर राजस्व 3,34,491 करोड़ रुपये तथा केंद्रीय करों में राज्य का अंश 2,68,910 .76 करोड़ रुपये शामिल है। यह वित्तीय संरचना स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि राज्य की आय में स्वयं के संसाधनों की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है, जिससे राज्य आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर और सशक्त बनता जा रहा है।

विधान सभा में यूपी बजट 2026-27 की प्रस्तुति का दृश्य।

श्रमजीवी महिला छात्रावास के लिए 80 करोड़ रुपये का बजट

मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना के अंतर्गत गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद और लखनऊ में निर्माण कार्य चल रहा है। अन्य जनपदों (अयोध्या, बरेली, अलीगढ़, मिर्जापुर, सहारनपुर एवं मुरादाबाद) में विस्तार के लिए 80 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। जनमानस के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एसजीपीजीआई में क्वाटर्नरी हेल्थ केयर सुविधा प्रारंभ करने के लिए 359 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही कैंसर मिशन के अंतर्गत हब एवं स्पोक मॉडल पर राज्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभागों तथा निजी क्षेत्र के समन्वय से कैंसर उपचार व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।

बजट में पूंजीगत निवेश को विशेष प्राथमिकता

राज्य सरकार ने कुल 9,12,696 .35 करोड़ रुपये के व्यय का प्रस्ताव रखा है, जिसमें पूंजीगत निवेश को विशेष प्राथमिकता दी गई है। इसमें से 6,64,470 .55 करोड़ रुपये राजस्व लेखा व्यय तथा 2,48,225 .81 करोड़ रुपये पूंजी लेखा व्यय के रूप में निर्धारित किए गए हैं। पूंजीगत व्यय का यह उच्च स्तर राज्य में दीर्घकालिक परिसंपत्तियों के निर्माण, आधारभूत संरचना के विस्तार और आर्थिक गतिविधियों को गति देने की स्पष्ट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वित्त मंत्री ने बताया कि समेकित निधि की प्राप्तियों में से कुल व्यय घटाने पर 64,463 .17 करोड़ रुपये का घाटा अनुमानित है। वहीं लोक लेखे से 9,500 करोड़ रुपये की शुद्ध प्राप्तियां अनुमानित की गई हैं। इन दोनों को समायोजित करने पर समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम 54,963 .17 करोड़ रुपये ऋणात्मक आंका गया है, जो वित्तीय प्रबंधन के संतुलन की आवश्यकता को इंगित करता है। वित्त मंत्री ने बताया कि प्रारंभिक शेष 96 .41 करोड़ रुपये ऋणात्मक को जोड़ने पर अंतिम शेष 55,059 .58 करोड़ रुपये ऋणात्मक अनुमानित है। एक सकारात्मक संकेत यह भी है कि राजस्व बचत 64,457 .57 करोड़ रुपये अनुमानित की गई है, जो दर्शाता है कि राज्य की नियमित आय उसके नियमित व्यय से अधिक है और राजकोषीय संतुलन को बनाए रखने में सहायता कर रही है।

डीजल से सोलर की ओर बड़ा कदम

बजट में विशेष रूप से कृषि विभाग के अंतर्गत डीजल पंप सेट को सोलर पंप में परिवर्तित करने की महत्वाकांक्षी योजना के लिए 637 .84 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे किसानों की डीजल पर निर्भरता कम होगी, लागत घटेगी और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। यह कदम कृषि क्षेत्र में हरित ऊर्जा संक्रमण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

विशेष टिप्पणी

यूपी बजट 2026-27 : चुनावी वर्ष में विकास का संतुलित संदेश

● राजेश श्रीनेत

उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले 9.12 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश कर सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह चुनावी माहौल में भी विकास के एजेंडे को केंद्र में रखना चाहती है। विधान सभा में पेश यह बजट आकार में पिछले साल से लगभग 12.2 प्रतिशत बड़ा है और पूंजीगत व्यय को 19.5 प्रतिशत तक बनाए रखते हुए दीर्घकालिक आधारभूत संरचना निर्माण पर जोर देता है। राजनीति के नजरिये से देखें तो यह केवल आय व्यय का ब्यौरा नहीं, बल्कि सरकार की प्राथमिकताओं और चुनावी रणनीति का संकेत भी है।

चुनावी वर्ष के बजट अक्सर तात्कालिक राहत और लोकलुभावन घोषणाओं के लिए जाने जाते हैं, किंतु इस बजट में राजकोषीय घाटे को तीन प्रतिशत की सीमा में रखने की प्रतिबद्धता वित्तीय अनुशासन का संदेश देती है। इससे लगता है कि सरकार विकास और स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखना चाहती है। निवेशकों के लिए यह संकेत महत्वपूर्ण है कि राज्य की वित्तीय सेहत नियंत्रित दायरे में है और बड़े बुनियादी प्रकल्पों के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में किए गए प्रावधान भी चुनावी दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। चिकित्सा शिक्षा के लिए उल्लेखनीय आवंटन, नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और स्वास्थ्य बजट में वृद्धि ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने का प्रयास है। यह उन मतदाताओं के लिए संदेश है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे में सुधार की अपेक्षा रखते हैं। युवा मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई मिशन के लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं। डिजिटल कौशल, स्टार्टअप संस्कृति और तकनीकी निवेश को बढ़ावा देना यह दर्शाता है कि सरकार नई पीढ़ी को अवसरों से जोड़ना चाहती है। टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण जैसी योजनाएं राजनीतिक दृष्टि से भी संवाद का माध्यम बनती हैं। हालांकि, युवाओं की अपेक्षाएं अब केवल उपकरणों से आगे बढ़कर गुणवत्तापूर्ण और स्थायी रोजगार के अवसरों पर केंद्रित हैं। इस दिशा में घोषित निवेश और संभावित रोजगार के आंकड़ों का धरातल पर क्रियान्वयन ही वास्तविक कसौटी होगा।

औद्योगिक विकास के क्षेत्र में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एमएसएमई प्रोत्साहन और निवेश नीति के लिए प्रावधान यह संकेत देते हैं कि सरकार राज्य को विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करना चाहती है। बड़े निवेश के समझौते और संभावित रोजगार सृजन के अनुमान चुनावी विमर्श में विकास आधारित राजनीति को बल देते हैं। फिर भी यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन परियोजनाओं का लाभ स्थानीय युवाओं और छोटे उद्यमियों तक कितनी तेजी से पहुंचता है। कृषि क्षेत्र में सिंचाई विस्तार, फसल सघनता में वृद्धि और उत्पादन में बढ़ोतरी के आंकड़े ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती को रेखांकित करते हैं। ऊर्जा क्षेत्र में उत्पादन क्षमता में वृद्धि और सौर परियोजनाओं का विस्तार राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में संकेत है।

हालांकि आलोचनात्मक दृष्टि से यह भी कहा जा सकता है कि चुनावी वर्ष में घोषित योजनाओं के क्रियान्वयन की गति और पारदर्शिता पर विशेष ध्यान देना होगा। बड़े बजट का वास्तविक प्रभाव तभी दिखाई देगा जब योजनाएं समयबद्ध ढंग से पूरी हों और लाभ लक्षित वर्गों तक पहुंचे। समग्र रूप से देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट विकास, निवेश और वित्तीय अनुशासन के संतुलन का प्रयास है। इसमें चुनावी संदर्भ की झलक अवश्य है, परंतु अत्यधिक लोकलुभावन रुख से बचते हुए दीर्घकालिक दृष्टि को सामने रखा गया है। मतदाता इस बात का मूल्यांकन करेंगे कि घोषित योजनाएं जमीन पर कितनी प्रभावी सिद्ध होती हैं। फिलहाल यह बजट विकास और विश्वास के संदेश के साथ चुनावी वर्ष की राजनीतिक पृष्ठभूमि को आकार देता हुआ दिखाई देता है।

एपस्टीन से मिला मगर उसके अपराधों से लेना-देना नहीं : हरदीप सिंह पुरी-7

भारत-अमेरिका समझौते में संवेदनशील क्षेत्र पूरी तरह संरक्षित : वाणिज्य सचिव-10

चीन ने कहा- आपसी मतभेदों को रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखे भारत-11

दक्षिण अफ्रीका की अफगानिस्तान पर दूसरे सुपर ओवर में रोमांचक जीत-12

आज का मौसम
24.0° अधिकतम तापमान
11.0° न्यूनतम तापमान
सूर्योदय 06.54
सूर्यास्त 05.59

एक सम्पूर्ण दैनिक अखबार

अमृत विचार

बरेली

www.amritvichar.com

2 राज्य | 6 संस्करण
लखनऊ बरेली कानपुर
मुरादाबाद अयोध्या हल्द्वानी

फाल्गुन कृष्ण पक्ष दशमी 12:22 उपरांत एकादशी विक्रम संवत 2082

गुरुवार, 12 फरवरी 2026, वर्ष 7, अंक 79, पृष्ठ 14+4 ■ मूल्य 6 रुपये

न्यूज ब्रीफ

उज्ज्वल निकम को नामित किए जाने पर याचिका दायर की

नई दिल्ली। कई हत्याओं के आरोपी गैंगस्टर विजय पलांडे ने बुधवार को अपने मामले में वकील उज्ज्वल निकम को विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) नामित किए जाने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की। अपनी याचिका में पलांडे ने दलील दी कि राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित होने के कारण निकम इस मामले में एसपीपी नहीं रह सकते, क्योंकि यह लाभ के पद पर आसीन होने के बराबर होगा। निकम ने 2024 के लोकसभा चुनाव में मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था।

भारतीय सेना से मिजोरम की साझेदारी, स्थानीय स्तर पर बढ़ेगी भर्ती

आइजोल। मिजोरम युवा आयोग (एमवाईसी) ने भारतीय सशस्त्र बलों में राज्य के युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से बुधवार को सेना भर्ती कार्यालय (एआरओ) के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की। एआरओ मुख्यालय में 'यंग मिजो एसोसिएशन' के अध्यक्ष मालसॉमजुआला राल्ते और एआरओ निदेशक कर्नल प्रकाश कुमार सिंह के बीच हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद इस सहयोग को अंतिम रूप दिया गया।

सलमान के बहनोई एवं अभिनेता आयुष को बिश्नोई गैंग की धमकी

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता सलमान के बहनोई आयुष शर्मा को धमकी भरा ईमेल मिला है। यह घटना अभिनेता रणवीर सिंह को व्हाट्सएप के माध्यम से मिली धमकी के एक दिन बाद हुई है। पुलिस ने कोई अन्य जानकारी दिए बिना बताया कि शर्मा को ईमेल भेजने वाले ने दावा किया कि वह लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सदस्य है।

योगी ने 10वीं बार बजट पेश कर ऐसे इकलौते मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड अपने नाम किया

महाबजट @9.12 लाख करोड़

- विकास और वित्तीय अनुशासन का संतुलन निवेश रोजगार और कल्याण पर सरकार का फोकस
- उच्च शिक्षा की मेधावी बेटियों को मिलेगी स्कूटी सिंचाई, बीमा एवं मुफ्त बिजली पर भी जोर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार : लोकलुभावन घोषणाओं के महाबजट के साथ बुधवार को मुख्यमंत्री योगी ने लगातार 10वीं बार बजट पेश कर इकलौते मुख्यमंत्री होने का रिकार्ड भी अपने नाम कर लिए। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट का कुल आकार 9,12,696.35 करोड़ रुपये रखा गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12.9 प्रतिशत अधिक है। इसमें विकास और वित्तीय अनुशासन का संतुलन दिखा। 10 लाख युवाओं को रोजगार, लड़कियों की शादी के लिए एक लाख रुपये समेत मेधावी बेटियों को स्कूटी के एलान से युवा मतदाताओं और सिंचाई, बीमा व मुफ्त बिजली से किसानों को साधने की कोशिश हुई है।

योगी सरकार ने बुधवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अब तक का सबसे बड़ा 912696 करोड़ का बजट पेश किया। यह बजट पिछले वर्ष की तुलना में करीब 13 प्रतिशत अधिक है। पूंजीगत व्यय 19.5 प्रतिशत रखा गया है, जिससे साफ है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और दीर्घकालिक विकास पर बड़ा दांव खेल रही है। राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत की सीमा में रखने और ऋण-जीएसडीपी अनुपात 23.1 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य वित्तीय अनुशासन का संकेत देता है। शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, कौशल विकास और महिला सशक्तीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश भाषण में सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि प्रदेश में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, लड़कियों की शादी के लिए एक लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा भी की गई है। बजट में नौकरीपेशा, कामगार, व्यापारी-उद्यमी समेत सबके लिए राहत और तरक्की का पिटारा है। यह बजट चुनावी वर्ष से पहले सरकार का विकास और रोजगार केंद्रित रोडमैप माना जा रहा है, जिसमें निवेश और सामाजिक योजनाओं के संतुलन के जरिए व्यापक मतदाता वर्ग को साधने की कोशिश दिखती है। फोकस सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंचाई, मेडिकल शिक्षा, एमएसएमई, ऊर्जा, डिजिटल एवं एआई मिशन है। इसका विकसित यूपी @-2047 से तालमेल है।

सामाजिक कल्याण पर सरकार का विशेष ध्यान

लखनऊ : वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में योगी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए 14,953 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। बजट में अल्पसंख्यक कल्याण योजना के लिए 2,058 करोड़, वृद्धावस्था व किसान पेंशन योजनाओं के लिए 8,950 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्तमान में 67 .50 लाख लाभार्थियों को प्रतिमाह एक हजार रुपये पेंशन दी जा रही है। दिव्यांग पेंशन योजना के तहत लगभग 11 लाख लाभार्थियों को 1,000 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। इसके लिए 1,470 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

- 14,953 करोड़ रुपये का प्रावधान, पेंशन से छात्रवृत्ति तक व्यापक कवरेज

छात्रवृत्ति और छात्रावास योजनाएं

- अनुसूचित जाति पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति : 977 करोड़ रुपये
- सामान्य वर्ग छात्रवृत्ति : 950 करोड़ रुपये
- पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति (पूर्वदशम/दशमोत्तर) : 3,060 .50 करोड़ रुपये
- अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति : 391 करोड़ रुपये
- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत 21 जिलों में 500 करोड़ रुपये
- मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना के तहत अयोध्या, बरेली, अलीगढ़, मिर्जापुर, सहारनपुर और मुरादाबाद में छात्रावास निर्माण के लिए 80 करोड़ रुपये

महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र

बजट भाषण में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार ने युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए मिशन मोड में कौशल संवर्धन अभियान चलाने की घोषणा की है। पीपीपी मोड में कौशल संवर्धन और जॉब प्लेसमेंट केंद्र विभिन्न जनपदों में स्थापित किए जाएंगे। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए अलग प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएंगे। कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों की क्षमता बढ़ाई जाएगी और नए केंद्र खोले जाएंगे। निजी क्षेत्र की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।

बनाए जाएंगे एग्री-एक्सपोर्ट हब

बजट में डिजिटल इंटरप्रेन्योरशिप योजना लागू करने की घोषणा की गई है। खन्ना कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अगले चरण में जनविश्वास सिद्धांत के आधार पर पंजीकरण और लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को और सरल बनाया जाएगा। विश्व बैंक सहायतित यूपी एग्रीज परियोजना के अंतर्गत एग्री-एक्सपोर्ट हब स्थापित किए जाएंगे। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग 29वें स्थान से सुधरकर 18वें स्थान पर पहुंच चुकी है।

विवाह योजना में बढ़ा 50 हजार

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अनुदान राशि 51,000 रुपये से बढ़ाकर 1.01 लाख रुपये कर दी गई है। योजना के लिए 750 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति की पुत्रियों के विवाह हेतु 100 करोड़ रुपये और सामान्य वर्ग की निर्धन पुत्रियों के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

पिछड़ा वर्ग और जनजाति विकास

पिछड़ा वर्ग कल्याण योजनाओं के लिए 3,402 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। दिव्यांगजन कल्याण के लिए 2,140 करोड़, ई-ट्राईसाइकिल योजना को 60 करोड़ तथा तीन से सात आयुवर्ग के बच्चों हेतु बचपन डे-केयर सेंटर के लिए पांच करोड़ रुपये दिए गए हैं।

रामपुर : आतंकी हमला मामले में सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली उप्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई, जिसमें 2007 के रामपुर सीआरपीएफ शिविर आतंकी हमले के मामले में चार आरोपियों को दी गई मौत की सजा और एक अन्य को दी गई आजीवन कारावास की सजा निरस्त कर दी गई थी।

रामपुर स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के शिविर पर 31 दिसंबर 2007 की रात को हुए हमले में सीआरपीएफ के आठ जवान मारे गए थे और पांच घायल हो गए थे। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने राज्य सरकार की याचिका पर आरोपियों को नोटिस जारी किये और मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की। पांचों आरोपियों की ओर से अधिवक्ता एम एस खान पेश हुए। राज्य सरकार ने

- उत्तर प्रदेश सरकार की हाईकोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई को हुई सहमत
- 2007 के आतंकी हमले में चार आरोपियों को दी गई मौत की सजा कर दी गई थी निरस्त

पिछले साल 29 अक्टूबर को उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने निचली कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया था, जिसमें इस मामले में चार लोगों को मृत्युदंड और एक अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएगी सरकार

नई दिल्ली, एजेंसी

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सदन में एक मंत्री के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाए हैं इसलिए सरकार ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। रीजीजू ने बुधवार को आरोप लगाया कि राहुल गांधी का भाषण झूठ से भरा था और सत्तारूढ़ गठबंधन लोस में नेता प्रतिपक्ष द्वारा किए झूठे दावों को सदन की कार्यवाही से हटाए जाने का अनुरोध करेगा।

केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान राहुल के भाषण के तुरंत बाद, रीजीजू ने कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन के सदस्य आसन को एक नोटिस देंगे, जिसमें नेता प्रतिपक्ष द्वारा बोले गए किसी भी कथन के प्रमाणीकरण की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने जो भी झूठ बोला है, हम उसे रिकॉर्ड से हटाए जाने की मांग करेंगे।

- राहुल गांधी के झूठे बयानों को सदन की कार्यवाही से हटाने का अनुरोध करेंगे : रीजीजू

हालांकि, राहुल गांधी ने अपने बयानों को प्रमाणित करने का वादा किया है, लेकिन मंत्री ने कहा, मुझे पता है कि वह उन्हें प्रमाणित नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने सदन में झूठ बोला है। रीजीजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता अक्सर जानबूझकर झूठ बोलते हैं और फिर संबंधित मंत्री का जवाब सुनने के बजाय सदन छोड़कर चले जाते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के पास लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पद के योग्य गंभीर स्वभाव वाला कोई व्यक्ति नहीं है। कहा, हमारी पार्टी का रुख यह है कि हम राहुल के झूठ का जवाब सदन के बाहर देंगे, लेकिन सदन के अंदर नोटिस जारी किया जाएगा।

विपक्ष के नोटिस में कमियां पाई गईं

नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने संबंधी विपक्ष के नोटिस में कमियां पाई गईं थी, जिसके बाद खुद बिरला ने इसमें सुधार करवा के कार्यवाही करने का निर्देश अपने सचिवालय को दिया। लोकसभा सचिवालय सूत्रों ने बताया कि नोटिस में कुछ घटनाक्रमों का उल्लेख करते हुए चार जगहों पर वर्ष 2026 के बजाय 2025 लिखा गया था और इस आधार पर नोटिस को खारिज भी किया जा सकता था।

नरवणे की किताब मामले की जांच शुरू प्रकाशक को नोटिस

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक के कथित प्रसार की जांच में आपराधिक साजिश के आरोप जोड़े हैं और इसके प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। दिल्ली पुलिस का विशेष प्रकोष्ठ मामले की जांच कर रहा है।

यह मामला पुस्तक के प्रकाशन से पहले सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुस्तक के पीडीएफ संस्करण के अनधिकृत प्रसार से संबंधित है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जांच अब यह पता लगाने पर केंद्रित है कि क्या पांडुलिपि के लीक और उसके बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसार के पीछे कोई आपराधिक साजिश थी। पेंगुइन ने एक बयान में कहा, पुस्तक का प्रकाशन नहीं हुआ है। कोई भी प्रति - मुद्रित या डिजिटल रूप में - प्रकाशित, वितरित व अन्य तरीके से जनता को उपलब्ध नहीं कराई गई है।

पत्नी के सामने अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या

कार्यालय संवाददाता, रामपुर

अमृत विचार : जिला पंचायत के हेड क्लर्क ने लाइसेंसी पिस्टल से बुधवार को एक अधिवक्ता को उसकी पत्नी के सामने ही जिला पंचायत परिसर में गोली मार दी। घायल अधिवक्ता ने अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। पत्नी के वेतन कटौती को लेकर अधिवक्ता का बाबू से विवाद हुआ था।

नगर कोतवाली नालापार निवासी वकील फारुख अहमद खान (45) की पत्नी गौसिया जिला पंचायत कार्यालय में क्लर्क हैं। यहीं पर थाना पटवाई क्षेत्र के मिलक तहव्वुर गांव का रहने वाला असगर अली हेड क्लर्क है। बताया जाता है कि अधिवक्ता की पत्नी का कार्यालय में लेट आने के कारण वेतन काट लिया गया था। इसी संबंध में बुधवार को गौसिया के साथ उनके पति अधिवक्ता फारुख अहमद जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे। उन्होंने हेड क्लर्क असगर अली से इस विषय पर बात की। इसी बीच दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। अचानक हेड क्लर्क ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से अधिवक्ता पर तीन फायर झोंक दिए।

फारुख अहमद

- जिला पंचायत कार्यालय में हेड क्लर्क ने कहासुनी के बाद मारी गोली

गोली लगते ही अधिवक्ता फारुख अहमद तड़पकर गिर गए। गौसिया शोर मचाते हुए बाहर की ओर भागी। लोग आनन फानन में अधिवक्ता को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तमाम वकील जिला अस्पताल पहुंच गए और हंगामा करने लगे। पुलिस अधीक्षक विद्या सागर मिश्र ने मौका मुआयना कर कार्रवाई के निर्देश दिए।

कनाडा में स्कूल में गोलीबारी, 10 की मौत

वैंकूवर, एजेंसी

कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में टंबलर रिज सेकेंडरी स्कूल और एक मकान में हुई गोलीबारी की घटना में हमलावर सहित 10 लोगों की मौत हो गई। कनाडाई प्राधिकारियों ने बताया कि 25 से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से दो की हालत गंभीर है। लगभग 2,400 लोगों की आबादी वाला टंबलर रिज शहर वैंकूवर से 1,000 किलोमीटर उत्तर में अल्बर्टा की सीमा के पास स्थित है।

प्रांतीय सरकार की वेबसाइट के अनुसार, टंबलर रिज सेकेंडरी स्कूल में सातवीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के 175 छात्र पढ़ते हैं। अधीक्षक केन फ्लॉयड ने बताया कि जांचकर्ताओं ने हमलावर की पहचान कर ली है,

- ब्रिटिश कोलंबिया में वारदात, 25 से अधिक लोग घायल, दो गंभीर

लेकिन उसका नाम जारी नहीं किया। न ही यह स्पष्ट है कि आरोपी ने इस घटना को अंजाम क्यों दिया। फ्लॉयड ने कहा, हम अभी इस बात को समझने की स्थिति में नहीं हैं कि इस त्रासदी का कारण क्या था। उन्होंने ने कहा कि पुलिस अभी यह जांच कर रही है कि पीड़ितों व आरोपी के बीच क्या संबंध थे। तलाशी के दौरान अधिकारियों को कई पीड़ित मिले।

संदिग्ध हमलावर भी मृत पाया गया

संदिग्ध हमलावर भी मृत पाया गया, जिसके शरीर पर खुद को चोट पहुंचाने के निशान दिखायी दे रहे थे। बयान में कहा गया है, संदिग्ध को छोड़कर छह अन्य व्यक्तियों को स्कूल के भीतर मृत पाया गया। गंभीर रूप से घायल दो लोगों को हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाया गया है। तीसरे व्यक्ति की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गयी। पीस रिवर साउथ स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने मंगलवार को कहा कि सेकेंडरी स्कूल और टंबलर रिज एलिमेंटरी स्कूल दोनों में किसी को अंदर जाने या बाहर निकलने की अनुमति नहीं है।

निर्देश

गृह मंत्रालय ने पहली बार राष्ट्रगीत गायन को लेकर प्रोटोकॉल तय किए

राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत के सभी छह छंद गाना जरूरी

नई दिल्ली, एजेंसी

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि जब भी राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' और राष्ट्रगान 'जन गण मन' एक साथ गाए या बजाए जाएं तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे गए राष्ट्रगीत के सभी छह छंद पहले गाए जाएं। आदेश में मंत्रालय ने पहली बार राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' के गायन को लेकर प्रोटोकॉल तय किए हैं।

जिसके तहत राष्ट्रपति के आगमन, तिरंगा फहराए जाने और राज्यपालों के भाषण जैसे आधिकारिक कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत के सभी छह छंद (कुल अवधि तीन मिनट 10 सेकंड) गाए जाएंगे। यह आदेश 28 जनवरी को जारी किया गया। आदेश में कहा गया, जब भी राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाए या बजाए जाएं, तो राष्ट्रगीत पहले गाया या बजाया जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जहां राष्ट्रगीत गाया जाएगा, वहां उपस्थित सभी लोगों को सावधान की मुद्रा में खड़ा होना होगा। इसमें कहा गया, जब भी राष्ट्रगीत का आधिकारिक संस्करण गाया या बजाया जाए, तो वहां मौजूद सभी लोगों को सावधान मुद्रा में खड़ा होना होगा लेकिन अगर किसी समाचार रील या वृत्तचित्र के दौरान राष्ट्रगीत फिल्म के हिस्से के रूप में बजाया जाए, तो दर्शकों से खड़े होने की अपेक्षा नहीं है क्योंकि इससे फिल्म दिखाने में रुकावट आएगी और सम्मान के बजाय अव्यवस्था एवं भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। मंत्रालय ने कहा कि विद्यालयों में दिन की शुरुआत राष्ट्रगीत के सामूहिक गायन से की जानी चाहिए। केंद्र सरकार 'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित कर रही है।

- जब भी राष्ट्रगीत व राष्ट्रगान गाया या बजाया जाएं तो राष्ट्रगीत पहले हो

छात्रों में राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान की भावना विकसित करने के निर्देश

आदेश के अनुसार, राष्ट्रध्वज फहराने, सांस्कृतिक एवं औपचारिक कार्यक्रमों (परेड को छोड़कर), तथा किसी सरकारी या सार्वजनिक समारोह में राष्ट्रपति के आगमन जैसे अवसरों पर राष्ट्रगीत का आधिकारिक संस्करण सामूहिक गायन के साथ गाया या बजाया जाएगा। राष्ट्रगीत ऐसे अवसरों पर भी गाया जा सकता है, जो भले ही पूरी तरह औपचारिक समारोह न हों, लेकिन मंत्रियों आदि की मौजूदगी के कारण महत्वपूर्ण हों। ऐसे मौकों पर (वाद्य यंत्रों के साथ या बिना) राष्ट्रगीत का सामूहिक गायन वांछनीय है। यह भी कहा कि उन सभी अवसरों की पूरी सूची देना संभव नहीं है, जहां राष्ट्रगीत का गायन किया जा सकता है लेकिन यदि मातृभूमि को सम्मान देने और उचित मर्यादा बनाए रखने के साथ राष्ट्रगीत गाया जाता है, तो इस पर कोई आपत्ति नहीं है। आदेश में विद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे छात्रों में राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान की भावना विकसित करें।

यूपी बजट 2026-27

दुग्ध विकास को बढ़ावा

- मथुरा में 30 हजार लीटर क्षमता की प्रस्तावित परियोजना को संशोधित कर 1 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का नया डेयरी प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 23 करोड़ का प्रावधान है। 220 नई दुग्ध समितियों के गठन और 450 के पुनर्गठन के लिए 107 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

पशुधन संरक्षण

- प्रदेश के 7,497 गो-आश्रय स्थलों में 12.38 लाख गोवंश संरक्षित हैं। छुट्टा गोवंश के रखरखाव के लिए 2,000 करोड़ तथा वृहद गो-संरक्षण केंद्रों के लिए 100 करोड़ प्रस्तावित हैं। पशु रोग नियंत्रण हेतु 253 करोड़ और पशु चिकित्सालय सुदृढ़ीकरण के लिए 155 करोड़ रखे गए हैं।

मत्स्य क्षेत्र में विस्तार

- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 195 करोड़ (पुरुष घटक) और 115 करोड़ (महिला घटक) का प्रावधान है। एकीकृत एक्वा पार्क हेतु 190 करोड़ तथा अत्याधुनिक मत्स्य थोक बाजार व प्रसंस्करण केंद्र के लिए 100 करोड़ प्रस्तावित हैं।

खाद्य एवं रसद

- खाद्य एवं रसद विभाग की योजनाओं के लिए 20,124 करोड़ का प्रावधान है। अन्नपूर्ति योजना हेतु 15,480 करोड़, नि:शुल्क एलपीजी रिफिलिंग योजना के लिए 1,500 करोड़ और अन्नपूर्णा भवन निर्माण के लिए 500 करोड़ रखे गए हैं।

उद्यान व खाद्य प्रसंस्करण

- उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए 2,832 करोड़ का प्रावधान है। राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन के लिए 715 करोड़, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना हेतु 478 करोड़ और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2022 के क्रियान्वयन के लिए 300 करोड़ रखे गए हैं।

प्रमुख प्रावधान

2,400 करोड़ रुपये निजी नलकूपों को निर्बाध बिजली के लिए

2,832 करोड़ रुपये उद्यान व खाद्य प्रसंस्करण के लिए

100 करोड़ रुपये मत्स्य थोक बाजार/एक्वा पार्क/प्रसंस्करण के लिए

2,000 छुट्टा गोवंश रखरखाव के लिए || **20,124** करोड़ रुपये खाद्य एवं रसद योजनाओं के लिए

किसानों पर मेहरबानी

637.84 करोड़ रुपये कृषकों के डीजल पंप सेट को सोलर पम्प में परिवर्तित करने के लिए

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार : वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए कहा कि कृषि, मत्स्य, उद्यान, दुग्ध विकास, खाद्य-रसद पर खास फोकस है।

बजट में कृषि योजनाओं के लिए 10,888 करोड़ रुपय का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 20% अधिक है। सरकार ने 2026-27 में 753.55 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न और 48.18 लाख मीट्रिक टन तिलहन उत्पादन का लक्ष्य रखा है। कृषकों के डीजल पंप सेट को सोलर पम्प में परिवर्तित करने के लिए 637.84 करोड़ रुपये खर्च करने का एलान किया गया।

डीजल पंप से सोलर की ओर

- किसानों के डीजल पंप सेट को सोलर पंप में बदलने के लिए 637.84 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना के लिए 298 करोड़ रखे गए हैं। निजी नलकूपों को निर्बाध बिजली आपूर्ति हेतु 2,400 करोड़ प्रस्तावित हैं।

एग्री-एक्सपोर्ट और यूपी एग्रीज

- यूपी एग्रीज परियोजना के तहत एग्री-एक्सपोर्ट हब की स्थापना के लिए 245 करोड़ तथा किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के लिए 75 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड प्रस्तावित है। एक्वा कल्चर अवसंरचना के अंतर्गत विश्वस्तरीय हैचरी व प्रशिक्षण केंद्र के लिए 155 करोड़ की बाह्य सहायता परियोजना भी शामिल है।

स्मार्ट तकनीक पुलिसिंग को मिली और ताकत

सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में कानून-व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, तकनीक-संपन्न और जवाबदेह बनाने के लिए 44 हजार करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रस्तुत इस बजट का उद्देश्य साइबर अपराध नियंत्रण, आपदा प्रबंधन, महिला एवं बाल सुरक्षा, अग्निशमन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और वैज्ञानिक जांच प्रणाली को मजबूत करना है।

44 हजार करोड़ से साइबर अपराध नियंत्रण, डिजिटल जांच व महिला सुरक्षा

मिशन शक्ति के तहत महिला सुरक्षा को बल

- मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला बीट कर्मियों के लिए वाहनों की खरीद हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इससे महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में पुलिस की सक्रियता और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ेगी।

साइबर थानों का आधुनिकीकरण

- साइबर थानों में संसाधन वृद्धि एवं वाहनों की खरीद के लिए 1215.60 लाख रुपये और साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र की स्थापना हेतु 95.16 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इससे डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण, त्वरित जांच और साइबर हमलों पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा।

अग्निशमन और आपदा प्रबंधन को मजबूती

- अग्निशमन वाहनों एवं उपकरणों की खरीद हेतु 190 करोड़ रुपये खर्च होंगे। आपदा प्रबंधन के तहत राज्य आपदा राहत बल (एसडीआरएफ) की तीन नई टीमों को सक्रिय किया जाएगा। एसडीआरएफ उपकरणों की खरीद हेतु 15 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

यूपी-112 को मिलेंगे नए वाहन

- त्वरित पुलिस प्रतिक्रिया प्रणाली यूपी-112 को और मजबूत किया जाएगा। नए वाहनों की खरीद हेतु 27.51 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।

फॉरेंसिक लैब और वैज्ञानिक जांच को बढ़ावा

- अपराधों की वैज्ञानिक जांच को तेज करने के लिए तीन नई विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं को क्रियाशील किया जाएगा। न उपकरणों केलिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

महिलाओं को सस्ते दर पर ऋण, आवास के साथ सामाजिक सुरक्षा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार: वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में महिला सशक्तिकरण को विशेष प्राथमिकता दी गई है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग के बजट में 11 प्रतिशत वृद्धि करते हुए कुल 18,620 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। सरकार का लक्ष्य महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और वित्तीय भागीदारी को नई ऊंचाई देना है।

सरकार ने महिलाओं को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की है, ताकि वे स्वरोजगार और उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भर बन सकें। स्वयं सहायता समूहों और महिला उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी। बजट में सफाई कर्मियों और निर्माण श्रमिकों को आवास उपलब्ध कराने की पहल भी शामिल है। इससे शहरी क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिक महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास सुविधा मिलेगी। बजट 2026-27 में महिला एवं बाल कल्याण योजनाओं का विस्तार करते हुए सरकार ने सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और पोषण सुरक्षा के दायरे को व्यापक बनाने की स्पष्ट रणनीति पेश की है। यह बजट महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और बालिकाओं के सुरक्षित भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ा

- निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए 3,500 करोड़ का प्रावधान।
- 2016-17 में लाभार्थी : 17.32 लाख
- 2025-26 में लाभार्थी : 38.58 लाख से अधिक
- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए 400 करोड़ की व्यवस्था।
- कामकाजी महिलाओं के छात्रावास निर्माण हेतु 100 करोड़।
- मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास निर्माण योजना के लिए 35 करोड़।

बच्चों के संरक्षण और पोषण पर जोर

- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए 252 करोड़।
- मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के तहत भवन निर्माण हेतु 80 करोड़।
- अनुपूरक पुष्टाहार कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 1.57 करोड़ लाभार्थियों को पोषण सहायता।

तकनीकी महाशक्ति की दिशा में कदम

वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में उत्तर प्रदेश सरकार ने आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को विकास की नई धुरी बनाया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस सेक्टर के लिए 2,059 करोड़ का प्रावधान किया है, जो वर्ष 2025-26 की तुलना में 76 प्रतिशत अधिक है। बजट में एआई मिशन के लिए 225 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

30,000 करोड़ निवेश का लक्ष्य डाटा सेंटर में

30,000 करोड़ के अनुमानित निवेश से 8 डाटा सेंटर पार्क स्थापित करने और 900 मेगावाट क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 8 परियोजनाओं को लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किए गए हैं, जिनमें 6 डाटा सेंटर पार्क और 2 डाटा सेंटर इकाइयां शामिल हैं। इनसे लगभग 21,342 करोड़ का निवेश और 644 मेगावाट क्षमता अर्जित की जा चुकी है।

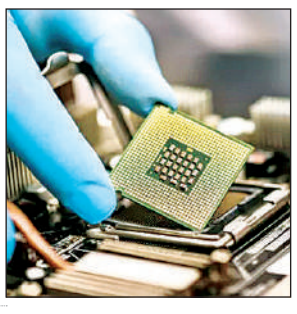

साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता

साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र की स्थापना को 95.16 करोड़ का दिए गए हैं। पहले से संचालित 'एआई प्रज्ञा' कार्यक्रम के तहत माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इंटेल, आईबीएम और वन एम वन बी जैसी कंपनियों के सहयोग से किसानों, स्वयं सहायता समूहों, विद्यार्थियों, चिकित्सकों और सरकारी कर्मियो को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में अग्रणी

उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण केंद्र बन चुका है। देश के कुल मोबाइल उत्पादन का 65 प्रतिशत उत्पादन प्रदेश में होता है। भारत की 55 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इकाइयां भी यहीं स्थित हैं। प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात बढ़कर 44,744 करोड़ तक पहुंच गया है।

बढ़ेगी शिक्षा की गुणवत्ता

अमृत विचार, लखनऊ : वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में योगी सरकार ने शिक्षा को विकास की केंद्रीय धुरी बनाते हुए व्यापक प्रावधान किए हैं।

बेसिक से लेकर उच्च, प्राविधिक और कौशल विकास तक हर स्तर पर उल्लेखनीय बढ़ोतरी कर प्रदेश को ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ाने का रोडमैप प्रस्तुत किया गया है। शिक्षा, कौशल और तकनीकी प्रशिक्षण पर अभूतपूर्व निवेश कर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि नया उत्तर प्रदेश ज्ञान, नवाचार और रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण के मजबूत आधार पर ही निर्मित होगा।

- बजट 2026-27 में ज्ञान और कौशल पर सबसे बड़ा निवेश

पढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे

बेसिक शिक्षा

- बेसिक शिक्षा के लिए 77,622 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कक्षा 1-8 के विद्यार्थियों को नि:शुल्क यूनिफॉर्म, बैग, जूते, मोजे व स्टेशनरी हेतु 650 करोड़।
- 75 जनपदों में 2-2 मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय। आवासीय बालिका विद्यालय विस्तार के लिए 580 करोड़।
- कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा : 358 करोड़। स्मार्ट स्कूल योजना : 300 करोड़।
- सहायता प्राप्त विद्यालयों के अनुरक्षण हेतु 300 करोड़।

उच्च शिक्षा

- उच्च शिक्षा के लिए 6,591 करोड़ (7% वृद्धि)।
- रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना : 400 करोड़
- मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन : 40 करोड़

नए विश्वविद्यालयों हेतु आवंटन

- मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय, मिर्जापुर- 50 करोड़
- गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद- 50 करोड़
- मां पटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर- 50 करोड़
- स्वामी शुकदेवानन्द विश्वविद्यालय शाहजहांपुर- 21 करोड़
- काशी नरेश विवि भदोही - 21 करोड़
- मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण : 14.5 करोड़।
- एआई प्रमाणन शुल्क प्रतिपूर्ति :10 करोड़
- मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना : 30 करोड़

माध्यमिक शिक्षा

- माध्यमिक शिक्षा के लिए 22,167 करोड़ (15% वृद्धि)।
- राजकीय विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु 520 करोड़।
- सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए 10 करोड़।
- संस्कृत पाठशालाओं की छात्रवृत्ति : 20 करोड़।
- ड्रीम स्किल लैब क्लस्टर : 150 करोड़।
- शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा : 89.25 करोड़।
- छात्राओं हेतु नि:शुल्क सेनेटरी नैपकिन : 300 करोड़।
- गोरखपुर में दूसरे सैनिक स्कूल का संचालन आरंभ।

व्यावसायिक शिक्षा

- व्यावसायिक शिक्षा बजट में 88% वृद्धि, कुल 3,349 करोड़। शिक्षा बजट में 72% वृद्धि, कुल 2,365 करोड़।
- 286 राजकीय आईटीआई 1.90 लाख सीटें।
- 2,963 निजी आईटीआई 4.58 लाख सीटें।
- 47 आईटीआई में महिला शाखाएं 12 महिला आईटीआई स्वतंत्र।
- टाटा टेक्नोलॉजीज के सहयोग से 149 आईटीआई उन्नत 62 और प्रगति पर।
- कौशल विकास मिशन प्रशिक्षण व्यय : 1,000 करोड़।
- दस्तकार प्रशिक्षण योजना : 836 करोड़
- प्रोजेक्ट प्रवीण : 500 करोड़।
- मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रशिक्षण : 20 करोड़

प्राविधिक शिक्षा

- प्राविधिक शिक्षा बजट में 72% वृद्धि, कुल 2,365 करोड़।
- 195 डिप्लोमा संस्थान संचालित
- 23 नए पॉलिटेक्निक निर्माणाधीन।
- उत्कृष्टता केंद्र व उन्नयन : 714 करोड़।
- स्मार्ट कक्षाएं (251 स्थापित, 143 प्रक्रियाधीन)।
- अवसंरचना विकास : 254 करोड़।

नए पॉलिटेक्निक : 50 करोड़।

हरियाली पर जोर

सामाजिक वानिकी व रोपण

- सामाजिक वानिकी योजना : 800 करोड़
- पौधशाला प्रबंधन योजना : 220 करोड़
- राज्य प्रतिकारात्मक वन रोपण योजना : 189 करोड़

रानीपुर बांध फाउंडेशन

- रानीपुर बांध से जुड़े रानीपुर बांध फाउंडेशन, चित्रकूट के कॉर्पस फंड गठन के लिए 50 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

स्वच्छ वायु

- उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट (2025-26 से 2030-31) : 194 करोड़
- यह विश्व बैंक सहायतित बहु-क्षेत्रीय योजना है।

अपशिष्ट निस्तारण

- सामूहिक जैव-चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण सुविधा
- ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग एवं उपचार सुविधा की स्थापना की कार्यवाही

प्रतिक्रियाएं | विशेषज्ञ बोले- डिजिटल कक्षाएं, आवासीय व्यवस्था और कैशलेस चिकित्सा से प्राथमिक शिक्षा का होगा कायाकल्प

ज्ञान, विज्ञान और नवाचार को मिलेगी उड़ान

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

अमृत विचार: उत्तर प्रदेश का बजट 2026-27 में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के बजट में पिछले वर्षो की तुलना में बढोत्तरी की गई है, जिसका शिक्षाविदों और अर्थशास्त्र के जानकारों ने स्वागत किया है। बजट में प्रदेश की बेसिक शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर विशेष फोकस किया गया है।

बजट प्रस्तावों से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि सरकार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा के ढांचे में व्यापक बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी के साथ प्राविधिक और औद्योगिक शिक्षा में सरकार के नए प्रयोग, नवाचार और इंडिया एआई मिशन युवाओं को समर्पित है।

अर्थव्यवस्था को गति देगा यह बजट

- बजट राज्य की अर्थव्यवस्था को गति को देने वाला विकासोन्मुखी बजट है। युवाओं के कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण योजनाओं, एवं प्रोत्साहन योजनाओं से उनकी सामाजिक आर्थिक भागीदारी मजबूत होगी, जिससे निसंदेह कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी। साथ ही कार्यरत महिलाओं के लिए हॉस्टल सुविधाएं महिला सुरक्षा की दिशा में सरकार का महत्वपूर्ण कदम हैं। पूंजीगत व्यय में वृद्धि से निवेश बढ़ेगा, जो रोजगार सृजन में सहायक होगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण नीति की नई योजना एक अच्छी पहल है जिससे ड्राप आउट रेट भी कम होगा।

-**प्रो. पूनम वर्मा**, अर्थशास्त्र विभाग, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय महिला महाविद्यालय

'सप्लाई-साइड इकोनॉमिक्स' की ओर झुकाव

- बजट केवल व्यय का ब्योरा मात्र नहीं है, बल्कि 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में एक 'मैक्रो-इकोनॉमिक रोडमैप' है। यह बजट स्पष्ट रूप से 'सप्लाई-साइड इकोनॉमिक्स' की ओर झुकाव दर्शाता है, जहां सरकार का प्राथमिक दर्शन 'इंफ्रास्ट्रक्चर से एम्प्लॉयमेंट' के बहुआयामी प्रभाव पर आधारित है। पूंजीगत व्यय और ढांचागत प्रोत्साहन बजट का लगभग 19.5% हिस्सा आवंटित करना एक साहसिक आर्थिक निर्णय है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इकाइयों में 55% की राष्ट्रीय हिस्सेदारी एक रणनीतिक कदम है। बजट में कौशल विकास के लिए पीपीपी मॉडल का प्रस्ताव 'ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन' की आवश्यकता को रेखांकित करता है। औद्योगिक इकाइयों में महिलाओं की भागीदारी प्रगतिशील पहल है।

-**डॉ. अनामिका चौधरी**, अर्थशास्त्र विभाग, डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय

संतुलित और स्वागत योग्य बजट

- प्रस्तुत बजट आम लोगों की आकांक्षाओं के अनुरुप है। शिक्षा के प्रत्येक मद में वृद्धि की गई है। इससे उत्तरप्रदेश का युवा अधिक ज्ञान और कौशल सम्पन्न होगा जिससे रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ वह सम्मन्न भी होगा। महिलाओं के कौशल विकास केंद्रों को विकसित करना आगामी चुनाव को देखते हुए घोषणा है। यह बजट सभी क्षेत्र की जरुरतों को पूरा करने वाला संतुलित बजट है।

-**डॉ. पीयूष कुमार त्रिवेदी**, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

विकसित उत्तर प्रदेश का बजट है यह

- पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में यह लगभग 12.9 प्रतिशत अधिक है। यह बजट विकसित भारत के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए 'विकसित उत्तर प्रदेश' पर फोकस करता है। बजट में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सीएम युवा उद्यमी योजना हेतु 1000 करोड़ रूपये की धनराशि आवंटित की गई है। साथ ही 40 लाख युवाओं को टैबलेट बांटने का भी प्रावधान है। जिसके लिए 575 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ओडीओसी (एक जिला एक व्यंजन) योजना लागू की गई है। राजकोषीय-जीएसडीपी अनुपात को अनुकूलतम 3 प्रतिशत पर रखा गया है।

-**प्रो. भारती पाण्डेय**, अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, श्रीजयनारायण पीजी कॉलेज

धुआं न शोर, इको फ्रेंडली ई-बसें बढ़ाने पर जोर

पर्यावरण की 'मित्र' इलेक्ट्रिक बसों की रफ्तार बढ़ाने की तैयारी, बस स्टेशनों पर बनेंगे चार्जिंग प्वाइंट

नीरज मिश्र, लखनऊ

अमृत विचार: न धुआं होगा और न ही शोर, इको फ्रेंडली ई-बसों के बढ़ाने पर इस बार सरकार का जोर। प्रदेश सरकार ने प्रदूषण पर गंभीर पहल करते हुए पर्यावरण के 'मित्र' इलेक्ट्रिक बसों की रफ्तार को और बढ़ाने का अपना विजन साफ कर दिया है। बजट में तात्कालिक लाभ से इतर दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उप्र. राज्य सड़क परिवहन निगम को 550 करोड़ का बजट आवंटित कर दिया है। इससे न केवल इलेक्ट्रिक बसों का कुनबा बढ़ेगा, बल्कि उनके करंट का भी ठोस इंतजाम करने पर अपनी मुहर लगा दी है। ई-बसों और ई-वाहनों को भविष्य मानते हुए सरकार न केवल गाड़ी के पंजीकरण में छूट बल्कि क्रय सब्सिडी तक में रियायत दे रही है। इसकी समय सीमा तक बढ़ा दी गई है। और तो और प्रदेश में ई-वाहनों की निर्माता कंपनियों के लिए भी विशेष तरह के छूट के पैकेज जारी किए जा चुके हैं।

400 करोड़ से खरीदी जाएंगी ई-बस

परिवहन निगम के बेड़े के सुदृढ़ीकरण के लिए बजट में 400 करोड़ रुपये मिले हैं। इस आवंटित धनराशि से इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की जाएगी। इसका प्रयोग अन्यत्र नहीं किया जा सकेगा। सिर्फ ई-बसें की कुनबे में शामिल की जाएंगी।

रोडवेज बेड़े में अभी 220 ई-बसें

परिवहन निगम के पास अब तक 220 ई-बसें आ गई हैं। यह बसें करीब 9 स्थानों पर चल रही हैं। इनमें प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, बाराबंकी, गोरखपुर, आगरा, मुरादाबाद, साहिबाबाद, नोएडा आदि शहरों में चल रही हैं। नई मिली धनराशि से ई-बसों की फ्लीट मजबूत और बड़ी होगी।

बस स्टेशनों पर 150 करोड़ से बनेंगे चार्जिंग स्टेशन

बजटीय प्रावधान में इन बसों के ईंधन यानी ई-करंट की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया गया है। बस स्टेशन निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इनसे रोडवेज प्रबंधन बस अड्डों पर ई-चार्जिंग स्टेशन की स्थापना करेगा। यही नहीं सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इनमें से 50 करोड़ का आवंटन जीरो फैटलिटी के लिए उपलब्ध कराया गया है। "मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा विजन योजना" के अंतर्गत दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं दुर्घटना के पश्चात त्वरित कार्रवाई के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रदेश बजट में परिवहन विभाग के प्रावधानों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट प्रदेश की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुरक्षित, आधुनिक एवं पर्यावरण-अनुकूल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण और दूरदर्शी कदम है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का आभार जताया है।

-दयाशंकर सिंह, परिवहन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

बजट में नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने, बस अड्डों के निर्माण एवं चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के लिए दिए गए 600 करोड़ के लिए संगठन राज्य सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करता है। इलेक्ट्रिक बसें बढ़ने से परिवहन निगम की रफ्तार और तेज होगी। संगठन का कहना है कि परिवहन निगम में दशकों से कार्यरत संविदा चालकों-परिचालकों व आउटसोर्स कर्मियों के चरणबद्ध नियमितीकरण पर भी निर्णय कराने की कृपा करें। **-गिरीश चंद्र मिश्र, महामंत्री रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद, उप्र.**

महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड से आधी आबादी को संबल

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट 2026-27 की प्रमुख उपलब्धियां बताते हुए कहा कि यह बजट महिलाओं, युवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, पर्यटन और दिव्यांगजन कल्याण को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में मजबूत कदम है। मुख्यमंत्री ने बताया कि महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से महिलाओं को ब्याज-मुक्त पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वे छोटे उद्यम शुरू कर सकें। इसके साथ ही महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना लागू की जाएगी, जो केंद्रीय स्तर की सी-मार्ट अवधारणा की तर्ज पर कार्य करेगी। इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों और महिला उद्यमियों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना है। प्रत्येक जिले में श्रमजीवी महिला छात्रावास के निर्माण का भी प्रावधान किया गया है, जिससे कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित आवास मिल सके।

दिव्यांग छात्राओं के लिए ई-ट्राइसाइकिल, डीडीआरसी केंद्र, कृत्रिम अंग वितरण केंद्र तथा 3-7 वर्ष के दिव्यांग बच्चों के लिए डे-केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर, प्रयागराज, लखनऊ, बरेली, झांसी, मेरठ और आगरा में विशेष प्रशिक्षण केंद्र स्थापित होंगे।

पीपीपी मॉडल पर 1 लाख अतिरिक्त होटल कक्ष

- प्रदेश में 2024-25 में 122 करोड़ पर्यटकों के आगमन का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने पीपीपी मॉडल पर 1 लाख अतिरिक्त होटल कक्ष और 50,000 होम-स्टे विकसित करने की घोषणा की। महिला गाइडों के लिए लाइसेंस शुल्क माफ किया जाएगा।

खेल के लिए ऐतिहासिक पहल

- "वन डिस्ट्रिक्ट, वन कमिश्नरी, वन डिविजनल मुख्यालय, वन स्पोर्ट्स कॉलेज" की परिकल्पना के तहत 18 मंडल मुख्यालयों पर स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। स्पोर्ट्स कालेज मेरठ अप्रैल-मई तक पूर्ण रूप से संचालित होगी। इन कॉलेजों को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स और 2036 ओलंपिक की तैयारी के दृष्टिकोण से उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

श्रमिकों की उन्नति पर जोर

रोजगार मिशन को 200 करोड़ का प्रावधान

- **अमृत विचार, लखनऊ :** वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में योगी सरकार ने श्रमिकों और असंगठित कामगारों के कल्याण को विशेष प्राथमिकता दी है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सदन में बताया कि उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन समिति के गठन और संस्थागत सुदृढ़ीकरण के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य प्रदेश के श्रमिकों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। बजट 2026-27 में रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से श्रमिक परिवारों को सशक्त बनाने का स्पष्ट रोडमैप दिखाई देता है, जो प्रदेश में श्रम आधारित विकास मॉडल को मजबूती देने की दिशा में निर्णायक कदम है। सरकार ने घर से दूर शहरों में कार्यरत मजदूरों के लिए लेबर अड्डों के निर्माण की घोषणा की है, ताकि उन्हें सुरक्षित, संगठित और सुविधायुक्त कार्यस्थल मिल सके। इसे प्रवासी श्रमिकों के श्रम प्रबंधन और सुविधा विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

शिक्षा और स्वास्थ्य से सशक्तिकरण

- श्रमिक परिवारों के सामाजिक उत्थान के लिए अटल आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक नि:शुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। वर्तमान में इन विद्यालयों में 10,876 श्रमिक बच्चों का नामांकन है। इस योजना के लिए 70 करोड़ की व्यवस्था की गई है। निर्माण श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण और स्वास्थ्य शिक्षा के लिए पहली बार मोबाइल हेल्थ वैन पायलट परियोजना के रूप में संचालित की गई है। एक्स-ग्रेशिया अनुदान के तहत पंजीकृत असंगठित श्रमिकों की दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में 2 लाख तथा आंशिक दिव्यांगता पर 1 लाख की सहायता का प्रावधान जारी रखा गया है।

स्वास्थ्य क्षेत्र को मिला बूस्टर डोज

55,820 करोड़ से सुदृढ़ होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, चिकित्सा शिक्षा का मिलेगा विस्तार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार: वर्ष 2026-27 के बजट में चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुल 55,820 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो राज्य के कुल बजट का लगभग 6.1 प्रतिशत है। इसे अब तक का सबसे बड़ा स्वास्थ्य आवंटन माना जा रहा है। इसमें आयुष सेवाओं में आयुर्वेद, यूनानी व होम्योपैथी के विस्तार के लिए 2,867 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है।

राज्य सरकार का फोकस स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ करने, चिकित्सा शिक्षा का विस्तार करने और ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण सेवाएं पहुंचाने पर है। बजट में चिकित्सा शिक्षा के लिए करीब 14,997 करोड़ रूप्ए की व्यवस्था की गई है। इसमें 14 नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 1,023 करोड़ रूपए तथा लखनऊ स्थित कैंसर इंस्टीट्यूट जैसे विशेष संस्थानों के लिए 315 रूपए करोड़ प्रस्तावित हैं। इसके अलावा चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग को 37,956 करोड़ रूपए का प्रावधान है, इनमें ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत 8,641 करोड़ रुपये और आयुष्मान भारत योजना के लिए 2,000 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। बजट में मातृ-शिशु स्वास्थ्य, सुरक्षित प्रसव, टीकाकरण, मानसिक स्वास्थ्य, रोग नियंत्रण और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया गया है। प्रदेश में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावी रूप से लागू है, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को कैशलेस प्रसव सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार का लक्ष्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी लाना है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में दो मेडिकल टीमें तैनात हैं, जो आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों में जाकर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही हैं। इससे जन्मजात बीमारियों, कुपोषण और अन्य रोगों की समय रहते पहचान संभव हो रही है।

टीकाकरण और रोग नियंत्रण में प्रगति

- 8 दिसंबर 2024 से संचालित पल्स पोलियो अभियान के तहत अब तक 3.28 करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक दी जा चुकी है। जापानी इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए 42 संवेदनशील जनपदों में नियमित टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। पूर्वांचल और तराई क्षेत्रों में विशेष स्वास्थ्य शिविरों और निगरानी की व्यवस्था की गई है। संक्रामक रोगों की निगरानी के लिए एकीकृत डिजीज सर्विलांस पोर्टल को और मजबूत किया गया है, जहां 16 संक्रामक रोगों और 6 टीकाकरण योग्य बीमारियों की नियमित रिपोर्टिंग हो रही है।

आयुष्मान और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूती

- गरीब और मध्यम वर्ग को महंगे इलाज से राहत देने के लिए आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के प्रभावी संचालन हेतु 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में 49.22 लाख लाभार्थी परिवार इस योजना से जुड़े हैं। साथ ही राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सभी 75 जनपदों में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। बजट में इसे और प्रभावी बनाने का प्रावधान किया गया है, ताकि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और उपचार सुविधाएं सुलभ हो सकें।

ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को बल

- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 8,641 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के लिए 2,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जिससे दूरदराज और पिछड़े इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार होगा।

हर मंडल में खेल महाविद्यालय

2032-36 ओलंपिक में चमकने का लक्ष्य

- अमृत विचार, लखनऊ: वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में प्रदेश के खेल ढांचे को नई दिशा देने की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि प्रत्येक मंडल में एक खेल महाविद्यालय स्थापित कर उसे उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि वर्ष 2032 और 2036 ओलंपिक को लक्ष्य बनाकर खिलाड़ियों को तैयार किया जा सके। इसके लिए प्रारंभिक तौर पर 80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों में प्रति विधानसभा 3 लाख रुपये और 80 संसदीय क्षेत्रों में प्रति क्षेत्र 10 लाख रुपये की दर से सांसद/विधायक खेल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसके लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे ग्रामीण और स्थानीय स्तर पर प्रतिभाओं को मंच मिलेगा। मेजर ध्यानचंद राज्य खेल विश्वविद्यालय, मेरठ के नवीन भवन निर्माण एवं विकास कार्य के लिए 80 करोड़ रुपये, पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए 30 करोड़ रुपये तथा शैक्षणिक व खेल गतिविधियों के संचालन के लिए 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार कुल 170 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान नई मांग के माध्यम से किया जा रहा है। कानपुर स्थित ग्रीनपार्क अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के उच्चीकरण और आधुनिकीकरण के लिए 45 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है, जिससे स्टेडियम का पुनर्विकास कर उसे आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। योगी सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय मंच पर तिरंगा लहराएं और उत्तर प्रदेश खेल प्रतिभा का नया केंद्र बने। वर्तमान में गोरखपुर में वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, लखनऊ में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज और सैफई स्पोर्ट्स कॉलेज हैं।

दोगुनी आय और घटती बेरोजगारी का किया दावा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार: वित्तीय वर्ष 2026-2027 के बजट अनुमानों पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सर्वांगीण विकास को प्रमुखता से रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि सरकार के पिछले और वर्तमान कार्यकाल में कानून-व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण से लेकर अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार, औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन, महिला सशक्तीकरण, युवाओं के कौशल संवर्धन, किसानों की खुशहाली और गरीबी उन्मूलन तक व्यापक बदलाव दर्ज किए गए हैं।

वित्त मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था निरंतर मजबूती की ओर अग्रसर है। वर्ष 2024-2025 (त्वरित अनुमान) में राज्य की जीएसडीपी 30.25 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,09,844 रुपये आंकी गई है, जो वर्ष 2016-2017 की 54,564 रुपये प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले दोगुने से अधिक है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि वर्ष 2025-2026 में प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 रुपये होने का अनुमान है। सरकार ने लगभग छह करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने में सफलता प्राप्त की है, जबकि बेरोजगारी दर घटकर 2.24 प्रतिशत रह गई है। उन्होंने दावा किया कि आर्थिक वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विस्तार और निवेश-आधारित विकास मॉडल के चलते उत्तर प्रदेश देश की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है।

वित्त मंत्री का बजट भाषण

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना

निवेश, निर्यात और नवाचार

अमृत विचार, लखनऊ : वित्तीय वर्ष 2026-2027 के बजट अनुमानों पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने भाषण में उत्तर प्रदेश की आर्थिक और औद्योगिक प्रगति को विस्तार से रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग वर्ष 2018-2019 में 29वें स्थान पर थी, जो बेहतर होकर वर्ष 2023-2024 में 18वें स्थान पर पहुंच गई है। वित्त मंत्री ने बताया कि फरवरी 2024 में आयोजित चौथे ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मिट ने निवेश के नए कीर्तिमान स्थापित किए। अब तक लगभग 50 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हस्ताक्षरित हो चुके हैं, जिनसे लगभग 10 लाख रोजगार सृजन की संभावना है। इनमें से करीब 15 लाख करोड़ रुपये के निवेश से जुड़ी 16 हजार से अधिक परियोजनाओं के चार ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह संपन्न हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आज भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण केंद्र बन चुका है। देश के कुल मोबाइल फोन उत्पादन का 65 प्रतिशत हिस्सा प्रदेश में निर्मित होता है। साथ ही, भारत की 55 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इकाइयां भी प्रदेश में स्थित हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 44,744 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि उद्योग और तकनीक में निवेश के साथ-साथ नवाचार को बढ़ावा देने के प्रयासों के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर स्टार्टअप रैंकिंग में "लीडर श्रेणी" का दर्जा प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि निवेश, विनिर्माण और नवाचार के इस त्रिकोणीय मॉडल ने प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं की कतार में खड़ा कर दिया है।

भाजपा सरकार का आखिरी और विदाई बजट : अखिलेश

अमृत विचार, लखनऊ : सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि यह भाजपा सरकार का आखिरी और विदाई बजट है। भाजपा जनता से किये वादों को भूल गयी। भाजपा जनता की भावनाओं से खेलती है। बजट में गरीबों, किसानों, युवाओं के लिए कुछ नहीं है। बजट का आकार बड़ा है, मगर न तो मंहगाई कम हुई और न ही बेरोजगारी खत्म हुई। सपा प्रमुख बुधवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार में बैठे लोग अयोग्य है, सरकार बजट खर्च नहीं कर पाती है। अभी तक पिछले बजट का 50 फीसदी भी नहीं खर्च कर पाई है। सरकार वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का सपना दिखाती है। उन्होंने कहा कि ट्रिलियन डालर इकोनामी के लिए जीएसडीपी 90 लाख करोड़ की होनी चाहिए और ग्रोथ रेट 30 फीसदी होनी चाहिए। जब आखिरी बजट पेश कर दिया तो 90 लाख करोड़ की जीएसटडीपी कहां से बनाएंगे।

बजट का आकार और तुलना

- कुल बजट : 9 लाख 12 हजार 696 करोड़ 35 लाख रुपये
- कुल प्राप्तियां: 8.48 लाख करोड़
- राजस्व प्राप्तियां: 7.29 लाख करोड़
- कुल व्यय: 9.13 लाख करोड़
- राजस्व व्यय: 6.64 लाख करोड़
- पूंजीगत व्यय: 2.48 लाख करोड़

नई योजनाओं की भरमार

- सरदार वल्लभभाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन
- बायोप्लास्टिक औद्योगिक नीति-2024
- वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति
- मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना
- महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना
- पशुधन बीमा एवं जोखिम प्रबंधन योजना
- सहकारी चीनी मिलों का आधुनिकीकरण
- ड्रीम स्किल लैब
- नए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय
- छात्राओं के लिए प्रत्येक जनपद में छात्रावास
- टेक युवा-समर्थ युवा योजना
- चार सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल (पीपीपी मोड)
- ट्रॉमा सेंटर लेवल-2
- चिकित्सा महाविद्यालयों में छात्रावास
- उत्तर प्रदेश एआई मिशन
- स्टेट डेटा सेंटर
- डेटा सेंटर क्लस्टर
- यू-हब की स्थापना
- 'ग्रीन' और 'पिंक' बजट पर फोकस

बजट विकसित भारत की संकल्पनाओं को समर्पित

अमृत विचार, लखनऊ : विधान परिषद में बजट सत्र के तीसरे दिन बुधवार को उप मुख्यमंत्री व नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश के 2026-27 के बजट प्रावधानों को प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह बजट विकसित भारत की संकल्पनाओं को समर्पित बजट है। जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। इसमें नारीशक्ति, किसानों, युवाओं और समाज के सभी वर्गों का खयाल रखा गया है। उप मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को आवंटित बजट का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो रहा है। अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में ठोस कदम उठाये गये हैं। युवाओं को रोजगार देने, किसानों व आम जनता की खुशहाली के लिये संतुलित बजट है। बजट में ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के लिए 25,550 करोड़ रुपये, इनमें मनरेगा तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए क्रमशः 5,544 करोड़ रुपये एवं 4580 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।

विशेष टिप्पणी | लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्रो. मनोज अग्रवाल ने बजट को बताया संतुलित

प्रदेश के समग्र विकास का प्रगतिगामी बजट

यह बजट चुनावी बजट होते हुए भी प्रगति का बजट है और दीर्घकालीन रणनीति वाला बजट है। सबसे बड़ी बात की इसमें संतुलन रखा गया है। बजट घाटे को सीमित दायरे में रखा गया है, 2.98 प्रतिशत जो 3 प्रतिशत से नीचे है। इसके अलावा राजस्व व्यय को सीमित रखते हुए राजस्व आय बढ़ाने के उपाय किए गए हैं। जिसके कारण हमारा पूंजीगत परिव्यय राज्य आय का 4.5 प्रतिशत हो गया है। यह आज से 9 साल पहले 3 प्रतिशत से काफी कम था। इसका लाभ यह हो रहा है कि जब विधि व्यवस्था दुरुस्त हो गई है, डिजिटल चीजें अच्छी होने के साथ गर्वनेंस में सुधार हुआ है। इसके अलावा इज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा हुआ है। सरकारी निवेश और आधारभूत संरचना बढ़ने से विदेशी निवेश के साथ घरेलू निवेश तेजी से बढ़ा है। जो इंवेस्टर समिट में दिखाई भी दिया।

प्रो. मनोज अग्रवाल, अर्थशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय

दूसरा, यह बजट युवाओं की संभावना वाला और महिलाओं के विकास वाला है। व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा का बजट काफी बढ़ाया गया है, इसी के साथ आईटी सेक्टर और इलेक्ट्रानिक का बजट बढ़ाया गया है। दोनों का तालमेल करके लैब बनाया जाना है, एआई का लैब, डेटा सेंटर के लिए 30 हजार करोड़ के 6 प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। यह सारी चीजें उत्तर प्रदेश को काफी आगे ले जाएंगी। कृषि में 20 प्रतिशत, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर 30 प्रतिशत बजट बढ़ा है, इसी प्रकार पंचायती राज में बहुत ज्यादा बजट बढ़ाया गया है। खेती को आधुनिक करने के लिए डीजल पम्पिंग सेट की जगह सोलर पम्पिंग सेट को बढ़ावा देना, सड़क बनाना, पुलिया आदि के अवस्थापना के लिए पर्याप्त बजट है। केंद्र सरकार के साथ यूरोपियन यूनियन और अमेरिका से जो प्रस्ताव पास हुआ है। जिससे हमारा टैक्सटाइल का निर्यात बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मित्र टैक्सटाइल पार्क योजना के तहत पार्क बनेगा। जिसका लाभ उठाते हुए हथकरघा और वस्त्र उद्योग का बजट 5 गुना कर दिया गया है, जिससे टैक्सटाइल सेक्टर में हमारा निर्यात बढ़ सके। इसी तरह एमएसएमई सेक्टर, अवस्थापना, उद्योग जगत का बजट भी बढ़ाया गया है। माइक्रो यूनिट में एक लाख लोगों को गारंटीमुक्त व ब्याज मुक्त ऋण देने की बात है, जिससे वह अपना व्यवसाय लगा सकें। युवाओं के प्रशिक्षण पर, मेडिकल एजुकेशन पर या मेडिकल सीट में जो बढ़ोत्तरी हुई है। उससे युवाओं के कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा और उनके रोजगार की संभावनाएं तेजी से बढ़ रही है। यह सारी चीजें प्रगतिगामी हैं।

● अमृत विचार

विभागीय आवंटन में प्राथमिकताएं

सबसे अधिक आवंटन प्राथमिक शिक्षा (80,997 करोड़), ऊर्जा (65,926 करोड़), गृह (44,145 करोड़) और लोक निर्माण विभाग (33,740 करोड़) को मिला है।

बुनियादी ढांचा और निवेश

- सात संचालित एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट शीघ्र शुरू
- 16,000 स्टार्टअप, 8 यूनिकॉर्न
- 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश प्रस्ताव

पर्यटन और धार्मिक अर्थव्यवस्था

- महाकुंभ 2025 में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु
- 234 गांव पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित
- लखनऊ 'क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी'

बरेली न्यूरो एण्ड स्पाईन सुपर स्पेशलिटी सेंटर

डा. मोहित गुप्ता

M.Ch., Neurosurgery (AIIMS)
Senior Consultant Neurosurgeon
मस्तिष्क, रीढ़ एवं नस रोग विशेषज्ञ
Reg. No. UPMCI 65389
समय - प्रातः 10 से 12:30 बजे तक एवं सायं 6 से 8:30 बजे तक

अब डॉ. मोहित गुप्ता रविवार को भी मिलेंगे प्रातः 10 से दोपहर 1 बजे तक

सुविधायें

ब्रेन हैमरेज | स्लिप डिस्क
ब्रेन ट्यूमर | मिर्गी का दौरा
गर्दन दर्द (सर्वाइकल)
रीढ़ की चोट, टी.बी
सिर दर्द, माइग्रेन
कमर दर्द, कंधों में दर्द
पीठ दर्द, रीढ़ की गांठ
सिर की चोट (हेड इंजरी)
हाथ पैरों में झनझनाहट
फालिज (लकवा)
नसों का दर्द
सियाटिका (कमर में पैरों का दर्द)
दिमागी में पानी व खून जमना
दिमाग, रीढ़ एवं नस सम्बन्धित सभी बीमारियों का इलाज एवं ऑपरेशन

Bareilly Neuro and Spine Super Speciality Centre
Google Maps Location

सी-427, डिवाइन अस्पताल के सामने, के.के. अस्पताल रोड, राजेन्द्र नगर, बरेली
7417389433, 7017678157
9897287601, 8191879754

भतीजी की लगन लेकर जा रहे चाचा की हादसे में मौत, दो घायल

अलग-अलग हादसों में तीन लोग गंभीर घायल, जिला अस्पताल किए गए रेफर

संवाददाता, आंवला

अमृत विचार: भतीजी की लगन लेकर जा रहे चाचा की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि बाइक पर पीछे बैठे दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया

मृतक अनिल

रामपुर जनपद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के गांव पनबड़िया निवासी अनिल(22) गांव के ही सतपाल और ओमकार के साथ बाइक से कुंवरगांव (बदायूं) भतीजी की लगन लेकर जा रहा था। बुधवार देर शाम आंवला–रामनगर रोड पर गांव भूरीपुर चम्पतपुर मोड़ के पास गन्ने की खाली ट्रॉली के चालक ने अचानक मोड़ लिया, जिससे बाइक ट्रॉली की चपेट में आ गई।

हादसे में अनिल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सतपाल और ओमकार गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। परिजनों के अनुसार मृतक की शादी एक वर्ष पूर्व ही हुई थी।

तेहरवीं के बाद मौसी को छोड़ने जा रहे बाइक सवार को बस ने मारी टक्कर, चालक फरार

नवाबगंज, अमृत विचार : दादी की तेहरवीं संस्कार के बाद मौसी को घर छोड़ने जा रहा एक युवक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद रोडवेज बस का चालक और परिचालक बस छोड़कर मौके से फरार हो गए। कस्बा नवाबगंज के मोहल्ला बिजौरिया निवासी संजू पुत्र ज्ञान प्रकाश बुधवार को अपनी दादी सुशीला देवी की तेहरवीं कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अपनी मौसी मीना को बाइक से मोहल्ला हरीनगर छोड़ने जा रहा था। इसी दौरान बरेली की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि संजू सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर अफरा–तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने उसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया, जहां से हालत नाजुक देखते हुए उसे बरेली रेफर कर दिया गया।

बाइक सवार युवक को पिकअप ने मारी टक्कर, घायल

भुता, अमृत विचार : बरेली बीसलपुर मार्ग पर बाइक सवार की पिकअप गाड़ी में टक्कर होने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया है। जहां घायल की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। बरेली बीसलपुर मार्ग पर राघवपुर निवासी धर्मेंद्र की बाइक पर सामने से आ रही पिकअप गाड़ी ने टक्कर मार दी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल धर्मेंद्र को बरेली अस्पताल भेजा।

पिकअप और ट्रैक्टर की आमने-सामने भिड़ंत, चालक गंभीर घायल

नवाबगंज, अमृत विचार : थाना क्षेत्र के धोरेरा मोड़ पर मंगलवार को पिकअप और ट्रैक्टर के बीच आमने–सामने की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार पिकअप चालक अमन, थाना भुता क्षेत्र के गांव गूंगा का निवासी है। वह अपने वाहन से जा रहा था, तभी धोरेरा मोड़ पर सामने से आ रहे ट्रैक्टर से उसकी सीधी भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। घायल अमन को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में ले लिया है। फरार ट्रैक्टर चालक की तलाश की जा रही है।

पेड़ से लटका मिला युवक का शव, जांच

संवाददाता, नवाबगंज

अमृत विचार : क्षेत्र के गांव रत्नानंदपुर में बुधवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब एक युवक का शव गांव के बाहर पेड़ से लटका मिला। घटना संदिग्ध परिस्थितियों में होने से परिजनों ने आशंका जताई है।

मृतक महेश।

जानकारी के अनुसार गांव रत्नानंदपुर निवासी महेश कुमार (24) की शादी करीब दस माह पूर्व बरखना हरचंदपुर गांव की कुसुम के साथ हुई थी। महेश रुद्रपुर स्थित एक फैक्टरी में कार्यरत था। 8 फरवरी को वह अपनी पत्नी को लेकर ससुराल गया था और वहां से सीधे रुद्रपुर चला गया था। बुधवार को उसका शव गांव में एक पेड़ से लटका मिलने से परिवार में कोहराम मच गया। मौके पर उसकी बाइक, हेलमेट और कपड़ों का बैग भी पड़ा मिला। परिजनों ने शव की पहचान महेश कुमार के रूप में की।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए जांच शुरू कर दी। मृतक की पत्नी कुसुम भी अपने मायके पक्ष के लोगों के साथ कोतवाली पहुंची और घटना को संदिग्ध बताया। मृतक के भाई नरेन्द्र कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है।

भदपुरा में हिंदू सम्मेलन आयोजित

भदपुरा, अमृत विचार : संगठित हिंदू, संगठित भारत'' के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने के उदेश्य से नकटी नारायणपुर गांव में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया।

सम्मेलन में हिंदू समाज के प्रबुद्ध नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और युवा वर्ग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। वक्ताओं ने हिंदू समाज की एकता, सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा, सामाजिक समरसता और राष्ट्र निर्माण में संगठन की भूमिका पर अपने विचार प्रस्तुत किए। सनातन की रक्षा के प्रति संकल्प लिया।

मुख्य वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि एक संगठित समाज ही सशक्त राष्ट्र की नींव होता है। हिन्दुत्व पर अडिग रहने और हिंदू समाज से जाति, वर्ग और क्षेत्रीय भेदभाव से ऊपर उठकर एकजुट होने का आह्वान किया।

इस दौरान महेश पाल, दिनेश कुमार, श्री कृष्ण, मुनेंद्र पाल अमित कुमार, पीताम्बर गंगवार आदि मौजूद रहे।

टोल प्लाजा के खिलाफ पदयात्रा

भोजीपुरा संवाददाता

अमृत विचार : भोजीपुरा टोल प्लाजा कर्मियों द्वारा हवाई अड्डा गेट के डेयरी किसानों के कथित उत्पीड़न के विरोध में किसान एकता संघ ने विशाल पदयात्रा निकाली । किसान नेता डॉ. रवि नागर के नेतृत्व में दोपहर 1:00 बजे हवाई अड्डा गेट से पदयात्रा प्रारंभ हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसान शामिल हुए।

पदयात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए किसान। ● अमृत विचार

किसानों ने टोल प्लाजा की कथित तानाशाही के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए टोल प्लाजा की ओर कूच किया और टोल प्लाजा पहुंचकर धरना दिया। यहां किसान नेता ने कहा कि डेयरी किसान परिवारों पर किसी भी प्रकार की तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि अतिक्रमण के नाम पर सड़क किनारे की जमीन खाली कराई जानी है तो यह कार्रवाई सभी पर समान रूप से होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि एकतरफा कार्रवाई के दौरान कोई अप्रत्याशित घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी टोल प्रशासन की होगी।

राष्ट्रीय सचिव यज्ञ प्रकाश गंगवार ने आरोप लगाया कि टोल प्लाजा पर कर्मियों के नाम पर, असामाजिक तत्व बैठे हुए हैं, जो किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। पदयात्रा में राजेश शर्मा, श्याम पाल चौधरी, बहुरन लाल गुर्जर, खेतल सिंह, रूपलाल लेखपाल, भगवान सिंह फौजी, गिरीश गोस्वामी, श्रीराम, वीरेश भगत, लालाराम, नरेश गुर्जर, पप्पू नेता जी, महेंद्र यादव, घनश्याम गुर्जर, राजेंद्र खलीफा, संजीव गुर्जर, अमरसिंह, वीरपाल, वीरेश गुर्जर, पेशकार, बंटू, इमरान, शुभम शर्मा, ताहिर, लखपत यादव, प्रेमपाल गंगवार, शहादत खान सहित सैकड़ों किसान उपस्थित रहे।

शादी से 10 दिन पहले युवती फरार

संवाददाता, नवाबगंज

अमृत विचार : विवाह से 10 दिन पहले युवती को एक युवक बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया। मामले में युवती की बुआ की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया।

जानकारी के अनुसार, युवती अपनी बुआ के साथ गांव में रहती है। देवरनिया थाना क्षेत्र के रहपुरा घनश्याम गांव निवासी एक युवक काफी समय से उसे परेशान कर रहा था। वह पहले भी दो बार युवती को अपने साथ ले जा चुका था, लेकिन ग्रामीणों के हस्तक्षेप से दोनों बार युवती को सकुशल वापस घर पहुंचा दिया गया था।

परिजनों ने युवती का विवाह बहेड़ी थाना क्षेत्र के इटौआ गांव के एक युवक के साथ तय कर दिया था। 22 फरवरी को बारात आनी थी और घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। इसी बीच मंगलवार को आरोपी युवक अपने मौसेरे भाई की मदद से युवती को फिर से अपने साथ ले गया। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया है।

नाबालिग को भगा ले गया युवक छह पर रिपोर्ट

फतेहगंज पश्चिमी के गांव से एक युवक पड़ोस की दलित नाबालिग को बहला फुसला कर भगा ले गया। पिता को भी आरोपी के घरवालों ने मारपीट की। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने युवक छोटेलाल समेत 6 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

अमृत विचार एक सम्पूर्ण अखबार
क्लासीफाइड
विज्ञापन हेतु सम्पर्क करें
9756905552, 8445507002

सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम फैज अहमद सिद्दीकी पुत्र स्व. शकील अहमद सिद्दीकी है मैं अपना नाम फैज अहमद सिद्दीकी से बदलकर फैज अहमद करना चाहता हूं। अतः भविष्य में मुझे फैज अहमद के नाम से ही जाना जाये।

सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपने पुत्र गुड्डू व पुत्रवधु फातिमा को उसके गलत व्यवहार व आचरण के कारण अपनी समस्त चल -अचल संपत्ति से बेदखल कर संबंध विच्छेद कर लिया है। अब मेरे व मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से उनका कोई संबंध व सरोकार नहीं होगा वह अपने कृत्य का स्वयं जिम्मेदार होंगे। **आरिफ पुत्र हामिद निवासी ग्राम नदायल परगना व तहसील सहसवान जिला (बदायू)**

सूचना
मैंने अपना नाम MOHAMMAD SHUAIB SHAMSI से बदलकर SHUAIB SHAMSI कर लिया है, भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाए। **शोएब शम्सी पुत्र अफजाल उल हक शम्सी, निवासी मोहल्ला पकड़िया गुरूद्वारा रोड, पीलीभीत।**

सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी PNB METLIFE पॉलिसी में पिता का नाम भूलवश समर पाल अंकित हो गया है जबकि उनका वास्तविक नाम समर पाल सिंह है। आधार कार्ड व अन्य सभी दस्तावेजों में भी उनका नाम समर पाल सिंह ही दर्ज है। **केन्द्र सिंह पुत्र श्री समर पाल सिंह निवासी ग्राम परौरा तहसील मीरगंज जिला बरेली।**

सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपने पुत्र ईबने अली व उसकी पत्नी रिहाना को गलत आचरण एवं दुर्व्यवहार के कारण सम्बन्ध विच्छेद कर अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति व जात जायदाद से बेदखल कर दिया है। भविष्य में उनके द्वारा किए गए कृत्यों के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे। मेरा व मेरे परिवार से कोई वास्ता नहीं होगा। **फातिमा बेगम पत्नी इसरत अली निवासी मोहल्ला मीरखां बाबर नगर कस्बा व तहसील मीरगंज जिला बरेली।**

बिकाऊ है
225 गज मकान
कॉर्नर का पूर्वमुखी
आशीष रॉयलपार्क फेस-2,
इच्छुक व्यक्ति ही संपर्क करें- बरेली
मो. 9897211014

वैधानिक सूचना :- समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन जैसे टावर सम्बन्धी, नौकरी सम्बन्धी, ऋण सम्बन्धी या अन्य किसी भी प्रकार के विज्ञापन में पाठकों को सावधान किया जाता है। विज्ञापनदाता द्वारा किये गये दावे या उल्लेख, समर्थन की पुष्टि समाचार पत्र नहीं करता है।

MEDICAL Lifelines OF BAREILLY अमृत विचार
विज्ञापन हेतु सम्पर्क करें :- 8445507002

फोकस नेत्रालय
राजेन्द्र नगर, बरेली 731-098-7005

बरेली का सबसे बड़ा केवल आँखों के लिए समर्पित प्राइवेट अस्पताल ...
नवीनतम AI तकनीक एवं NABH मान्यता के साथ
● 40,000 से अधिक सफल सर्जरी सम्पन्न
● बिना इंजेक्शन एनेस्थीसिया (केवल आई ड्राप्स द्वारा)
● आयुष्मान/सीजीएचएस/ ईसीएचएस/सीएपीएफ सभी स्वास्थ्य बीमा मान्य
● कैशलेस ईलाज

स्वास्थ्य जागरूकता अभियान
नि : शुल्क परामर्श
कैम्प में समस्त ब्लड जाँचें, ई.सी.जी., एक्स-रे 50% के छूट पर किये जायेंगे।
रजिस्ट्रेशन शुल्क 20/-
प्रेमलोक हॉस्पिटल
नरियावल अड्डा, शाहजहाँपुर रोड, बरेली।
महीने के प्रत्येक रविवार को
समय : सुबह 10 से 5 बजे तक
डॉ. दीपक माहेश्वरी
MBBS., MD, Consultant Physucuan & Critical Care Specialist
ब्लड प्रेशर, हृदय रोग श्वांस रोग, गम्भीर रोग विशेषज्ञ
9084307201, 9412244430
डॉ. नितिन अग्रवाल हृदय रोग विशेषज्ञ मो. 9457833777

ADITYA
आदित्य आई एण्ड लेजर सेन्टर
उपलब्ध सुविधायें :-
बिना सुई बिना टांका आधुनिक लेंस प्रत्यारोपण की सुविधा।
TPA कैशलेस सुविधा उपलब्ध
100000 से अधिक आंखों के आपरेशन का अनुभव
अल्ट्रासाउण्ड द्वारा पर्दे की जांच की सुविधा उपलब्ध
IOL Master 700 द्वारा लेंस का नम्बर
लेजर द्वारा आंख की झिल्ली हटाने की सुविधा उपलब्ध
बी स्कैन द्वारा पर्दे की जांच उपलब्ध
OCT द्वारा काला पानी एवं पर्दे की जांच व उपचार
8077344353
समय : प्रातः 10 बजे से सायं 7 बजे तक (सोमवार से शनिवार)

डॉ. आदित्य त्यागी
MBBS, DOMS, DNB, MNAMS
CARARACT REFRATIVE & GLAUCOMA SURGERON
आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए फ्री आपरेशन की सुविधा
ट्यूलिप ग्रांड के सामने, पीलीभीत बाईपास, बरेली

न्यूज डायरी

सीएचसी पर गंदगी देख एसडीएम नाराज

आंवला, अमृत विचार : सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बुधवार को एसडीएम आंवला विदुषी सिंह ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने उपस्थिति रजिस्टर आदि की जांच की। एसडीएम ने सीएचसी परिसर में गंदगी पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। कर्मचारियों ने एसडीएम को बताया कि स्वास्थ्य केन्द्र पर एक सफाई कर्मी तैनात है। एसडीएम ने सप्ताह में एक बार समुचित सफाई कराने के निर्देश दिये।

एनएसएस के शिविर में बनाया सोशल मीडिया चैनल

मीरगंज, अमृत विचार : बुधवार को राजेंद्र प्रसाद डिग्री कॉलेज में एक दिवसीय एनएसएस शिविर में एनएसएस स्वयंसेवकों ने कार्यक्रम अधिकारी बी .के . प्रधान के नेतृत्व में एनएसएस फेसबुक आईडी और यूट्यूब चैनल बनाया, जिसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाना है। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी ने कहा, हमारा उद्देश्य एनएसएस के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाना है।

बच्चों का किया टीकाकरण

शेरगढ़, अमृत विचार : गांव बैरमनगर में आयोजित टीकाकरण कार्यक्रम में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती को टीके लगाए गए। पर्यवेक्षक शिवांगी शुक्ला ने टीकाकरण कार्यक्रम का निरीक्षण किया। इस दौरान स्वस्थ कर्मियों ने ग्रामीणों को स्वस्थ रहने का मंत्र देते हुए टीकाकरण को जरूरी बताया। उन्होंने महिलाओं को बच्चों की देखभाल एवं खान–पान पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य के प्रति प्रेरक जानकारी दी। सलमा, छज्जो देवी, संगिनी सरिता, आशा सरोज आदि रहीं।

बारहवीं के बच्चों की हुई विदाई

भोजीपुरा, अमृत विचार : गायत्री शिक्षा पीठ इंटर कॉलेज में 11वीं कक्षा के जूनियर बच्चों ने 12 वीं कक्षा के बच्चों को धूमधाम से बिदाई की। इस अवसर पर सभी विषयों के अध्यापकों ने अपने – अपने विषयों में छात्रों से अच्छी लगन और मेहनत से पढ़ाई व रिवीज़न करके परीक्षा देने के गुण सूत्र बताए। कालेज की प्रधानाचार्या शोभा आनंद ने सभी बच्चों की परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने व उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर मैनेजर गोपाल शर्मा, सिद्धि शर्मा, इंचार्ज सविता शुक्ला एवं समस्त शिक्षक गण की उपस्थिति रहे।

न्यूज ब्रीफ

स्कूल गया 9वीं का छात्र गायब

भमोरा, अमृत विचार : थाना क्षेत्र के गांव रामपुर कांकर निवासी विमल कुमार ने बताया कि उनका 14 वर्षीय पुत्र यश कक्षा नौवीं का छात्र है। 9 फरवरी को सुबह स्कूल जाने की बात कहकर घर से गया था। देर शाम तक घर वापस न आने पर काफी तलाश किया। लेकिन उसकी कोई जानकारी नहीं मिली। थाना पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच की बात कही।

दो महिलाओं सहित तीन का चालान

फतेहगंज पश्चिमी, अमृत विचार : थाना क्षेत्र के गांव सोराहा में बच्चों के बीच हुए विवाद ने देखते ही देखते बड़ों के बीच मारपीट का रूप ले लिया। खेल के दौरान बच्चों में कहासुनी हो गई, जिसके बाद दोनों पक्षों के परिजन आमने-सामने आ गए और जमकर हंगामा हुआ। शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने दोनों पक्षों से तस्लीम उर्फ भूरा, सोना और शवनव के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई करते हुए चालान कर दिया।

आज ग्रामीण क्षेत्रों में बाधित रहेगी बिजली

नवाबगंज, अमृत विचार : गुरुवार को 33 केवी लाइन पर एनएचएआई द्वारा कार्य किया जाएगा। कार्य की निरंतरता और सुरक्षा के लिए गुरुवार को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक देहात क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। यह जानकारी अवर अभियंता (ग्रामीण) ने दी है।

दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

सिरौली, अमृत विचार : पुलिस ने दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के मामले में काफी समय से फरार चल रहे आरोपी फैजान को गिरफ्तार कर लिया है। कस्बा सिरौली निवासी पीडिता ने फैजान पुत्र उमर निवासी मोहल्ला कौवा टोला के खिलाफ बहला-फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाने और इस बात को साझा करने पर जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामला दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। बुधवार को पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया है।

नौ ग्राम स्नैक के साथ तस्कर गिरफ्तार,

कैंट, अमृत विचार : थाना पुलिस ने 9 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

अतिक्रमण हटाने में ईओ व दुकानदार के बीच मारपीट

शेरगढ़ में दो दिनों से शांति से चल रहा था अभियान, दुकानदार और ईओ ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में दी तहरीर

संवाददाता शेरगढ़

अमृत विचार: फतेहगंज पश्चिमी में अतिक्रमण हटाने के दौरान ईओ और व्यापारी के बीच हुई झड़प का मामला शांत ही हुआ था कि अब शेरगढ़ में भी वैसा ही मामला हो गया है। बुधवार को बाजार से अतिक्रमण हटाने के दौरान व्यापारी और ईओ के बीच पहले वाद विवाद फिर हाथापाई की नौबत आ गई। दोनों तरफ से थाने में तहरीर दी गई है। पुलिस इस बार फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है और अभी किसी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। ईओ के साथ हुई बदसलूकी के बाद पंचायत कर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया है। ईओ के साथ मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है।

पिछले दो दिनों से चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया, जब ईओ दुर्गेश कुमार सिंह के नेतृत्व में पंचायत की टीम बाजार में अतिक्रमण हटाने को पहुंची। बाजार में दुकानदारों ने नाले के ऊपर अपना सामान लगा रखा था कुछ जगह नाले को बंद कर दिया गया था। टीम जब जब शेखर गुप्ता की दुकान पर पहुंची और जेसीबी के जरिए अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया तभी दुकानदार ने विरोध जताते हुए इस कार्यवाही को द्वेषपूर्ण और एकतरफा बताते हुए कुछ व्यापारियों को लक्ष्य में रखकर कार्यवाही करना बताया। इसी दौरान हुई बातचीत बढ़कर वाद विवाद में बदली और फिर हाथापाई तक पहुंच गई। कई व्यापारी एकत्र हो गए और उन्होंने ईओ को पकड़ लिया। कर्मचारी उन्हें छुड़ाने पहुंचे तो व्यापारियों ने उनसे भी झड़प की। पुलिस ने व्यापारियों के चंगुल से ईओ को छुड़ाकर अलग किया। ईओ ओर दुकानदारों के बीच हुई इस हाथापाई के दौरान में मुख्य बाजार में जाम लग गया। सड़क पर जेसीबी और दुकानदारों की भीड़ लगने से वाहनों का आवागमन रूक गया। पुलिस ने सभी को हटाकर रास्ता साफ कराया।

यहां से हटकर कर्मचारियों के साथ ईओ थाने पहुंचे और वहां दुकानदार के खिलाफ तहरीर दी। उनके जाने के बाद दुकानदार अपने साथियों के साथ उन्होंने भी ईओ और कर्मचारियों के खिलाफ तहरीर दी। तहरीर देते समय दोनों पक्ष थाने में मौजूद थे।

मारपीट के दौरान ईओ (नीले कोट में) को पकड़े व्यापारी। ● अमृत विचार

शेरगढ़ में अतिक्रमण हटाने के लिए जेसीबी के आगे खड़े व्यापारी। ● अमृत विचार

● ईओ बोले- काम में बाधा डाली तो होगी कार्रवाई, आज से तेज होगा अभियान

पंचायत कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार

घटना से आक्रोशित नगर पंचायत कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया। कर्मचारियों का कहना है कि यदि ईओ तथा हमारे साथ हुई घटना पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो वे थाने का घेराव करेंगे। ईओ दुर्गेश कुमार सिंह ने कहा कि अतिक्रमण हटाना नगर पंचायत की जिम्मेदारी है। यदि इसमें बाधा डाली जाएगी तो प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बृहस्पतिवार से अतिक्रमण अभियान को तेज किया जाएगा।

फतेहगंज पश्चिमी में भी हुआ था अतिक्रमण हटवाने में विवाद

नवंबर 2025 में फतेहगंज पश्चिमी में भी अतिक्रमण हटाने के दौरान व्यापारी और ईओ के बीच कहासुनी हो गई थी और तब भी दोनों तरफ से थाने में तहरीर दी गई। चार दिसंबर को फतेहगंज पुलिस ने ईओ की तहरीर पर व्यापारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली लेकिन दुकानदार की तहरीर पर कार्रवाई नहीं की। यह मामला जिले से होता हुआ मुख्यमंत्री तक पहुंचा। विधानपरिषद की कमेटी के समक्ष मामला गया। अब भी मामला शांत नहीं हुआ है और ईओ के निलंबन की मांग को मुख्यमंत्री तक पत्र भेजा गया है। अब बुधवार को शेरगढ़ में भी वैसा ही मामला हुआ है। दोनों तरफ से तहरीर दी गई है। अब पुलिस फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है। वरिष्ठ अफसरों की संज्ञान में मामला पहुंच गया है। अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

घर में सो रही किशोरी को दबोचा रिपोर्ट दर्ज

फरीदपुर, अमृत विचार: दुस्साहसी युवक ने किशोरी के घर में घुसकर सो रही किशोरी को दबोच लिया । चीख-पुकार सुनकर परिजनों के जाग जाने पर युवक धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के परिजनों ने पुलिस को बताया कि मंगलवार की रात्रि उनकी पुत्री घर पर ही थी घर के अन्य सदस्य भी सो रहे थे तभी गांव का ही देवेंद्र पुत्र ओमकार उनके घर में घुस आया और किशोरी के बिस्तर पर पहुंचकर उसे बुरी नीयत से दबोच लिय। युवक ने किशोरी के गाल पर बुरी तरह काट लिया जिससे वह चीख पड़ी तो किशोरी का भाई जाग गया। तभी युवक धमकी देते हुए घर से निकलकर भाग खड़ा हुआ। घटना के बाद परिजन किशोरी को लेकर फरीदपुर कोतवाली पहुंचे जहां पुलिस ने किशोरी को मेडिकल परीक्षण हेतु भेज कर परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।

अल्लाह के दरबार से हमेशा बंटता है मोहब्बत का पैगाम

उर्स के जलसे में सैय्यद इकरार मियाँ मकनपुरी को मोमेंटो पेश किया गया।

संवादाता,बहेड़ी

अमृत विचार : मौलाना एहतिसाब क़दीरी ने कहा कि औलिया अल्लाह के दरबार से हमेशा प्यार-मोहब्बत का ही पैगाम बंटा है। इन्होंने बिना किसी भेदभाव के हर किसी के भले की ही दुआ दी है।

मुरादाबाद से आए मौलाना एहतिसाब यहाँ चल रहे उर्स दादा मियाँ के सिलसिले में आयोजित जलसे में ख़िताब कर रहे थे।मशहूर बुज़ुर्ग सैय्यद खुर्शीद मियाँ और सैय्यद ज़हीरुद्दीन मियाँ का यह उर्स दादा मियाँ के उर्स के नाम से मशहूर है। दरगाह दादा मियाँ के सज्जादा नशीन सैय्यद मुजीबुर रहमान ने बताया कि कुल शरीफ के बाद मुल्क में अमन-चैन की दुआ की गई। इस मौके पर सैयद मदरूद्दीन,सैयद इकरार मियाँ, सैयद जियाउर रहमान बाबा मियां,सैयद अजीज मियां,सैयद अयानुद्दीन मियां, मौलाना फरीद अहमद मदारी, मुफ्ती काशिफ, सईद अहमद मदारी,मौलाना नादिर खलीक मदारी आदि रहे।

निरीक्षण में नायब तहसीलदार रहे गैरहाजिर

संवाददाता, आंवला

अमृत विचार: बुधवार को अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) पूर्णिमा सिंह ने तहसील परिसर का निरीक्षण किया। वह देर शाम तहसील पहुंचीं। निरीक्षण की शुरुआत उन्होंने तहसीलदार न्यायालय से की।

निरीक्षण के दौरान एडीएम ने तहसीलदार बृजेश कुमार वर्मा को निर्देश दिए कि सभी कार्य पोर्टल पर ही दर्ज किए जाएं, ऑफलाइन किसी भी प्रकार का कार्य स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने विभागीय कार्रवाई के लिए अलग रजिस्टर बनाने के निर्देश दिए। साथ ही सर्विस रजिस्टर की जांच की और जो अद्यतन नहीं हैं, उन्हें तत्काल अपडेट कराने को कहा।

निरीक्षण के दौरान नायब तहसीलदार दीपक कुमार की अनुपस्थिति पर एडीएम ने नाराजगी जताई। इसके बाद उन्होंने बकायेदारों की स्थिति की समीक्षा की और बड़े बकायेदारों की सूची की फ्लैक्सी लगवाने के निर्देश दिए। एसडीएम विदुषी सिंह ने बताया कि तहसील परिसर में पुताई का कार्य चल रहा है और शीघ्र ही फ्लैक्सी लगवा दी जाएगी।

उन्होंने पट्टों के रजिस्टर को नए कवर में रखने, राजस्व संग्रह से संबंधित फाइलों के समुचित रखरखाव तथा सभी अमीनों की जानकारी ली। निरीक्षण में कोई भी अमीन सबसे पुराने बकायेदार की जानकारी नहीं दे सका। अमीन कार्यालय में वर्ष 2002 की 800 रुपये की आरसी में कमी स्टांप पाए जाने पर उसे रजिस्टर में सही कराने के निर्देश दिए गए। एडीएम ने अमीनों की नियमित मॉनिटरिंग करने, सभी दस्तावेज सर्विस बुक में संलग्न करने तथा समस्त डाटा मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज कराने के निर्देश दिए।

एसडीएम न्यायालय उन्होंने मैनुअल तैयार करने तथा एक माह से अधिक लंबित मामलों को न रखने के निर्देश दिए। साथ ही पूरे तहसील परिसर में साफ-सफाई के कड़े निर्देश दिए गए। एडीएम पूर्णिमा सिंह ने कहा कि निरीक्षण का उद्देश्य किसी भी कर्मचारी को दंडित करना नहीं, बल्कि व्यवस्थाओं को बेहतर बनाना है। निरीक्षण के दौरान जहां भी कमियां पाई गईं, वहां आवश्यक सुधार के निर्देश दिए।

निरीक्षण करती एडीएम पूर्णिमा सिंह

● बड़े बकायेदारों की सूची की फ्लैक्सी लगाने के दिए निर्देश

जमीन बेचने के बहाने हड़पे 19.70 लाख, रिपोर्ट दर्ज

संवाददाता, कैंट

अमृत विचार : जमीन बेचने के नाम पर युवक से 19.70 लाख की रकम हड़प ली। पीड़ित युवक ने कई बार रजिस्ट्री कराने को कहा, जब आरोपियों ने रजिस्ट्री नहीं कराई तो रकम वापस मांगने पर आरोपी टालमटोल करते रहे। पीड़ित ने कैंट थाने में पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।

थाना क्षेत्र के दुबारी निवासी मुकेश कुमार ने बताया, कि उसके गांव का पत्तराम गूंगा बहरा है। इससे वह बहन पूरन देवी पत्नी नंदकिशोर निवासी मगनापुर रजऊ परसपुर थाना बिथरी चैनपुर में रहता है। पत्तराम की दुबारी में जमीन है। जिसमें से 6 बीघा 9 विस्वा जमीन का सौदा चार लाख रुपए प्रति बीघा के हिसाब से मुकेश ने अपने चचेरे बहनोई टीकाराम तथा उसके दामाद नन्हे उर्फ हरपाल निवासीगण ग्राम तुमड़िया थाना आंवला के माध्यम से कुल रकम 26 लाख रुपए में कर लिया। 5 मई से सितंबर 2025 तक कई बार में कभी नगद तो कभी आनलाइन रुपया ट्रांसफर कराया। 10 सितंबर को 1.5 लाख रुपए पूरन देवी तथा नंदकिशोर को नकद देकर मुकेश व उसके तीन अन्य भाइयों ने ढाई-ढाई लाख रूपए चार बार में ऑनलाइन आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांसफर किए। लेकिन नियत तिथि पर रजिस्ट्री करने नहीं आये और 19.70 लाख रुपए हड़प लिए। पीड़ित मुकेश ने टीकाराम, पूरन देवी, नन्हे उर्फ हरपाल, नन्द किशोर तथा पत्तराम समेत पांच लोगों के खिलाफ कैंट थाने में मंगलवार को रिपोर्ट दर्ज कराई है।

● पीड़ित की तहरीर पर पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा

न्यूज डायरी

अवैध रोकटोक से निजात को टेंपो चालकों ने सौंपा ज्ञापन

आंवला, अमृत विचार : टैम्पो चालकों ने टैम्पो में सवारी न बैठने देने समेत विभिन्न गम्भीर आरोप लगाकर एसडीएम आंवला को संबोधित एक ज्ञापन तहसीलदार आंवला बृजेश कुमार को सौंपा है।

टैम्पो चालकों ने बताया कि पुरैना स्टैंड पर कुछ लोग जबरन सवारी नहीं बैठने देते हैं। विरोध करने पर टैम्पो में डंडा मारकर शीशे तोड़ दिए जाते हैं, जिससे टैम्पो चालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। टैम्पो चालकों का कहना है कि उन्होंने टैम्पो लोन पर ले रखे हैं। यदि उन्हें टैम्पो नहीं चलाने दिया गया, तो वे न तो किस्त चुका पाएंगे और न ही अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकेंगे। चालकों ने स्टैंड पर की जा रही दबंगई पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। टैम्पो चालकों ने आरोपितों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई कराने की मांग की, जिससे वे बिना भय के अपने टैम्पो चला सकें। इस दौरान सतेन्द्र पाल, अजय कुमार सिंह, राजीव, छोटू, खिलेंद्र, रामशरण, सुरेश, गब्बर, शिवम, उवैस, संजू, संजीव, सर्वेश, बिजेंद्र, विमल, के .पी., रामवीर, अरविंद, संदीप, सुगम, छेदालाल, मुकेश, कल्लू, छोटे लाल, प्रेमपाल, रामनिवास, महेश, सचिन पाल, आदि मौजूद रहे।

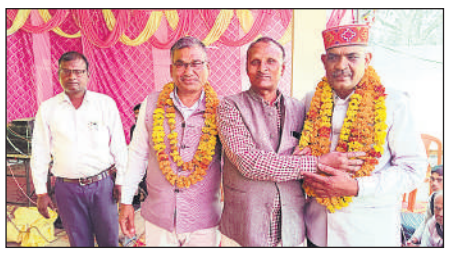

बुद्ध कथा में दिया शांति का संदेश

बरेली, अमृत विचार : सात दिवसीय भव्य बुद्ध कथा का गंगापुर गांव देवचरा में शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि शिशुपाल मौर्य ने फीता काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की। अध्यक्षीय संबोधन में उन्होंने कहा कि बुद्ध के संदेश शांति, करुणा, प्रेम और सद्भावना को बढ़ावा देते हैं तथा समाज में समन्वय और बंधुत्व की भावना मजबूत करते हैं। आयोजन समिति के ब्रजराम मौर्य, मुकेश कुमार मौर्य और यादराम मौर्य ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। कार्यक्रम में क्षेत्र के लोगों की उत्साहपूर्ण भागीदारी रही। आयोजकों ने बताया कि कथा से समाज में सकारात्मक सोच और मानवता के मूल्यों को बढ़ावा मिलेगा।

खामी की वजह से छह घंटे बंद रही सेमीखेड़ा चीनी मिल

देवरनियां, अमृत विचार : किसान सहकारी चीनी मिल की मशीनरी में आई खामी से मिल छह घंटा बंद रही। इससे गन्ना किसानों को खासी दिक्कत का सामना करना पडा। जवाब दे चुकी मशीनरी की वजह से हर गन्ना सीजन में चीनी मिल ठप हो जाती है। बुधवार को मशीनरी में खामी से मिल करीब छह घंटे ठप रही। इस बीच मिल यार्ड में गन्ना किसान और गन्ना लदे वाहनों की भीड जमा रही है। मिल प्रबंधन के मुताबिक खामी को दूर कर लिया गया है।

आंवला में अतिक्रमण करने वालों का सामान किया जब्त

आंवला, अमृत विचार : नगर में व्यापारी संगठनों की मांग पर बुधवार को नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान के तहत वजीरगंज रोड से पक्का कटरा मेन मार्केट होते हुए स्टेट बैंक तथा सरगम टॉकीज तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। पालिका के अधिशासी अधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि अभियान के दौरान सड़क पर अतिक्रमण कर रखी गई पॉलिथीन, 500 लीटर की पानी की टंकी तथा बीच सड़क पर खड़े चार ई-रिक्शा जब्त किए गए। साथ ही संबंधित लोगों पर जुर्माने की कार्रवाई भी की गई। अधिशासी अधिकारी ने व्यापारियों से अपील की कि वे सड़क पर अतिक्रमण न करें और यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। अतिक्रमण हटाओ अभियान में राजस्व निरीक्षक पवन कुमार सिंह, रणजीत सिंह मौर्य, अनिल कुमार मौर्य, संजीव मौर्य, समस्त सफाई नायक सहित नगर पालिका के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।

तीसरे दिन पूरी तरह कब्जा मुक्त हो पाई नहर भूमि

संवाददाता, सेंथल

अमृत विचार: नहर की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए अवैध स्विमिंग पूल को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए तीसरे दिन भी कार्रवाई चली। सिंचाई विभाग के अफसरों ने दिन में कार्यवाही करते हुए नहर की भूमि को पूरी तरह अतिक्रमण से मुक्त करा लिया है। आठ साल पहले जब नहर की भूमि पर चहारदीवारी बनाकर स्वीमिंग पूल बनाने की तैयारी की गई थी उस दौरान विभागीय अफसरों के संज्ञान में मामला आया था लेकिन तब अफसरों ने राजनीतिक दबाववश अतिक्रमण हटाने के लिए खानापूर्ति की और शांत हो गये। तत्कालीन अधिशासी अभियंता विभाग को केवल नोटिस देने तक ही सीमित रहे और इस तरह विभाग की भूमि आठ साल तक अवैध कब्जे की गिरफ्त में रही।

सोमवार को मजिस्ट्रेट और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में 6 घंटे तक बुलडोजर चलाकर स्विमिंग पूल के अवैध हिस्से पर कार्रवाई की गई थी। उस दौरान दीवार के पिलर नहीं तोड़े जा सके थे। बुधवार को सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने इन पिलरों को भी तुड़वा दिया।

● आठ साल पहले सिंचाई विभाग केवल नोटिस देने तक सीमित रहा

हजरत इलाही बख्श मियां का उर्स सम्पन्न

मीरगंज, अमृत विचार: कस्बा शाही के मोहल्ला हसनपुर (नूरी नगर) में हजरत इलाही बख्श मियां रहमतुल्लाह अलैह का पांच दिवसीय वार्षिक उर्स अकीदत और उल्लास के साथ सम्पन्न हो गया। बुधवार को आयोजित समापन कार्यक्रम में कस्बे सहित आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए और दरगाह पर हाजिरी देकर दुआएं मांगीं। उर्स के दौरान दरगाह परिसर में रूहानी माहौल छाया रहा।

अकीदतमंदों ने चादरपोशी की और मुल्क में अमन-चैन, खुशहाली और भाईचारे की दुआ की। शाम होते ही महफिल-ए-कव्वाली का दौर शुरू हुआ, जिसने पूरी फिजा को सूफियाना रंग में रंग दिया।

हिन्दू सम्मेलन से पहले नगर में निकाली बाइक रैली

संवाददाता, फतेहगंज पूर्वी

अमृत विचार : गुरुवार को नगर में होने वाले हिंदू सम्मेलन से पूर्व आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को बाइक रैली रैली निकाली। रैली बदायूं-दातागंज मार्ग स्थित सरस्वती विद्या मंदिर से प्रारंभ हुई और नगर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी।

आरएसएस के नेतृत्व में स्वयंसेवक अनुशासित पंक्तियों में पथ संचलन करते हुए आगे बढ़े। सभी कार्यकर्ता निर्धारित गणवेश में, मस्तक पर चंदन तिलक और हाथों में दंड (लाठी) लिए नजर आए। दर्जनों कार्यकर्ता मोटरसाइकिल पर सवार होकर रैली में शामिल हुए। कार्यकर्ताओं की मोटरसाइकिलों पर हिंदू धर्म ध्वजाएं भी लहराती दिखाई दीं हेलमेट लगाए युवा जोश और अनुशासन के साथ नगरवासियों का ध्यान आकर्षित करते रहे थे।

कार्यकर्ताओं ने नगरवासियों से अपील की कि वे गुरुवार को रामलीला मैदान में आयोजित हिंदू सम्मेलन में बढ़-चढ़कर भाग लें। आयोजक पवन राज मिश्रा, ऋषभ मिश्रा , सुधीर सिंह, राजेंद्र गुप्ता, रमेश वर्मा, उत्तम शंखधार ,मनीष चंद शर्मा, आदि रहे।

हिंदू सम्मेलन कल निकाली बाइक रैली

आंवला, अमृत विचार : विराट हनुमत शक्ति सम्मेलन समिति के नेतृत्व मे भव्य बाइक रैली निकाली गई जिसमें सैकड़ों बाइक सवारों के साथ विभिन्न स्थानों पर रुक-रुक कर गुरुवार को होने वाले विराट हिन्दू सम्मेलन में सहभागिता निभाने के लिए आवाहन किया गया। समिति की अध्यक्ष ऊषा सतीजा, नगर प्रचारक हेमन्त कुमार, संजय अग्रवाल, दुर्गेश सक्सेना, विमल त्रिपाठी,विपिन सिंह, सत्यवीर सिंह, रामवीर प्रजापति, वैभव शर्मा, अभय चौहान, जयदीप पाराशर, शैलेन्द्र सिंह,आदि रहे।

शेयर मार्केट में पैसा लगाने के नाम पर 93 हजार ठगे

बरेली, अमृत विचार : शेयर मार्केट में पैसा लगाने के नाम पर युवक 93 हजार रुपये ठग लिए गए।सीबीगंज पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। सीबीगंज थाना क्षेत्र के अटरिया गांव निवासी रमेश अवस्थी ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति ने टेलीग्राम पर शेयर मार्केटिंग में पैसा इनवेस्ट करने के बाद अच्छे मुनाफे का झांसा दिया। 23 अक्टूबर 2025 को उनके खाते से कई बार में 93 हजार रुपये कट गए। इसके बाद उन्हें ठगी का एहसास हुआ। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

ड्यूटी से लौट रहे युवक पर जानलेवा हमला

भोजीपुरा, अमृत विचार : अटटापट्टी जनूबी गांव निवासी वसीम ने दी तहरीर में बताया कि 9 फरवरी की शाम वह ड्यूटी से घर लौट रहे थे। रास्ते में गांव के ही शाहिद, शोएब, गुड्डू और शैफू ने उन्हें घेर लिया और लाठी-डंडों से मारपीट की। हमलावर उसके घर में भी घुस आए और उसकी बहन के साथ मारपीट की।

मैरिज हाल के सामने खड़ी कार में लगी आग

संवादाता, बहेड़ी

अमृत विचार : शहर के बीचो-बीच एक मैरिज हाल के सामने खड़ी एक कार में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने आसपास खड़ी दो और कारों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग की ऊँची लपटों के साथ उठे धुएं के गुबार को देखकर लोगों की भीड़ लग गई। सूचना पर पहुँची फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई।

शहर में पंजाबी कॉलोनी से होली चौराहा को जाने वाली सड़क पर स्थित मैरिज हाल के सामने आबपाशी कोठी की बाउंड्री के करीब खाली जगह में लोग गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। आज दिन में 2:30 बजे के करीब यहाँ खड़ी अकील अहमद उर्फ हकीम जी की एक्सयूवी कार में अचानक आग लग गई। आग ने बगल में खड़ी आज़म और शकील सेठ की कारों को अपनी चपेट में ले लिया। तीनों गाड़ियां धूँ धूँ कर जलने लगीं। आग देख लोग वहां जमा हो गए। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड के पहुँचने तक गाड़ियों से आग की लपटे ऊँची ऊँची उठ रही थीं। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुँच कर आग बुझाई।

आग की चपेट में आईं तीन कारों के पास एक और कार भी खड़ी थी, मगर उसके मालिक ने आकर कार को निकाल लिया। कुछ देर और लगती तो वह भी आग की चपेट में आ जाती। आग कैसे लगी, इस बात की जानकारी सामने नहीं आ पाई है।

कार से उठतीं लपटें। ● अमृत विचार

न्यूज ब्रीफ

गंगनहर में डूबा एमबीए द्वितीय वर्ष का छात्र

हरिद्वार। रुड़की में बुधवार को आईआईटी रुड़की के एमबीए द्वितीय वर्ष का छात्र आशीष शुक्ला (निवासी बनारस) डूबकर लापता हो गया। आशीष अपने दोस्तों के साथ नगर निगम पुल के पास गंगनहर किनारे घूमने गया था। नहर के पास अचानक पैर फिसलने से वह तेज बहाव में जा गिरा और देखते ही देखते नहर के पानी में लापता हो गया। दोस्तों ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुलाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी।

पीटीआर में वृद्धा का मिला क्षतविक्षत शव

पीलीभीत, अमृत विचार : पीलीभीत टाइगर रिजर्व की महोफ रेंज में बुधवार सुबह एक बुजुर्ग महिला का क्षत विक्षत शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला के गले और पेट में गहरा घाव के निशान पाए गए। घटना की जानकारी लगते ही ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सूचना पर वन विभाग की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। महिला की मौत वन्यजीव के हमले में होना पाया गया है। फिलहाल महिला की मौत जंगल में हुई है या फिर वन्यजीव उसे उठाकर जंगल में ले गया।

बालगृह में रहने वाले नाबालिगों की जाति, धर्म के उल्लेख पर आपत्ति

हाईकोर्ट ने अधिकारियों से तलब किया स्पष्टीकरण

विधि संवाददाता, प्रयागराज

अमृत विचार : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग बच्चों को राजकीय बालगृह में रखे जाने के दौरान उनके अभिलेखों में जाति एवं धर्म के उल्लेख के मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निदेशालय के निदेशक और सचिव से यह पूछा था कि क्या राजकीय बालगृह में रह रहे नाबालिगों के परामर्शदाताओं और जिला परिवीक्षा अधिकारी के कार्यालय द्वारा तैयार किए गए अभिलेखों में जाति और धर्म का उल्लेख आवश्यक है। इस विषय पर कोर्ट ने पूर्व में पारित आदेशों के आलोक में महिला कल्याण निदेशालय और राज्य सरकार के अधिकारियों से विस्तृत स्पष्टीकरण तलब किया।

- राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया जानकारी गोपनीय रखी जाती है

निदेशक एवं सचिव, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर न्यायालय की सहायता करने का निर्देश दिया गया। राज्य सरकार की ओर से अवगत कराया गया कि विभागीय अभिलेखों में संकलित जानकारी गोपनीय रखी जाती है और उसका उपयोग केवल पुनर्वास उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

बता दें कि नाबालिग सुनीता व अन्य द्वारा दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकलपीठ ने बाल गृह में रखे जाने वाले नाबालिगों के विवरण में जाति एवं धर्म के उल्लेख पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सरकार व आयोग से जवाब तलब किया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट के पूर्व आदेशों के अनुपालन में नाबालिग को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कोर्ट ने यह पाया कि बालिका को कौशल उन्नयन, परामर्श एवं मनोवैज्ञानिक सहायता की आवश्यकता है, जिससे वह अपने भविष्य के संबंध में उचित निर्णय ले सके। इस संबंध में जिला प्रोबेशन अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर 'इंडिविजुअल केयर प्लान' प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिया गया।

मामले की अंतिम सुनवाई यानी 3 फरवरी 2026 को राज्य की ओर से यह सूचित किया गया कि नाबालिग वर्तमान में अपने भाई की सुरक्षित अभिरक्षा में है, साथ ही राज्य सरकार द्वारा अधिनियम, में संशोधन हेतु सुझाव केंद्र सरकार को प्रेषित किए जाने की जानकारी भी दी गई। उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर कोर्ट ने माना कि अब याचिका लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है। अतः याचिका को निस्तारित कर दिया।

लालकुआं-राजकोट ट्रेन 1 मार्च से चलेगी

हल्द्वानी, अमृत विचार : होली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए लालकुआं–राजकोट–लालकुआं साप्ताहिक होली विशेष गाड़ी चलाने की घोषणा की है। यह विशेष ट्रेन मार्च में कुल पांच फेरों के लिए चलाई जाएगी, जिससे उत्तराखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। लालकुआं–राजकोट साप्ताहिक होली विशेष गाड़ी 1 से 29 मार्च तक प्रत्येक रविवार को लालकुआं से दोपहर 12:35 बजे चलेगी।

यह ट्रेन किच्छा, बहेड़ी, भोजीपुरा, इज्जतनगर, बरेली सिटी, बरेली जंक्शन, बदायूं, सोरो, कासगंज, हाथरस सिटी, मथुरा कैंट, मथुरा जंक्शन, भरतपुर, दौसा, जयपुर, फुलेरा, नावा सिटी, कुचामन सिटी, मकराना, डेगाना, मेड़ता रोड, गोटन, जोधपुर, लूनी, समदड़ी, मोकलसर, जालोर, मोदरान, मारवाड़ भीनमाल, रानीवाड़ा, धनेरा, भीलड़ी, पाटन, महेसाणा जंक्शन, वीरमगाम, सुरेंद्रनगर और वांकानेर जंक्शन होते हुए अगले दिन शाम 6:10 बजे राजकोट पहुंचेगी। वापसी में यह स्पेशल ट्रेन 2 से 30 मार्च तक प्रत्येक सोमवार को राजकोट से रात 10:30 बजे प्रस्थान करेगी।

खेत में दवा छिड़कने के दौरान किसान की मौत

जैतीपुर/शाहजहांपुर, अमृत विचारः आलमपुर गांव में एक किसान खेत पर फसल में कीटनाशक दवा छिड़क रहा था। दवा छिड़कते समय किसान बेहोश हो गया। परिवार वाले खेत पर पहुंचे और उसे मेडिकल कालेज लेकर आए। इलाज के दौरान किसान की मौत हो गयी।

जैतीपुर थाना क्षेत्र के गांव आलमपुर निवासी 40 वर्षीय अमोल मंगलवार की दोपहर बाद खेत पर फसल में कीटनाशक दवा का छिड़काव कर रहे थे। दवा छिड़कते समय किसान बेहोश हो गए। परिवार वाले खेत पर पहुंचे और उसे लेकर सीएचसी पर गए। जहां डॉक्टर ने मेडिकल कालेज के लिए रेफर कर दिया। परिजन रात में उसे मेडिकल कालेज लेकर आए। जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी। परिजनों ने बताया कि उनके पास एक बीघा खेत था।

दीवार गिरी, दंपती की मौत

धौरहरा, अमृत विचार : शारदा नगर थाना क्षेत्र के गांव लौखनिया में बुधवार तड़के टीनशेड का लकड़ी का पिलर टूटने से टीन सहित पक्की दीवार भरभराकर ढह गई। मलबे के नीचे दबने से चारपाई पर सो रहे बुजुर्ग दंपति और उनकी दो पोतियां घायल हो गईं। घायलों को सीएचसी रमियाबेहड़ ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने वृद्धा को मृत घोषित कर दिया। जबकि उसके पति ने लखनऊ जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया।

किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, सम्पूर्णानगर, जिला-खीरी

ई-निविदा सूचना

मिल समिति में वर्ष 2025-26 में Supply of PM Analyzer Sensor Etc. से सम्बन्धित ई-बिड निविदायें दिनांक 11.02.2026 से दिनांक 18.02.2026 को सायंकाल 6:55 बजे तक आमंत्रित की गयी है। उक्त निविदायें www.etender.up.nic.in एवं www.upsugarfed.org पर देखी जा सकती है।

प्रधान प्रबन्धक

पूर्वोत्तर रेलवे

ई-निविदा सूचना : ओटी-18-2025

उप मुख्य विद्युत इंजीनियर / निर्माण, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित कार्यो के लिये ''खुली'' निविदा आमंत्रित की जाती है। **निविदा सं०:-** ओटी-18-2025, **कार्य का विवरणः-** कुसुम्ही-गोरखपुर- डोमिनगढ़ तीसरी लाइन और गोरखपुर- नकहा दोहरीकरण परियोजना के अन्तर्गत गोरखपुर में 25 केवी, 50 हट्र्ज, सिंगल फेज, एसी नए स्विचिंग पोस्ट (एसएसपी) का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं कमीशनिंग का कार्य। **अनुमानित लागतः-** रु. 1,48,35,483.35, **बयाना राशिः-** रु. 2,24,200.00, **निविदा प्रपत्र का मूल्य** - रु निल, **कार्य पूर्ण करने की अवधि** - 06 माह, **निविदा बन्द होने की अंतिम तिथि व समयः** 05.03.2026 को 15.00 बजे।, **नोटः** • इस निविदा के विरुद्ध कोई मैनुअल आफर स्वीकार नहीं किया जायेगा। ऐसे प्राप्त मैनुअल आफर को उपेक्षित कर दिया जायेगा। विस्तृत विवरण व निविदा जमा करने हेतु कृपया भारतीय रेलवे की वेबसाइट **www.ireps.gov.in** को देखें।, • निविदा सूचना में यदि हिन्दी या अंग्रेजी के आलेखों में कोई भिन्नता होती है तो अंग्रेजी के ही आलेख मान्य होगें।

उप मुख्य विद्युत इंजीनियर/निर्माण, गोरखपुर

मुजाधि/विद्युत-277

ट्रेनों में बीड़ी/सिगरेट न पियें

मशीन की बेल्ट में फंसकर कर्मचारी की मौत

मुरादाबाद, अमृत विचार : सिविल लाइन कोतवाली के अगवानपुर स्थित दीवान शुगर मिल में मंगलवार देर रात एक कर्मचारी की काम करने के दौरान मशीन की चेन बेल्ट में फंसकर मौके पर ही मौत हो गई। कर्मचारी के परिवार वालों ने प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया। भाई के अनुसार मंगलवार की रात 12 बजे अरविंद बेल्ट की चेन के पास कार्य कर रहा था तभी मशीन में फंस गया।

लूटपाट, हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद

कार्यालय संवाददाता, बदायूं

- बदायूं में 14 अक्टूबर 2018 की शाम नौकर ने अपने साथियों की मदद से की थी हत्या

अमृत विचारः शहर के उमेश जनरल स्टोर के मालिक की पत्नी की उनके ही नौकर और दो सहयोगियों ने लूट करके हत्या की थी। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र रिंकू ने तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 80-80 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा उमेश चंद्र रस्तोगी पुत्र स्व. कृष्ण कांति स्वरूप ने कोतवाली सिविल लाइन पुलिस को 14 अक्टूबर 2018 को तहरीर दी। जिसमें बताया कि उनकी पत्नी अरुणा रस्तोगी घर पर अकेली थी। बेटा नितिन और बहू पूजा एक समारोह में शामिल होने के लिए कासगंज के आगे मारहरा गए थे। उमेश चंद्र नौकरों के साथ दुकान पर थे। शाम लगभग छह बजे उनके घर पर काम करने वाली महिला प्रिया घर पर पहुंची। पत्नी को घर के फर्श पर घायल अवस्था में तपड़ते देखा तो बेटे और पुत्रवधू को फोन करके सूचना दी। उमेश चंद्र तुरंत घर पहुंचे तो उनकी पत्नी रसोइघर में खून से लथपथ पड़ी थीं। उनकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। इस दौरान घर के नौकर शिवम मौर्य और उसके साथ सोनू मौर्य व दिलीप मौर्य के नाम सामने आए। पुलिस ने 15 अक्टूबर को शिवम मौर्य और उसके साथियों की निशानदेही पर सोनू के मकान के कमरे के संदूक से एक काले रंग का बैग बरामद किया। जिसमें 20 लाख रुपये बरामद हुए। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू और जले हुए कपड़े बरामद किए।

न्यायालय में सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के गांव खेड़ा बुजुर्ग निवासी शिवम मौर्य पुत्र राधेश्याम मौर्या, दिलीप मौर्य पुत्र राम किशोर, सोनू मौर्य पुत्र सुरेश मौर्य पर लूटपाट और हत्या करने के आरोप का मुकदमा चलाया गया।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, बदायूँ।

ऑनलाइन ई-निविदा आमंत्रण सूचना

No. : 166 / Nivida(E-T.)/ 2025-26 **Date : 05-02-2026**

1. महामहिम राज्यपाल, उ0 प्र0 की ओर से अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोनिवि बदायूँ के अन्तर्गत निम्न तालिका में अंकित विवरण के अनुसार ऑनलाइन ई-निविदा दि0 13.02.2026 से दि0 19.02.2026 की दोपहर 12.00 बजे तक आमंत्रित की गयी हैं:-

2.

Sr. No.	District	Name of work	Estimated cost (in Rs. Lacs)	Bid Security (in Rs.lac)	Cost of Bid Document (Rs.)	Time of completion	Address of Executive Engineer Executing the work	Address of Superintending Engineer	Address of Chief Engineer	Eligible category of Contractor
1	2	3	0	5	6	7	8	9	10	11
1	Budaun	वर्ष 2024-25 में विधानसभा क्षेत्र बिसौली के अन्तर्गत पड़ने वाले ग्रामीण मार्गो पर गडढा मुक्ति एवं पैच मरम्मत का कार्य।	32.10	3.21	Tender Cost+ Stationery Charges+ GST Rs.944.00	Four Month	C.D. P.W.D., Budaun	Budaun-Pilibhit Circle, P.W.D. Bareilly	Bareilly Zone P.W.D., Bareilly	A,B,C,D
2	Budaun	वर्ष 2024-25 में विधानसभा क्षेत्र बिसौली के अन्तर्गत पड़ने वाले राज्य मार्ग/अजिमा पर गडढा मुक्ति एवं पैच मरम्मत का कार्य।	30.40	3.04	Tender Cost+ Stationery Charges+ GST Rs.944.00	Four Month	C.D. P.W.D., Budaun	Budaun-Pilibhit Circle, P.W.D. Bareilly	Bareilly Zone P.W.D., Bareilly	A,B,C,D
3	Budaun	वर्ष 2024-25 में विधानसभा क्षेत्र सहसवान के अन्तर्गत पड़ने वाले ग्रामीण मार्गो पर गडढा मुक्ति एवं पैच मरम्मत का कार्य।	28.70	2.87	Tender Cost+ Stationery Charges+ GST Rs.944.00	Four Month	C.D. P.W.D., Budaun	Budaun-Pilibhit Circle, P.W.D. Bareilly	Bareilly Zone P.W.D., Bareilly	A,B,C,D
4	Budaun	वर्ष 2024-25 में विधानसभा क्षेत्र सहसवान के अन्तर्गत पड़ने वाले राज्य मार्ग मार्गो पर गडढा मुक्ति एवं पैच मरम्मत का कार्य।	32.60	3.26	Tender Cost+ Stationery Charges+ GST Rs.944.00	Four Month	C.D. P.W.D., Budaun	Budaun-Pilibhit Circle, P.W.D. Bareilly	Bareilly Zone P.W.D., Bareilly	A,B,C,D
5	Budaun	वर्ष 2024-25 में राज्य मार्ग/अन्य जिला मार्ग एवं ग्रामीण मार्गों पर गडढा मुक्ति एवं पैच मरम्मत हेतु बिसौली स्थित विभागीय हॉट मिक्स प्लाण्ट पर ग्रिट आपूर्ति का कार्य।	28.70	2.87	Tender Cost+ Stationery Charges+ GST Rs.944.00	Four Month	C.D. P.W.D., Budaun	Budaun-Pilibhit Circle, P.W.D. Bareilly	Bareilly Zone P.W.D., Bareilly	A,B,C,D

3- बिड डाक्यूमेन्ट वेबसाइट http://etender.up.nic.in. पर दिनांक 13.02.2026 से 19.02.2026 तक उपलब्ध है, निविदाये दिनांक 19.02.2026 को दोपहर 12.00 बजे तक अपलोड की जा सकती हैं। इसकी तकनीकी बिड दिनांक 19.02.2026 को दोपहर 12.30 बजे खोली जायेगी।

निविदा से सम्बन्धित अधिक जानकारी वेबसाइट http://etender.up.nic.in पर उपलब्ध है।

UP - 245765 दिनांकः 10/02/2026
विज्ञापन वेबसाइट www.up.gov.in पर उपलब्ध है।

(देवपाल सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि., बदायूँ।

कार्यालय ग्राम पंचायत ढकनी रजपुरी वि.खं. भुता बरेली

पत्रांकः 108/लेखा/निविदा/वर्ष 2025-26 दिनांकः 08.01.2026

अल्पकालीन निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत ढकनी रजपुरी में मनरेगा योजना के अन्तर्गत मुकेश पन्डित के घर से हरप्रसाद के घर तक सी.सी. रोड व नाली निर्माण कार्य होना है। जिसकी लागत 2.50 लाख है। इच्छुक फर्म सीमेन्ट, बजरफुट, बजरी, रेता, प्रथम ईट, रोड़ा आदि आपूर्ति हेतु दिनांक 17.02.2026 तक निविदा आमंत्रित की जाती है। जिन्हें कार्यालय ग्राम पंचायत में दिनांक 18.02.2026 तक जमा कर सकते हैं। जिन्हें उसी दिन शाम 4 बजे खोला जायेगा। जिस फर्म का टेन्डर सबसे कम दर का होगा उसे स्वीकार किया जायेगा।

नरेन्द्र कुमार, प्रधान — अजेय यादव, सचिव

कार्यालय ग्राम पंचायत सिठौरा वि.खं. भदपुरा (बरेली)

निविदा आमंत्रण सूचना दिनांक : 12.02.2026

समस्त अधिकृत फर्मो व विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत सिठौरा में मनरेगा योजना के अन्तर्गत निम्न निर्माण हेतु सामग्री आपूर्ति हेतु पंजीकृत फर्मो से निविदा आमंत्रित की जाती है। सामग्री विवरण निम्नवत् है। ईट, बजरफुट, सरिया, सीमेंट, रेज, बजरी व अन्य सामग्री जो प्राक्कलन में लिखित है। निविदा पंचायत कार्यालय पर दिनांक 12.02.2026 से 14.02.2026 तक किसी समय खोली जा सकती है। कार्य हेतु सामग्री आपूर्ति आदि की सूचना किसी कार्यालय दिवस में देखी जा सकती है।

क्र.सं.	कार्य का नाम	माप	अनु. लागत
1.	पूरनलाल की बैठक से नहर तक सी.सी. रोड व पक्की नाली निर्माण	95x4 मीटर	2,86,500.00

अभिषेक सिंह-सचिव — वीरवती-ग्राम प्रधान

क्षेत्रीय कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स
193-ए, सिविल लाइन्स, बरेली मण्डल, बरेली

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री कृष्ण पाल सिंह द्वारा अध्यक्ष की हैसियत से करन सिंह मैमोरियल पब्लिक शिक्षा समिति, ग्राम महताबपुर पो. खास तह. दातागंज जिला बदायूं का नाम परिवर्तन कर संस्था का नया नाम करन सिंह मैमोरियल संस्कृत पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति, ग्राम महताबपुर पो. खास तह. दातागंज जिला बदायूं करने हेतु प्रपत्र प्रस्तुत किये गये है। वर्तमान में प्रबन्धकारिणी समिति की सूची में निम्नलिखित पदाधिकारी/सदस्य है-

क्र.सं.	नाम/पिता/पति का नाम	पद
1.	श्री कृष्णपाल सिंह पुत्र श्री करन सिंह	अध्यक्ष
2.	श्री शिवओम पुत्र श्री कृष्णपाल सिंह	उपाध्यक्ष
3.	श्री राजकपूर उर्फ अभिषेक पुत्र श्री देवेन्द्र पाल	प्रबन्धक
4.	श्री पप्पू सिंह पुत्र श्री कृष्णपाल सिंह	कोषाध्यक्ष
5.	श्री रानी पत्नी श्री कृष्णपाल	सदस्य
6.	श्रीमती आरजू पत्नी श्री राजकपूर उर्फ अभिषेक	सदस्य
7.	प्रियंका पुत्री श्री रविकान्त	सदस्य

उपरोक्त संस्था का नाम परिवर्तन किये जाने में यदि सम्मानित पदाधिकारी/सदस्य को कोई आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिनों के अन्दर फोटोयुक्त नोटरीशपथ पत्र के माध्यम से आपत्ति पत्र अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि उक्त निर्धारित अवधि में किसी की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो यह समझा जायेगा कि किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तत् उपरान्त आपत्ति के अभाव में एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जायेगी जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी भू.पू./वर्तमान पदाधिकारी/सदस्यों की होगी। उपरोक्त सार्वजनिक सूचना/नोटिस सोसा. रजि. एक्ट 1860 की धारा-4 के अन्तर्गत जारी की जा रही है।

सहायक रजिस्ट्रार, बरेली।

पूर्वोत्तर रेलवे ई-ऑक्शन सूचना

सं. सी/54/खानपान/ई ऑक्शन दिनांक 10.02.2026

वरि. मंडल वाणिज्य प्रबन्धक/इज्जतनगर द्वारा आई.आर.ई.पी.एस. (IREPS) पर पंजीकृत संस्थाओं से ई-ऑक्शन के माध्यम से खानपान ठेकों हेतु बोलियाँ आमंत्रित की जा रही हैं। ऑक्शन कैटलाग को आई.आर.ई.पी.एस. (IREPS) की वेबसाइट www.ireps.gov.in पर प्रकाशित किया जा चुका है। इज्जतनगर मंडल की आगामी ई-ऑक्शन का विवरण निम्नवत है-

श्रेणी	कैटलॉग सं.	ऑक्शन प्रारंभ	ऑक्शन समापन
खानपान	IZN-CAT-26-01	20.02.26/12:00:00	20.02.26/13:50:00

क्रम	स्टेशन	स्टेशन कोड	श्रेणी	ऑक्शन के लिए इकाई	चिन्हित इकाई	प्लेटफार्म सं.
01	गंजडुंडवारा	GWA	डी	जीएमयू/स्टाल	अनारक्षित	01
02	कमालगंज	KLJ	डी	जीएमयू/स्टाल	अनारक्षित/महिला	01
03	सिकंदराराउ	SKA	डी	जीएमयू/स्टाल	अनारक्षित	01
04	रुदायन	RDN	डी	जीएमयू/स्टाल	अनारक्षित	01
05	फतेहगढ़	FGR	डी	जीएमयू/स्टाल	अनारक्षित	01
06	निगोही	NOH	ई	जीएमयू/स्टाल	अनारक्षित	01
07	कम्पिल रोड	KXF	ई	जीएमयू/स्टाल	अनारक्षित/महिला	01
08	उझानी	UJH	डी	एसएमयू/स्टाल	अन्य पिछड़ा वर्ग	01
09	पीपलसाना	PLS	ई	एसएमयू/स्टाल	अन्य पिछड़ा वर्ग	01

1. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि ई-ऑक्शन से सम्बन्धित जानकारी के लिए रेलवे की वेबसाइट www.ireps.gov.in देखें। 2. उक्त ई-ऑक्शन, आई.आर.ई.पी.एस. (IREPS) के ई-ऑक्शन लीजिंग मॉड्यूल के माध्यम से आमंत्रित किया गया है। 3. ई-ऑक्शन संबंधित समस्त जानकारी जैसे पात्रता, कार्य का दायरा, ठेके की अवधि, नियम एवं शर्तें आदि आई.आर.ई.पी.एस. (IREPS) की वेबसाइट www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है। 4. बोलीदाता उक्त दिये गये दिनांक एवं समय के अनुसार ही ई-ऑक्शन में भाग ले सकते हैं। 5. सभी संभावित बोलीदाताओं से अनुरोध है कि ई-ऑक्शन से संबंधित किसी भी शुद्धिपत्र हेतु नियमित रूप से रेलवे की वेबसाइट www.ireps.gov.in का अवलोकन करते रहें।

मुजाधि/वाणिज्य-257 — सहायक वाणिज्य प्रबन्धक/इज्जतनगर

गाड़ियों की छतों व पायदान पर कदापि यात्रा न करें

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में उसका फूफा गिरफ्तार

अमेठी, एजेंसीः जिले में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में उसके फूफा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों ने बुधवार को बताया कि जिले के पीपरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक महिला ने गत 22 जनवरी को थाने में शिकायत दी थी कि उसकी 17 वर्षीया बेटी एक व्यक्ति के साथ चली गयी है। इस पर पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी। उन्होंने बताया कि प्राथमिक जांच में मोबाइल कॉल विवरण के आधार पर कई लोगों को जांच के दायरे में शामिल किया गया। बाद में पुलिस ने मंगलवार को लड़की को सुलतानपुर के रहने वाले उसके फूफा संदीप कुमार के पास पाया। संदीप कुमार को भारतीय न्याय संहिता तथा बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया।

थाईलैंड की राजकुमारी ताजमहल का दीदार करने पहुंचीं आगरा

आगरा, एजेंसीः थाईलैंड की राजकुमारी सिरिवन्नवारी नारीरत्ना बुधवार को ताजमहल का दीदार करने के लिए आगरा पहुंचीं। सुबह करीब आठ बजे डेलिगेशन के साथ ताजमहल में पहुंचीं और ताजमहल में करीब डेढ़ घंटे तक रहीं। इस मौके पर उन्होंने फोटो शूट भी कराया। गाइड से ताजमहल के इतिहास के बारे में जानकारी ली। ताजमहल देखने के बाद आगरा किला भी गईं। उन्होंने भारी सुरक्षा के बीच आगरा का दौरा किया।

गाजियाबाद में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़

गाजियाबाद, एजेंसी

- पुलिस ने 11 महिलाओं को हिरासत में लिया

गाजियाबाद जिला के कौशांबी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि क्षेत्र के एक निजी बड़े होटल में लंबे समय से देह व्यापार का अवैध धंधा संचालित किया जा रहा है। पुलिस द्वारा कार्यवाई के संबंध में बुधवार को जानकारी दी गई। पुलिस ने बताया कि सूचना के आधार पर थाना कौशांबी पुलिस टीम ने योजनाबद्ध तरीके से होटल में छापा मारा। छापेमारी के दौरान मौके से 11 महिलाओं को हिरासत में लिया गया, जबकि होटल प्रबंधन और रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

पुलिस द्वारा जांच पड़ताल में सामने आया कि होटल में बाहरी राज्यों से महिलाओं को बुलाकर देह व्यापार कराया जा रहा था। मौके से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद होने की सूचना है। सभी हिरासत में ली गई महिलाओं से पूछताछ की जा रही है और उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। थाना कौशांबी पुलिस का कहना है कि मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। होटल संचालक और रैकेट के मास्टरमाइंड के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है, ताकि इस अवैध धंधे से जुड़े सभी लोगों को कानून के शिकंजे में लाया जा सके।

उत्तराखंड में ड्रग मुक्ति मुहिम को नया ढांचा

देहरादून, अमृत विचारः मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में जहां नशे के खिलाफ निर्णायक जंग की मुहिम को नया आकार दिया गया तो दो विभागों में 116 पदों के सृजन को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट ने छह प्रस्तावों पर मुहर लगायी है।

सीएम ने इस अवसर पर कहा कि, राज्य के समग्र विकास, प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण, कर्मचारी हितों के संरक्षण तथा कानून-व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की दृष्टि से राज्य कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श कर आवश्यक निर्णय लिए गए।

देहरादून में गैस एजेंसी के स्वामी की दिनदहाड़े हत्या

मुख्य संवाददाता, देहरादून

- पारिवारिक व करीबी से 42 करोड़ रुपये का संपत्ति विवाद आया सामने

अमृत विचारः देहरादून में बुधवार को तिब्बती मार्केट के पास स्कूटी सवार दो शूटरों ने अमरदीप गैस एजेंसी के मालिक अर्जुन शर्मा (42) की सीने में गोली मारकर हत्या कर दी। प्रारंभिक जांच में इस घटना के पीछे पारिवारिक व 42 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का विवाद सामने आया है। अर्जुन की पत्नी ने सास सहित 4 पर डालनवाला थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी है।

एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि बसंत विहार निवासी अर्जुन सुबह करीब 10:30 बजे परेड ग्राउंड में टेनिस खेलने के बाद अपनी कार में बैठने जा रहे थे। तिब्बती मार्केट के मंदिर के पास स्कूटी सवार दो बदमाशों ने उन्हें घेरकर नजदीक से गोली मार दी और फरार हो गए। एसपी के अनुसार, अर्जुन के परिवार में विवाद था और इसी कारण उनकी मां ने हाईकोर्ट से यह हवाला देते हुए सुरक्षा हासिल की थी कि उन्हें अपने बेटे से जान का खतरा है। इसी बीच, अर्जुन की पत्नी अभिलाषा ने अपनी सास बीना शर्मा सहित चार पर पति की हत्या का शक जताते हुए पुलिस को तहरीर सौंपी जिसके आधार पर खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अर्जुन जीएमएस रोड स्थित भारत गैस एजेंसी के संचालक थे। वे कारगिल शहीद स्व. कर्नल आरसी शर्मा के बेटे थे।

कार्यालय सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, बरेली सम्भाग, बरेली

पत्रांक : 2972/स्वी.अनु./गे.ख./परि.-ई-निविदा/2026-27/बरेली दिनांक : 10.02.2026

अल्पकालीन ई-टेण्डर नोटिस

कार्यालय आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ.प्र. जवाहर भवन, लखनऊ के कार्यालय पत्रांक 5471/अ.आ.वि./रा.वि.व.-01/2026-27 दिनांक 29.12.2025 के साथ संलग्न शासनादेश सं.- 380/29-5-2025 (ई.2000859) दिनांक 24.12.2025 के द्वारा रबी विपणन वर्ष 2026-27 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ क्रय व्यवस्था संबंधी समय सारिणी में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं. 591/29-4-2023/4013(99)/7/2022 दिनांक 16.05.2023, शासनादेश सं. 1215/29-4013(99)7/2022 दिनांक 15.09.2022, शासनादेश सं.-571/29-4-2023/4013(99)/ 7/2022 दिनांक 03.05.2023, शासन के पत्र संख्या 831/29-4-2023-385/19 दिनांक 25.07.2023 एवं अपर आयुक्त (विपणन), खाद्य तथा रसद विभाग, उ.प्र. जवाहर भवन लखनऊ के पत्रांक 3773/अ.वि.श./है.परि./परि.दर/359/2022 दिनांक 25.07.2023 के साथ संलग्न राज्य स्तरीय कमेटी (एस.एल.सी.) की दिनांक 10.07.2023 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 2893/स्वी.अनु./गे.ख./परि./ई-निविदा/2026-27/बरेली दिनांक 02.02.2026 के द्वारा प्रथम बार बरेली सम्भाग के जनपद बरेली, बदायूं, पीलीभीत एवं शाहजहांपुर में रबी विपणन वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नामित समस्त क्रय एजेन्सियों से सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारियों द्वारा स्वीकृत गेहूँ क्रय केन्द्रों से निर्धारित/सम्बद्ध भारतीय खाद्य निगम डिपो तक गेहूँ के परिवहन कार्य हेतु (एस.एल.सी. द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में) शेड्यूल दर के सापेक्ष ई-टेण्डरिंग के माध्यम से ई-निविदायें आमंत्रित की गयी थी।

उक्त ई-टेण्डर के उपरांत मण्डल में विज्ञापित केन्द्रों पर परिवहन कार्य हेतु विचारणीय निविदा न प्राप्त होने वाले अवशेष केन्द्रों एवं जिलाधिकारी बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर द्वारा स्वीकृत नवीन गेहूँ क्रय केन्द्रों पर संलग्न सूची (सूची सं. 01) के अनुसार समस्त क्रय संस्थाओं के गेहूँ परिवहन कार्य हेतु जनपद बरेली के 6, जनपद बदायूं के 23 जनपद पीलीभीत के 07 एवं जनपद शाहजहांपुर के 18 कुल 54 गेहूँ क्रय केन्द्रों पर पुनः ई-टेण्डर आमंत्रित किये जाते है।

शासनादेश सं. 380/29-5-2025 (ई.2000859) दिनांक 24.12.2025 में निर्धारित व्यवस्थान्तर्गत क्रय केन्द्रों का चयन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। यदि जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत/प्रस्तावित क्रय केन्द्रों में से किसी क्रय केन्द्र का चयन नहीं किया जाता है अथवा चयन के उपरान्त निरस्त किया जाता है तो क्रय केन्द्र हेतु डाली गयी समस्त परिवहन कार्य की निविदायें निरस्त समझी जायेगी। संलग्न सूची के अनुसार रबी विपणन वर्ष 2026-27 के अन्तर्गत गेहूँ परिवहन कार्य हेतु ई-निविदायें जनपदवार, केन्द्रवार प्राप्त की जायेगी। निविदादाता द्वारा प्रत्येक केन्द्र के लिए पृथक-पृथक निविदा संलग्न किये जायेंगे तथा निविदा शुल्क (प्रत्येक केन्द्र हेतु) एवं धरोहर धनराशि के रिसीट/यू.टी.आर. की ''स्कैन्ड कापी'' ऑनलाइन निविदा प्रपत्र के साथ निविदादाता द्वारा अपलोड की जायेगी। परिवहन कार्य हेतु निर्धारित निविदा प्रपत्र मूल्य, धरोहर धनराशि निविदा विशिष्टीकरण निविदा खुलने की तिथि एवं अन्य सम्बन्धित जानकारी http://etender.up.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है। परिवहन कार्य हेतु निविदा प्रपत्र शुलक 500+90(जी.एस.टी.)=590/- तथा प्रत्येक निविदा के साथ परिवहन कार्य के लिये धरोहर धनराशि रू. 15,000/- सम्भागीय वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी (खाद्य), बरेली के पदनाम से खाता संख्या 0232104000190848 आई.एफ.एस.सी. कोड IBKL0000232 आई.डी.बी.आई. बैंक सिविल लाइन्स बरेली में आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. से जमा किया जायेगा। प्रत्येक निविदा के साथ निविदा शुल्क एवं धरोहर धनराशि के रिसीट/यू.टी.आर. की ''स्कैन्ड कापी'' ऑनलाइन निविदा प्रपत्र के साथ निविदादाता द्वारा अपलोड की जायेगी।

निविदा प्रपत्र ऑनलाइन वेबसाइट http://etender.up.nic.in पर दिनांक 17.02.2026 को अपरान्ह 02:00 बजे तक अपलोड की जा सकती है। टेक्निकल बिड दिनांक 17.02.2026 को अपरान्ह 03:00 बजे तदर्थ गठित ई-निविदा समिति के द्वारा ऑनलाइन खोली जायेगी। टेक्निकल बिड के प्रपत्रों की जांचोपरान्त इसमें अहर्य निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। तदोपरांत वित्तीय, निविदा समिति द्वारा खोली जायेगी। निविदा को बिना कोई कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, बरेली के पास सुरक्षित होगा।

निविदा की शर्त में परिवर्तन तथा शुद्धि पत्र आदि की सूचना केवल ई-टेण्डर वेबसाइट http://etender.up.nic.in पर उपलब्ध होंगे।

(डा. मनिकन्डन ए.)
आई.ए.एस.
सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक,
बरेली सम्भाग, बरेली।

वर्ल्ड ब्रीफ

मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद का निर्माण शुरू

रेजिनगर। तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बहुचर्चित मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू किया। हाल ही में जनता उन्नयन पार्टी (जेयूपी) का गठन करने वाले कबीर ने घोषणा की कि बेलडांगा के रेजिनगर में इस मस्जिद का निर्माण दो साल के भीतर पूरा हो जाएगा और इसकी लागत लगभग 50 से 55 करोड़ रुपये आएगी। यह मस्जिद 11 एकड़ जमीन पर बनाई जा रही है और इसमें लगभग 12,000 लोगों के नमाज अदा करने की क्षमता होगी।

फेमा मामले में पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह बेटे समेत तलब

चंडीगढ़। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन के मामले में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके बेटे रनिंदर सिंह को पूछताछ के लिए तलब किया है। अधिकारियों के मुताबिक पिता-पुत्र पर स्विस बैंक खाते सहित कुछ विदेशी संपत्तियों के लाभार्थी होने का आरोप है। अधिकारियों ने बताया कि भाजपा नेता अमरिंदर सिंह को केंद्रीय जांच एजेंसी ने बृहस्पतिवार को जालंधर स्थित अपने कार्यालय में पेश होने के लिए कहा है, जबकि उनके बेटे को शुक्रवार को तलब किया गया है।

विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक पर 31 सदस्यीय समिति

नई दिल्ली। उच्च शिक्षा के लिए एकल नियामक बनाने का प्रस्ताव करने वाले विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक (वीबीएसए) पर गौर करने के लिए संसद में 31 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया गया है, जिसका नेतृत्व बीजेपी सांसद डी. पुरंदेश्वरी करेंगी। लोकसभा सचिवालय द्वारा मंगलवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, इस समिति में दोनों सदनों के सदस्य शामिल हैं और यह प्रस्तावित कानून के प्रावधानों की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। संसद में वीबीएसए विधेयक को शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किया गया था। यह विधेयक राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप उच्च शिक्षा नियामक ढांचे में व्यापक बदलाव करने का उद्देश्य रखता है।

ट्रेड यूनियनों की हड़ताल आज, देश भर में कई जरूरी सेवाएं हो सकती हैं बाधित

नए श्रम कानूनों समेत केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में 30 करोड़ कामगार होंगे हड़ताल में शामिल, किसान भी करेंगे विरोध प्रदर्शन

नई दिल्ली, एजेंसी

- बिजली, बैंक-बीमा, परिवहन और स्वास्थ्य सेवाओं के साथ गैस व पानी आपूर्ति पर पड़ेगा असर

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साझा मंच की ओर से बुलाई गई देशव्यापी हड़ताल की वजह से बृहस्पतिवार को पूरे देश में बिजली, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, स्वास्थ्य के साथ गैस और पानी आपूर्ति से जुड़ी सेवाओं पर असर पड़ सकता है। इस आम हड़ताल में अलग-अलग क्षेत्र के 30 करोड़ कामगारों के शामिल होने की उम्मीद है।

केंद्र सरकार पर मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, देश विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक नीतियों का आरोप लगाते हुए ट्रेड यूनियनों के एक समूह ने नौ जनवरी को देशव्यापी हड़ताल का एलान किया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की महासचिव अमरजीत कौर ने बताया, देशव्यापी हड़ताल से बिजली, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, गैस और जलापूर्ति की सेवाओं पर असर पड़ेगा। खनन और गैस पाइपलाइन क्षेत्र पर भी इस आंदोलन का असर दिखने की उम्मीद है। बीमा क्षेत्र के कर्मचारी इस क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई की इजाजत देने और नए श्रम कानून लागू करने के सरकार के फैसले का विरोध करेंगे। निजी और सरकारी ट्रांसपोर्ट कंपनियों के बड़ी संख्या में कर्मचारी विरोध में हिस्सा लेंगे।

उन्होंने भरोसा जताया कि इस बार, कम से कम 30 करोड़ कामगार हड़ताल में हिस्सा लेंगे और करीब 600 जिलों पर इसका असर पड़ने की उम्मीद है। पिछले साल नौ जुलाई को हुई इसी तरह की हड़ताल में, करीब 25 करोड़ कामगारों ने आंदोलन में हिस्सा लिया था, जिसका असर करीब 550 से ज्यादा जिलों पर पड़ा था।

ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (एआईपीईएफ) के अध्यक्ष, शैलेंद्र दुबे ने कहा कि देश भर में करीब 27 लाख बिजली कर्मचारी और इंजीनियर 12 फरवरी को एक दिन की हड़ताल करेंगे। यह हड़ताल निजीकरण, बिजली (संशोधन) विधेयक 2025, प्रस्तावित राष्ट्रीय बिजली नीति 2026 और बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने के विरोध में बुलाई गई है।

किसान भी हड़ताल में हों शामिल, अमेरिका से समझौते का प्रतियां जलाएं

नई दिल्ली। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने किसानों से बृहस्पतिवार को होने वाली अखिल भारतीय आम हड़ताल को सफल बनाने के लिए श्रमिक संगठन कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ने का आह्वान किया है। एसकेएम ने कहा कि हड़ताल में चार श्रम संहिताओं, बिजली विधेयक-2025, बीज विधेयक-2025 और वीबी-जी राम जी अधिनियम-2025 की वापसी, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, योजना श्रमिकों सहित श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी का कार्यान्वयन और अन्य मांगें शामिल हैं। बयान में कहा गया, एसकेएम जनता से केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से किसानों, श्रमिकों और आम लोगों पर किए जा रहे सभी नए हमलों का विरोध करने का आह्वान करता है। मोर्चा ने सभी किसानों से विरोध प्रदर्शन में शामिल होने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पुतले के के साथ अमेरिका से व्यापार समझौतों की प्रतियां जलाने की अपील की है।

संयुक्त किसान मोर्चा ने किया आह्वान

भिवानी में हड़ताल के मद्देनजर निषेधाज्ञा लागू

भिवानी। हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन की ओर से बृहस्पतिवार को राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दौरान बस स्टैंड और कार्यशाला परिसर में शांति व कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत धारा 163 लागू की गई है। हरियाणा रोडवेज, भिवानी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले बस स्टैंड और कार्यशाला परिसर के दो किमी की परिधि के अंदर पाबंदी के आदेश पारित किए गए है। जिलाधीश साहिल गुप्ता ने बुधवार को अपने आदेशों में कहा है कि इस संभावित हड़ताल के मद्देनजर, हरियाणा रोडवेज, भिवानी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले बस स्टैंड और कार्यशाला परिसर में अशांति, गैरकानूनी जमावड़ा और शांति भंग होने की आशंका है।

देश को बेच दिया, ऐसा न पहले किसी ने किया, न आगे करेगा

राहुल ने कहा- अमेरिका के आगे झुक गए प्रधानमंत्री, शर्म आनी चाहिए

नई दिल्ली, एजेंसी

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर बुधवार को हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार झुक गई और देश को बेच दिया, उसे इस पर शर्म आनी चाहिए। उन्होंने लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए दावा किया कि अमेरिका के दबाव में प्रधानमंत्री मोदी इस तरह का समझौता करने को विवश हुए। उन्होंने सत्तापक्ष के सदस्यों की टोकाटाकी के बीच यह भी कहा कि भारत-अमेरिका समझौते में देश के किसानों के हितों को कुचल दिया गया, जैसा आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया और आगे भी कोई नहीं करेगा।

कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री मोदी और सरकार पर निशाना साधते हुए अमेरिका में एक भारतीय उद्योगपति के खिलाफ दर्ज मामले और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चित एक प्रकरण का उल्लेख किया, जिस पर पीठासीन सभापति ने कहा कि यह रिकॉर्ड में शामिल नहीं होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने जो आरोप लगाए हैं उन्हें उन आरोपों को सत्यापित करना चाहिए, जिस पर राहुल ने कहा कि वह इसके लिए तैयार हैं। राहुल गांधी ने कहा, मुझे सबसे हैरानी इस बात पर हुई कि अमेरिका-भारत व्यापार समझौते में क्या हुआ। अगर हम 'इंडिया' गठबंधन की सरकार में ट्रंप से बातचीत कर रहे होते तो एक बात बिल्कुल साफ करते कि इस पूरे समीकरण में सबसे महत्वपूर्ण पूंजी भारतीय डेटा है। अगर अमेरिका डॉलर को सुरक्षित रखना चाहता है तो उसे मानना होगा कि भारतीय डेटा एक रणनीतिक पूंजी है और किसी भी चर्चा को बराबरी के स्तर पर होना चाहिए, मालिक और नौकर की तरह नहीं।

उन्होंने कहा, हम यह भी स्पष्ट करते कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं हो सकता और जहां अमेरिका अपने किसानों की रक्षा करेगा, वहीं हम अपने किसानों की रक्षा करेंगे। 'इंडिया' गठबंधन की सरकार बराबरी पर बातचीत करती, भारत को पाकिस्तान के बराबर नहीं खड़ा करने देती और ऐसे किसी भी प्रतीकात्मक अपमान पर कड़ा विरोध दर्ज कराती। राहुल ने आरोप लगाया कि इस समझौते में मोदी सरकार ने डिजिटल व्यापार के नियमों पर नियंत्रण छोड़ दिया, डेटा लोकलाइजेशन हटाया, अमेरिका को डेटा का मुक्त प्रवाह करने की अनुमति दी, डिजिटल कर पर सीमा लगा दी, सोर्स कोड खुलासा करने की शर्त हटा दी और बड़ी टेक कंपनियों को लंबे 'टैक्स हॉलिडे' (लंबे समय तक कर से छूट) दे दिए।

पहली बार भयंकर तूफान में फंसे हैं देश के किसान

राहुल गांधी ने कहा कि इतिहास में पहली बार भारतीय किसान एक भयानक तूफान का सामना कर रहे हैं। आपने हजारों एकड़ में फैले यांत्रिक अमेरिकी खेतों के लिए दरवाजा खोल दिया है और हमारे छोटे किसानों को पूरी तरह कुचल दिया है। आरोप लगाया कि अमेरिका को भारत की वित्त व्यवस्था और ऊर्जा को भारत के ही खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करने की छूट दे दी गई है। कहा, आप इस सदन में आकर इसका बचाव कैसे कर सकते हैं। जो कुछ आप सौंप रहे हैं, उस पर आपको शर्म नहीं आती। राहुल ने कहा, अमेरिका और चीन के बीच मुकाबले में सबसे महत्वपूर्ण बात भारत का डेटा है। अगर अमेरिका महाशक्ति बने रहना चाहता है और डॉलर की रक्षा करना चाहता है तो अमेरिकियों के लिए भारत का डेटा बहुत महत्वपूर्ण है।

प्रधानमंत्री पर राहुल के आरोप गलत और भाषा सड़कछाप

भाजपा ने नेता प्रतिपक्ष पर देश व सदन को गुमराह करने का लगाया आरोप

नई दिल्ली, एजेंसी

भाजपा ने बुधवार को भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी के आरोपों को हास्यास्पद रूप से गलत बताकर खारिज करते हुए कहा कि लोकसभा में बोलते समय नेता प्रतिपक्ष ने सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल कर संसदीय मर्यादा को निम्न स्तर पर पहुंचा दिया। भाजपा की टिप्पणी तब आई जब राहुल गांधी ने सदन में केंद्रीय बजट पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए मोदी पर तीखा हमला किया और आरोप लगाया कि सरकार ने इस व्यापार समझौते के जरिए भारत माता को बेच दिया है।

राहुल गांधी की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना करते हुए भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी ने कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर कांग्रेस नेता के दावे हास्यास्पद रूप से असत्य एवं गलत हैं। बलूनी ने ''एक्स'' पर सिलसिलेवार पोस्ट में कहा, राहुल गांधी ने एक बार फिर सच्चाई की जगह नाटक का चयन किया है, सदन और देश दोनों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान राहुल ने न केवल दस्तावेज की आलोचना की, बल्कि उसे गलत तरीके से उद्धृत किया और पढ़ा तथा फिर उस विकृति के आधार पर अपना तर्क खड़ा किया। भाजपा सांसद ने कहा, राहुल गांधी का दावा एक ऐसे दस्तावेज पर आधारित है जो अब वास्तविकता को प्रतिबिंबित नहीं करता। वह अमेरिका सरकार के एक पुराने तथ्यपत्र का हवाला दे रहे हैं जिसमें भारत द्वारा प्रस्तावित 500 अरब अमेरिकी डॉलर की खरीद को एक प्रतिबद्धता के रूप में प्रस्तुत किया गया था। उस भाषा को बाद में संशोधित कर दिया गया है।

बलूनी ने कहा, अद्यतन स्थिति स्पष्ट है, भारत ने आने वाले वर्षों में 500 अरब अमेरिकी डॉलर तक की वस्तुओं की खरीद का इरादा व्यक्त किया है, यह बाध्यकारी नहीं है। भारतीय डेटा को अमेरिका को बेचे जाने के दावे को खारिज करते हुए बलूनी ने कहा कि बजट, जिसमें 2047 तक भारत में डेटा सेंटर स्थापित करने वाली कंपनियों को कर में छूट देने का प्रस्ताव है, भारत के डेटा का स्थानीयकरण करने के लक्ष्य को और आगे बढ़ाएगा। उन्होंने कहा, भारत में अधिक डेटा सेंटर होने से हमारी आईटी कंपनियां पश्चिमी देशों के ग्राहकों को क्लाउड और अन्य एआई समाधान प्रदान कर सकेंगी।

त्रिवेदी बोले- राहुल कांग्रेस के सबसे बुद्धिमान मूर्ख

इसके पहले भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने गांधी के आरोपों को बेबुनियाद बताकर खारिज करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता ने सदन में बोलते समय सड़क छाप भाषा और सड़क छाप आचरण का इस्तेमाल करके संसदीय मर्यादा एवं राजनीति को निम्न तर स्तर पर पहुंचा दिया। उन्होंने राहुल गांधी की टिप्पणियों की निंदा करते हुए यहां भाजपा मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, अगर महाराजा जेम्स प्रथम ईसाई जगत के सबसे बुद्धिमान मूर्ख थे, तो हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बुद्धिमान मूर्ख हैं। त्रिवेदी ने कहा, उन्होंने आरोप लगाया कि देश को बेच दिया गया। मुझे लगता है कि अगर उन्हें कूटनीति और आर्थिक नीतियों की समझ होती, तो ऐसे निराधार आरोप नहीं लगाते।

अजित पवार के बेटों ने भी जताया विमान हादसे में साजिश का शक

मुंबई, एजेंसी

- राकांपा (शप) विधायक रोहित पवार ने किया दावा, हादसे से जुड़ा नया वीडियो जारी किया

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना में हुई मौत का मामला और गहराता जा रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के विधायक रोहित पवार ने बुधवार को इस हादसे से जुड़ा एक नया वीडियो जारी किया और दावा किया कि अजित पवार के बेटे पार्थ और जय पवार को इस घटना पर गंभीर संदेह हैं। उन्होंने कहा, परिवार और पार्टी के भीतर इस हादसे को लेकर भारी अविश्वास का माहौल है।

रोहित पवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने हाल ही में पार्थ पवार से मुलाकात की है, उनके मन में भी कई प्रश्न हैं। उन्होंने तर्क दिया कि यह एक सामान्य दुर्घटना होती तो अजित पवार गुट के नेता जैसे अमोल मिटकरी और रूपाली ठोंबरे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने नहीं जाते। रोहित ने कहा कि इन नेताओं ने पार्थ और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार की सलाह के बाद ही मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि यह हादसा कैसे और किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी तह तक जाना जरूरी है।

रोहित पवार ने एक राजनीतिक सलाहकार का जिक्र करते हुए मामले में नया मोड़ दे दिया। उन्होंने बताया कि हादसे से पहले अजित पवार एक ऐसे सलाहकार की सेवाएं समाप्त करने पर चर्चा कर रहे थे, जिसका बजट करोड़ों में था।

उच्चस्तरीय जांच के लिए शाह से मिलेंगी सुप्रिया सुले

इस बीच, सांसद सुप्रिया सुले ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का समय मांगा है। रोहित पवार ने स्पष्ट किया कि हालांकि वे किसी पार्टी या सरकार पर सीधा आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें इस घटना के पीछे एक बड़ी साजिश की बू आ रही है। उन्होंने कहा कि वे अमित शाह से मिलकर इस दिशा में गहन जांच की मांग करेंगे ताकि सच सामने आ सके।

केंद्र को निर्देश, एअर इंडिया विमान दुर्घटना की जांच रिपोर्ट दाखिल करे

नई दिल्ली, एजेंसी

- केंद्र ने कहा- एएआईबी जांच अंतिम चरण में, कुछ जांच विदेश में किए जाने की जरूरत

उच्चतम न्यायालय ने 12 जून, 2025 को एअर इंडिया विमान दुर्घटना के मामले में बुधवार को केंद्र से अब तक अपनाए गए प्रक्रियात्मक प्रोटोकॉल पर संक्षिप्त रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। अदालत ने यह निर्देश तब दिया जब उसे सूचित किया गया कि हादसे की जांच विमान दुर्घटना जांच बोर्ड (एएआईबी) द्वारा अंतिम चरण में है।

लंदन जा रही एअर इंडिया की बोइंग 787-8 उड़ान एआई171 गुजरात के अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसमें 241 यात्री और चालक दल समेत 260 लोग मारे गए। दुर्घटना में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी मौत हो गई थी। बुधवार को प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि एएआईबी जांच अंतिम चरण में है और कुछ जांच विदेश में किए जाने की जरूरत है। मेहता केंद्र और नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) की तरफ से अदालत में पेश हुए। शीर्ष विधि अधिकारी ने कहा कि मामले पर तीन संबंधित याचिकाओं को व्यापक सुनवाई के लिए तीन सप्ताह के बाद सूचीबद्ध किया जा सकता है। पीठ का शुरू में विचार था कि एएआईबी जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में उसके समक्ष प्रस्तुत की जाए।

एनआईए यूएपीए पर रिपोर्ट दाखिल करे

सुप्रीम कोर्ट ने को निर्देश दिया है कि वह पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुई हिंसा से संबंधित मामले में आतंकवाद से जुड़े कठोर प्रावधानों वाले यूएपीए के इस्तेमाल का औचित्य स्पष्ट करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में रिपोर्ट दाखिल करे। राज्य सरकार की अपील का निस्तारण करते हुए पीठ ने उसे मामले में एनआईए की जांच के खिलाफ अपनी शिकायतों के साथ उच्च न्यायालय में जाने के लिए भी कहा।

जाइडस को कैंसर दवा निवोलुमाब के समान उत्पाद की बिक्री रोकने से कोर्ट का इन्कार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब (बीएमएस) द्वारा पंजीकृत जीवन रक्षक कैंसर की दवा 'निवोलुमाब' के किफायती और 'जेनेरिक बायोसिमिलर' की बिक्री कर रही जाइडस लाइफसाइंसेज पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। 'बायोसिमिलर दवा' वह दवा होती है जो किसी पहले से मौजूद जैविक दवा के बहुत समान होती है, लेकिन उसकी हूबहू कॉपी नहीं होती। सीजेआई सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ बीएमएस की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें जाइडस को बायोसिमिलर दवा की बिक्री से रोकने की मांग की गई थी। पीठ ने बीएमएस को जाइडस उत्पाद की अपने पेटेंट प्राप्त दवा के साथ सीधी तुलना करने का निर्देश दिया और कहा कि इस प्रक्रिया के परिणाम के आधार पर कंपनी अंतरिम राहत के लिए उच्च न्यायालय का रुख कर सकती है।

भाजपा की रितु मुंबई की महापौर, शिंदे गुट के संजय घाडी उपमहापौर बने

मुंबई। भाजपा की पार्षद रितु तावडे बुधवार को मुंबई की महापौर चुनी गईं, जबकि शिवसेना के संजय घाडी उप महापौर बने। बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) की विशेष आम सभा में तावडे और घाडी दोनों निर्विरोध निर्वाचित हुए। बीएमसी मुख्यालय में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद, सत्ताधारी और विपक्षी दलों के पार्षदों के नारेबाजी के बीच तावडे ने मुंबई की 78वीं महापौर के रूप में कार्यभार संभाला। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एवं शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे समारोह में उपस्थित थे। उन्होंने नव निर्वाचित महापौर और उपमहापौर को बधाई दी। नगर निकाय के लिए 15 जनवरी को हुए चुनाव में तावडे वार्ड 132, जबकि घाडी वार्ड-पांच से निर्वाचित हुए थे। निर्वाचित आमसभा के अभाव में, बीएमसी आयुक्त भूषण गगराणी मार्च 2022 से नगर निकाय के कामकाजों की देखरेख कर रहे थे। तावडे के महापौर बनने के साथ ही भाजपा ने 44 वर्षों के बाद देश के सबसे अमीर नगर निकाय में महापौर का पद पर कब्जा जमा लिया। वह मुंबई में भाजपा की दूसरी महापौर हैं।

आवास आवंटन मामले में माता-पिता और आश्रित भाई-बहन भी सैन्य अधिकारियों के परिवार में शामिल

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य अधिकारियों को सरकारी आवास आवंटन करने के उद्देश्य से परिवार की परिभाषा के विस्तार को मंजूरी दे दी है। अब इसमें माता-पिता, आश्रित भाई-बहन और कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चों को भी शामिल किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि संशोधित परिभाषा में अब पति- पत्नी एवं आश्रित बच्चों, सौतेले बच्चों के अलावा माता-पिता, आश्रित भाई-बहन और कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चों को भी शामिल किया गया है। इस विस्तारित परिभाषा से सभी सैन्य अधिकारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसमें अपने माता-पिता के साथ रहने वाली अविवाहित महिला अधिकारी भी शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा है कि यह निर्णय ''माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007'' को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और पारिवारिक दायित्वों तथा देखभाल की व्यवस्थाओं की बदलती प्रकृति को स्वीकार करता है। यह वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण, पारिवारिक सुख-समृद्धि और सामाजिक एवं पीढ़ीगत संबंधों को सुदृढ़ करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

बिहार: हर महीने 50 लाख हड़प रही थीं सहरसा की महापौर, रिपोर्ट

पटना। नगर विकास एवं आवास विभाग ने सरकारी राशि के दुरुपयोग के आरोप में सहरसा की महापौर, उनके निजी सचिव और निजी सचिव की पत्नी पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह मामला सहरसा की महापौर, उनके निजी सचिव राजीव कुमार एवं उनकी पत्नी पर स्ट्रीट लाइट, डेकोरेटिव लाइट रखरखाव एवं मेंटेनेंस के नाम पर प्रतिमाह लगभग 50 लाख रुपये दुरुपयोग का आरोप है। इस बारे में सहरसा के कोसी कॉलोनी निवासी राहुल कुमार पासवान ने परिवाद दायर की थी। जिला पदाधिकारी, सहरसा के स्तर पर त्रिस्तरीय जांच समिति का गठन किया गया था।

एप्स्टीन से मिला मगर उसके अपराधों से लेना-देना नहीं

नई दिल्ली, एजेंसी

- केंद्रीय मंत्री पुरी ने राहुल गांधी पर लगाया बदनाम करने का आरोप

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उनके खिलाफ आरोप लगाने के लिए बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि उनकी मुलाकात जेफ्री एप्स्टीन से कुछ मौकों पर हुई थी, लेकिन उसके साथ हुई बातचीत का उन अपराधों से कोई लेनादेना नहीं था जिनमें अमेरिकी यौन अपराधी शामिल था। पुरी ने यह स्पष्टीकरण राहुल गांधी के उस दावे के बाद दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्रीय मंत्री का नाम अमेरिका में जारी एप्स्टीन फाइल्स में आया है।

पुरी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत के रूप में इस्तीफा देने के कुछ महीनों बाद मुझे अंतरराष्ट्रीय शांति संस्थान (आईपीआई) में शामिल होने का निमंत्रण मिला। मैं आईपीआई में एक परियोजना के रूप में स्थापित बहुपक्षवाद संबंधी स्वतंत्र आयोग (आईसीएम) का महासचिव था। उन्होंने कहा, आईपीआई में मेरे बॉस टेर्जे रोड-लार्सन कुख्यात व्यक्ति एप्स्टीन को जानते थे और आईपीआई या आईसीएम के प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में ही मेरी एप्स्टीन से तीन या बार मुलाकात हुई थी।

पुरी ने कहा कि आईसीएम अंतरराष्ट्रीय और विषयगत मुद्दों से निपट रहा था और एप्स्टीन इसका हिस्सा नहीं था। उन्होंने कहा कि एप्स्टीन पर कई अपराधों का आरोप था और यह भी आरोप था कि उसके पास एक द्वीप था जहां वह लोगों को उनकी यौन जरूरतों को पूरा करने के लिए ले जाता था।

केबिन क्रू पिंकी माली के पिता ने भी हादसे पर उठाए सवाल

मुंबई। अजित पवार वाले विमान हादसे में जान गंवाने वाली फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली के पिता शिवकुमार माली ने भी घटना की परिस्थितियों पर संदेह जताते हुए गहन जांच की मांग की है। पिंकी के पिता शिवकुमार माली ने बुधवार को कहा कि राकांपा (शप) के विधायक रोहित पवार के बताए बिंदुओं ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या यह महज एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कुछ और कारण थे।

राष्ट्रीय सुरक्षा | जैसलमेर के पास पोखरण फायरिंग रेंज में 27 फरवरी को होगा वायु सेना का बड़ा अभ्यास

वायु शक्ति अभ्यास में जलवा दिखाएगा स्वदेशी तेजस

नई दिल्ली, एजेंसी

पिछले वर्ष दुबई एयर शो में करतब दिखाते हुए भीषण दुर्घटना का शिकार हुआ वायु सेना का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस मार्क-1 ए एक बार फिर 'वायु शक्ति 2026' अभ्यास में प्रमुख भूमिका में नजर आएगा। वायु सेना का यह व्यापक शक्ति प्रदर्शन 27 फरवरी को राजस्थान के जैसलमेर के पास पोखरण फायरिंग रेंज में होगा।

सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा निर्मित तेजस मार्क-1ए इस अभ्यास में हवाई ड्रिल और युद्ध प्रदर्शन में भाग लेगा। इस अभ्यास में तेजस के साथ लड़ाकू विमान राफेल, जगुआर, मिराज-2000, सुखोई-30 एमकेआई, मिग-29, हॉक, मालवाहक विमान सी-130जे, सी-295, सी-17, हेलिकॉप्टर चेतक, एमआई 17, अपाचे और चिनूक तथा रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सहित 120 प्लेटफार्म हिस्सा लेंगे। अभ्यास में छोटी दूरी के लॉइटरिंग म्यूनिशन, आकाश, स्पाइडर और काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स जैसी उन्नत हथियार प्रणालियां भी शामिल होंगी जो दिन, संध्या और रात्रि मिशनों को अंजाम देंगी। हालांकि, लंबी दूरी की लक्ष्यभेदी कार्रवाई शामिल नहीं होगी।

रक्षा मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा 'वायुशक्ति-26' ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को भी प्रदर्शित करेगा और आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से प्रेरित स्वदेशी प्लेटफॉर्मों के माध्यम से हवाई क्षेत्र में प्रभुत्व, लंबी दूरी की सटीक लक्ष्यभेदन क्षमता, बहु-क्षेत्रीय अभियानों और निर्णायक प्रभाव डालने की भारतीय वायु सेना की क्षमता की पुनः पुष्टि करेगा। अचूक, अभेद्य और सटीक के मूल मंत्र से प्रेरित भारतीय वायुसेना के इस अभ्यास का उद्देश्य राष्ट्र को देश की सुरक्षा के प्रति आश्वस्त करना है।

अमृत विचार

गुरुवार, 12 फरवरी 2026

डीपफेक पर शिकंजा

एआई के दौर में डीपफेक लोकतंत्र, निजता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है। आईटी नियमों में हालिया संशोधन, डीपफेक और एआई-जनित सामग्री की नई परिभाषाएं, निर्दिष्ट सामग्री को शीघ्रता से हटाने का अनिवार्य प्रावधान नियामकीय ढांचे को ताकत देंगे। ये इस चुनौती से निबटने का सराहनीय प्रयास है। संशोधित नियमों में 'एआई-जनित या सिंथेटिक मीडिया', 'डीपफेक', 'मॉर्फ्ड या मैनिपुलेटेड कंटेंट' और 'भ्रामक लेबलिंग' जैसी स्पष्ट परिभाषाएं शामिल करने के बाद प्लेटफॉर्म का यह तर्क कि सामग्री 'यूजर-जनरेटेड' है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी सीमित है, कुतर्क में बदल गया है। अब यदि कोई ऑडियो-वीडियो एआई जनित है और उसे वास्तविक बताकर प्रसारित किया गया, तो साफ बताना होगा। गंभीर मामलों में शिकायत होने के तीन घंटे के भीतर सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को इसे हटाना या निष्क्रिय करना होगा। यह प्रावधान महत्वपूर्ण सोशल मीडिया इंटरमीडियरी, मैसेजिंग सेवाओं, वीडियो-शेयरिंग साइट्स और होस्टिंग प्रदाताओं सभी पर लागू होगा।

आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत प्लेटफॉर्म को 'सेफ हार्बर' सुरक्षा मिलती है, यानी यूजर की पोस्ट के लिए वे स्वतः दोषी नहीं माने जाते। अब नए नियमों के तहत यदि प्लेटफॉर्म समयबद्ध तरीके से डीपफेक हटाने, लेबलिंग और शिकायत-निवारण अपनाएंगी, तभी उनकी सेफ हार्बर सुरक्षा बचेगी। इसका अर्थ है कि अब उनकी जिम्मेदारी अधिक है और बचाव की गुंजाइश थोड़ी कम, हालांकि इन संशोधनों के बाद भी यह चुनौती बाकी है कि नियम मुख्यतः शिकायत-आधारित हैं, कंटेंट हटाने की प्रक्रिया तब सक्रिय होती है, जब कोई यूजर शिकायत करे और सरकार उस संबंधित सामग्री को फ्लैग करे। डीपफेक का शिकार स्थानीय पुलिस के साइबर सेल में एफआईआर दर्ज करा सकता है, साइबर क्राइम पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकता है अथवा ग्रिवेंस ऑफिसर को ईमेल के जरिये औपचारिक शिकायत दर्ज करा सकता है। पर सवाल यह है कि हर यूजर दिन रात इसकी बात पर निगरानी नहीं रख सकता कि वह कब कहां और किस प्लेटफॉर्म पर डीपफेक का शिकार हो चुका है। इस मामले में आम उपयोगकर्ता विकल्पहीन नजर आता है, इसलिए भले ही एआई टूल्स सुलभ हैं और 'क्राइम-एज़-ए-सर्विस' मॉडल ने इसे संगठित अपराध का रूप दे दिया हो, नये नियमों के सख्त लेबलिंग, त्वरित टेकडाउन और ट्रेसबिलिटी से नुकसान को किंचित कम किया जा सके, लेकिन अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्लेटफॉर्म को प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग, एआई-आधारित डिटेक्शन और जोखिम-आधारित फ्लैगिंग अपनानी ही होगी। सर्विस प्रोवाइडर समय सीमा में कार्रवाई नहीं करता, तो सेफ हार्बर तत्काल समाप्त होने, भारी जुर्माने के साथ उसके विरुद्ध आपराधिक मामला बनना चाहिए, लेकिन यहां स्पष्ट आर्थिक दंड और पीड़ित के लिए क्षतिपूर्ति तंत्र का अभाव है, जो नियमों को कमजोर बनाएगा। जब तक अनुपालन न करने पर ठोस दंड, जैसे- राजस्व-आधारित जुर्माना, अस्थायी निलंबन या लाइसेंस शर्तें स्पष्ट न हों, तब तक नियमों की प्रभावशीलता सीमित रहेगी।

प्रसंगवश

स्वराष्ट्र, स्वभाषा के पक्षधर थे महर्षि दयानंद सरस्वती

महान समाज सुधारक महर्षि दयानंद सरस्वती ऐसे युग पुरुष थे, जिन्होंने सामाजिक कुरीति उन्मूलन, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन, सामाजिक समरसता के लिए काम कर समाज सुधार की नई क्रान्ति का सूत्रपात किया। उन्होंने देश में स्वराज्य तथा आजादी की भावना को सुदृढ़ किया। महर्षि दयानंद और उनका आदर्श था- 'कृण्वंतो विश्वमार्यम्' ॥ अर्थात, हम पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाएं, हम पूरे विश्व में श्रेष्ठ विचारों का, मानवीय आदर्शों का संचार करें, इसलिए, 21वीं सदी में आज जब विश्व अनेक विवादों में फंसा है, हिंसा और अस्थिरता में घिरा हुआ है, तब महर्षि दयानंद सरस्वती जी का दिखाया मार्ग करोड़ों लोगों में आशा का संचार करता है।

उनका जन्म 12 फरवरी, 1824 को गुजरात के टंकारा में एक पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका नाम मूल शंकर तिवारी था। उनके माता-पिता यशोदाबाई और लालजी तिवारी

सुधांशु टाक
लेखक

समर्पित हिंदू थे। छोटी उम्र में ही उनमें आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति गहरी रुचि विकसित हो गई और उन्होंने मूर्ति पूजा, अनुष्ठानों और अंधविश्वासों पर प्रश्न उठाए।

19 वर्ष की उम्र में सांसारिक जीवन त्यागकर, वे सत्य की खोज में लगभग 15 वर्षों तक एक तपस्वी के रूप में भ्रमण करते रहे। उन्होंने मथुरा में स्वामी विरजानंद से शिक्षा प्राप्त की, जिन्होंने उन्हें हिंदू धर्म से भ्रष्ट प्रथाओं को समाप्त करने तथा वेदों के सच्चे अर्थ को पुनर्स्थापित करने के लिए काम करने का आग्रह किया। जब महर्षि दयानंद जी का जन्म हुआ, तब देश सदियों की गुलामी से कमजोर पड़कर अपनी आभा, अपना तेज, अपना आत्मविश्वास, सब कुछ खोता चला जा रहा था। प्रतिपल हमारे संस्कारों को, हमारे आदर्शों को, हमारे मूल्योंर को चूर-चूर करने की लाखों कोशिशें होती रहती थीं। जब किसी समाज में गुलामी की हीन भावना घर कर जाती है, तो आध्यात्म और आस्था की जगह आडंबर आना स्वाभाविक हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में महर्षि दयानंद जी ने आगे आकर वेदों के बोध को समाज जीवन में पुनर्जीवित किया। उन्होंने समाज को दिशा दी, अपने तर्कों से ये सिद्ध किया और उन्होंने ये बार-बार बताया कि खामी भारत के धर्म और परंपराओं में नहीं है। खामी है कि हम उनके वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं और विकृतियों से भर गए हैं।

स्वराष्ट्र, स्वभाषा, स्वभूषा, स्वसंस्कृति और स्वतंत्रता के प्रबलतम पक्षधर महर्षि दयानंद सरस्वती ऐसे दिव्य राष्ट्र पुरुष थे, जिनका संपूर्ण चिंतन और कार्य जहां आध्यात्मिकता से ओतप्रोत था, वहीं राष्ट्र उनके लिए प्रथम था। महर्षि दयानंद मानते थे कि व्यक्ति की सर्वांगीण उन्नति 'स्व' से ही प्रारंभ होती है। किसी भी क्षेत्र की पराधीनता व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिए अधोगति का कारण बनती है। पराधीन व्यक्ति चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता है।

भारतवर्ष की स्वाधीनता के लिए एकदम साफ और बुलंद शब्दों में आवाज उठाने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति महर्षि दयानंद ही थे और इसके लिए कष्ट और अमानवीयता की सीमा तक यातनाएं सहने वाले अधिकांशतः व्यक्ति देव दयानंद के अनुयाई और पथानुगामी ही थे। उसे समय के प्रायः सभी युगपुरुष और महापुरुष जहां कुछ एक क्षेत्र में कार्य करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ रहे थे वहां मात्र महर्षि दयानंद ने संपूर्ण क्रांति के लिए कार्य किया। अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना से भी पहले सन् 1874 में ऋषि दयानंद सरस्वती ने 'आर्याभिविनय' की रचना की थी। उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा था- 'अन्य देशवासी राजा हमारे देश में कभी शासन न करें। हम कभी पराधीन न हों।'

हम खेलना बंद नहीं करते, क्योंकि हम बूढ़े हो जाते हैं। हम बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि हम खेलना बंद कर देते हैं।

–जार्ज बर्नाड शॉ, आइरिश लेखक

उत्तराखंड के लिए संजीवनी बनेगी होमस्टे की नीति

अमित शर्मा
हल्द्वानी

पर्वतीय और पर्यटन राज्य की बेशुमार खूबियां समेटे उत्तराखंड के लिए होमस्टे की नयी नीति को किसी संजीवनी से कम नहीं आंका जा सकता है। होमस्टे के कॉन्सेप्ट ने न केवल यहां रोजगार के द्वार खोले हैं, बल्कि अकल्पनीय पर्यटन का विस्तार भी किया है। प्रदेश के दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में होमस्टे अलग से पहाड़ की लोक संस्कृति, परंपरा, संस्कार और स्थानीय उत्पादों की पहचान देश-विदेश में करवा रहा है। मात्र 10 वर्षों में होमस्टे का प्रचलन राज्य के कोने-कोने में पैर जमाने में सफल हुआ है।

अलग राज्य बनने के बाद प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या रोजगार की थी जिस कारण ग्रामीण क्षेत्रों से युवाओं को मजबूरन पलायन करना पड़ रहा था और पलायन रोकना ही प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी चुनौती रहती आई है। रोजगार के अभाव में प्रदेश में गांव के गांव वीरान होने लगे थे। इस समस्या पर अंकुश लगाने के लिए कोई युक्ति नहीं थी, लेकिन करीब दस वर्ष पहले होमस्टे का कॉन्सेप्ट वापसी की लौ बनकर सामने आया। यह देखने में बेहद मामूली नजर आ रहा था, लेकिन रोजगार के साथ पर्यटन के विस्तार का बड़ा मार्ग था। कुछ वर्ष यूं ही बीत गए और करीब छह बरस पहले इसके महत्व को समझते हुए प्रदेश सरकार ने होमस्टे को आगे ले जाने के लिए युवाओं को इससे जोड़ने व प्रेरित करने का अभियान शुरू कर दिया।

दरअसल, यह पर्यटन की ऐसी अवधारणा थी, जिसमें खर्च न के बराबर और आकर्षण अनूठा था। अधिक कुछ न कर पुराने घरों को संवारना था और पर्यटक के रूप में आने वाले मेहमानों को घर जैसे प्यार के साथ आवभगत करना था। कुमाऊं और गढ़वाल की संस्कृति सैकड़ों वर्ष पुरानी है, जो देश और दुनिया में अलग पहचान रखती है, लेकिन इसका विस्तार तभी संभव था, जब महानगरों से लोग आएं और यहां की संस्कृति, सौहार्द, खान-पान और रहन-सहन की अनुभूति को अनुभव कर सकें।

उत्तराखंड के लिए होमस्टे की नई नीति को किसी संजीवनी से कम नहीं आंका जा सकता। होमस्टे के कॉन्सेप्ट ने न केवल यहां रोजगार के द्वार खोले हैं, बल्कि पर्यटन का विस्तार भी किया है।

प्रदेश के पारंपरिक कुमाऊंनी, गढ़वाली घर मिट्टी-पत्थर और लकड़ी से बने होते हैं। पर्यावरण संरक्षण की झलक और उदाहरण देते प्रतीत होते हैं। पर्यटकों के लिए यह ऐसा आकर्षण और अनुभव है, जो कल्पना से परे होता है। मगर इस अहसास को जगाने के लिए सैलानियों की मौजूदगी बेहद जरूरी थी। इस बीच कोविड महामारी शुरू हो गई। यह महामारी अभिशाप जरूर थी, लेकिन राज्य के होमस्टे का सुहाना सफर यहीं से शुरू हुआ। पलायन कर चुके युवाओं का रिवर्स पलायन शुरू हो गया और उनके लिए उन्हें जब होमस्टे के बारे में पता लगा तो उन्हें अपने सपनों का संसार घर में बसाने का सुनहरा अवसर मिल गया।

एक खास बात यह भी है कि उत्तराखंड की एक विशेष पहचान कुकिंग को लेकर भी रही है। गांव छोड़ महानगरों की शरण लेने वाले लोगों में एक तबका बड़े-नामी होटलों में खाना बनाने में माहिर माने जाते हैं। यह ऐसा हुनर है, जो होमस्टे की सफलता की बुनियाद है। यही वजह है कि वर्तमान में प्रदेशभर में 6545 होमस्टे सफलता के साथ संचालित हो रहे है और 20 हजार से अधिक लोग इन होमस्टे में आजीविका कमाने के साथ अपनी जड़ों से वापस जुड़ रहे हैं।

इसमें जरा भी संदेह नहीं कि उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता दुनिया में अलग और बेपनाह खूबसूरत है। इधर, होमस्टे ने जहां रोजगार की दिशा में बड़ा कदम उठाया, वहीं प्रदेश की तमाम खूबियों के चलते देश-विदेश के लोगों के प्रति आकर्षण पैदा किया है। देवभूमि की बड़ी विशेषता यहां का भोजन है, जो औषधि का काम करता है। गहत और भट्ट की दाल और राजमा का कोई सानी नहीं। इसके अलावा बिच्छू समेत पहाड़ी सब्जियों का भंडार ग्रामीण अंचलों में उपलब्ध है, जो शहरों की हाईब्रिड सब्जियों से कहीं अधिक उत्तम व ऑर्गेनिक है। भाग दौड़ भरी जिंदगी से पहाड़ों का सुकून व शांति का वातावरण पर्यटकों को बेहद भाने लगा है। आदर सत्कार, स्नेह, प्रेम और संस्कार, जो होटलों में संभव नहीं, वह होमस्टे में मिलता है। कम खर्च और ढेर सारी मौज-मस्ती का आनंद होमस्टे में मिल जाता है। यही वजह है कि वर्तमान में होटलों की जगह होमस्टे की मांग बढ़ने लगी है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट ने बीते माह होमस्टे योजना को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए अहम बदलाव किए। इसके अनुसार, अब केवल उत्तराखंड के स्थायी निवासी ही होमस्टे योजना का लाभ उठा सकते हैं, हालांकि अन्य राज्यों के होम स्टे संचालक बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना में शामिल होंगे, जिन्हें जीएसटी और व्यावसायिक दरों पर बिजली-पानी मिलेगा। नई 'उत्तराखंड पर्यटन, यात्रा व्यवसाय, होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट पंजीकरण नियमावली-2026' का स्पष्ट उद्देश्य स्थानीय निवासियों के हितों की रक्षा करना है।

इस योजना के बड़े फायदों में, स्थानीय निवासियों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और रिवर्स पलायन में यह योजना संजीवनी का काम करेगी। पहाड़ की जवानी पहाड़ के ही काम आएगी। स्थानीय होने के चलते वे स्वयं पहाड़ व अपने आसपास की संस्कृति, विशेषताओं से मेहमान पर्यटकों को बता सकेंगे। स्थानीय होम स्टे संचालकों को बिजली और पानी की सुविधा घरेलू दरों पर मिलने से उनकी लागत भी कम होगी।

पर्यटन अधिकारी अतुल भंडारी कहते हैं कि होमस्टे दूरदराज के ग्रामीण अंचल के लिए किसी वरदान से कम नहीं। प्रदेश की बड़ी आबादी दूर गांवों में रहती है, जहां रोजगार के रूप में होमस्टे लोगों का जीवन स्तर बदल रहा है। होमस्टे खोलने को लेकर सरकार 50 प्रतिशत की सब्सिडी दे रही है, तो बैंक से मिलने वाले ऋण में बैंक ब्याज में 50 फीसद छूट दे रहा है। होमस्टे ने रिवर्स पलायन में बड़ी भूमिका निभाई है। ग्रामीण विकास और पलायन आयोग की रिपोर्ट 2025 के अनुसार 6000 से अधिक प्रवासी अपने गांवों में लौटकर अधिकांश होमस्टे का स्वरोजगार कर रहे हैं।

आमने

आपने भारत बेच दिया है। क्या आपको भारत बेचने में शर्म नहीं आती? आपने हमारी मां, भारत माता को बेच दिया है। आपको पता है उन्होंने भारत क्यों बेचा? क्योंकि वे उनका गला घोंट रहे हैं। उन्होंने उनकी गर्दन पकड़ रखी है। हम प्रधानमंत्री की आंखों में डर देख सकते हैं।

–राहुल गांधी
नेता प्रतिपक्ष

सामने

आपने कहा कि इन्होंने देश बेच दिया, पर मैं कहना चाहता हूं कि आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, जो देश को बेच सके और न कोई है जो हमारे देश को खरीद सके। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश के अब तक के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं।

–किरेन रिजिजू
संसदीय कार्यमंत्री

बजट: चुनावी रेवड़ियों की जगह मजबूत रोडमैप

मनोज त्रिपाठी
कानपुर

उत्तर प्रदेश में 2027 के पूर्वार्द्ध में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इसके बावजूद योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट उम्मीदों के विपरीत चुनावी घोषणाओं, लोक लुभावन योजनाओं और मुफ्त की रेवड़ियों से परहेज करता हुआ जनता के उस विश्वास का दस्तावेज जैसा लगता है, जिसे सरकार ने नौ सालों में पूरी शिद्दत के साथ अर्जित किया है। इसी कारण वित्तीय वर्ष 2026-27 का सरकार का बजट जो कि 9,12,696 करोड़ रुपये के साथ आकार में अब तक का सबसे बड़ा है, वित्तीय लेखा-जोखा से ज्यादा, सरकार की आर्थिक सोच, राजनीतिक प्राथमिकताओं और प्रशासनिक क्षमताओं का बखान करने के साथ स्वाभाविक रूप से महत्वाकांक्षी और रणनीतिक रहते हुए विकसित यूपी का रोडमैप प्रस्तुत करता है।

यदि समग्र आकार और संरचना पर नजर डालें, तो यह बजट पिछले वर्षों की तुलना में अधिक विस्तारवादी है। कुल परिव्यय पिछले साल की तुलना में करीब 12.2 फीसदी ज्यादा है। इसके साथ ही वित्तीय अनुशासन और पूंजीगत खर्च बढ़ाने पर खास फोकस है। पूंजीगत व्यय (कैपिटल एक्सपेंडिचर) में वृद्धि के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि प्रदेश केवल कल्याणकारी योजनाओं पर ही नहीं, बल्कि दीर्घकालिक बुनियादी ढांचे पर भी निवेश कर रहा है। एक्सप्रेस-वे, मेट्रो विस्तार, डिफेंस कॉरिडोर, औद्योगिक पार्क, एग्री-एक्सपोर्ट हब, नए मेडिकल कॉलेज, एआई मिशन, प्लेसमेंट सेंटर्स आदि, ये सब मिलकर उस नए उत्तम प्रदेश की तस्वीर पेश करते हैं, जिसे सरकार निवेश-हितैषी और आधुनिक बनाना चाहती है, हालांकि पूंजीगत व्यय के साथ राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखना आसान नहीं होता। यदि राज्य का कर्ज अनुपात बढ़ता है, तो भविष्य की पीढ़ियों पर बोझ बढ़ सकता है। सरकार ने इसे लेकर संतुलन का दावा किया है, लेकिन वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और केंद्र से मिलने वाले अनुदान पर निर्भरता को देखते हुए उसे वित्तीय प्रबंधन की परीक्षा देना अभी बाकी है।

सरकार जब प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय एक लाख 20 हजार होने और छह करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का आंकड़ा पेश करती है, तो यह बताना नहीं भूलती कि अर्थव्यवस्था का हाल पहले क्या था और किस तरह वह राज्य की अर्थव्यवस्था को एक डॉलर ट्रिलियन बनाने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। इसी क्रम में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का यह बताना कि उत्तर प्रदेश देश की तीन टॉप अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में प्रदेश की रैंकिंग 2018-19 में 29वें स्थान से सुधरकर 2023-24 में 18वें स्थान पर पहुंच गई है।

फरवरी 2024 में आयोजित चौथे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में करीब 50 लाख करोड़ रुपये के एमओयू साइन हुए हैं, जिनसे लगभग 10 लाख रोजगार पैदा होने की संभावना है। अब तक 16 हजार से ज्यादा परियोजनाओं के लिए लगभग 15 लाख करोड़ रुपये के निवेश के साथ चार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी हैं, तो योगी सरकार के इसी दावे पर मुहर लगती है कि उसके पिछले और वर्तमान कार्यकाल में प्रदेश का सर्वांगीण विकास हुआ है, चाहे कानून व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हो, अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार हो, औद्योगिक निवेश या रोजगार सृजन हो, महिलाओं का सशक्तीकरण हो या युवाओं का कौशल संवर्धन, किसानों की खुशहाली हो या गरीबी उन्मूलन। इन सारी बातों से सरकार यही संदेश हर किसी तक पहुंचाना चाहती है कि अब तक की बदलाव की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए इस बार का बजट भी प्रदेश के संतुलित विकास, विशेषकर युवाओं और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित है, ताकि राज्य को देश की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाया जा सके।

बजट का सबसे बड़ा हिस्सा बुनियादी ढांचे के लिए आवंटित किया गया है। विशेष रूप से सड़कों और फ्लाईओवर के निर्माण पर 34,468 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इससे प्रदेश में एक्सप्रेसवे, मुख्य राजमार्ग, बाईपास, ग्रामीण सड़कों और पुलों के विस्तार पर तेजी से काम होगा। फिलहाल प्रदेश में सात एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक दौड़ रहा है, तीन एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन हैं। अब चार और नए एक्सप्रेसवे बनने की घोषणा से सरकार का इरादा साफ है कि प्रदेश के हर जिले को बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए, ताकि परिवहन सुविधाएं मजबूत हों और आर्थिक गतिविधियां बढ़ें, क्योंकि यही वह बिंदु है, जिससे लोगों में विकास होने की आम राय बनती है।

निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। बेहतर सड़क नेटवर्क से औद्योगिक क्षेत्रों तक माल की ढुलाई आसान होने से लॉजिस्टिक्स लागत कम होती है और व्यापार-कारोबार बढ़ता है। इसी तरह ग्रामीण इलाकों में सड़कों के विस्तार से किसानों की बाजार तक पहुंच आसान होने से उनकी आय में सुधार आ सकता है। बजट का दूसरा सबसे प्रमुख हिस्सा टेक्नोलॉजी और एआई मिशन है, जिसमें राज्य को आईटी हब बनाने का संकल्प है।

यूपी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट उम्मीदों के विपरीत चुनावी घोषणाओं से परहेज करता हुआ जनता के विश्वास का दस्तावेज जैसा लगता है।

सोशल फोरम

फिर चित्रा ने नहीं गाया

1975-76 के लगभग जगजीत-चित्राजी का पहला LP रिकार्ड Unforgettables आया, उसके बाद ही हिंदुस्तान में ही नहीं, एक हद तक पाकिस्तान में भी गज़ल गायकी का जैसे ट्रेंड ही बदल गया। उस समय ग़ज़ल गायकी में ग्रेट मेंहदी हसन बहुत बड़ा नाम थे और भारत में तलत महमूद थे और भी बड़े-बड़े शास्त्रीय ग़ज़ल गायक थे

रश्मि त्रिपाठी
ब्लॉगर

उस दौर के, किंतु जगजीत सिंह एक ऐसा नाम उभरा जो जीवन का अंत होने के समय तक निरंतर शोहरत की बुलंदियों पर चढ़ता चला गया। बिना इस बात की परवाह किए कि बाकी गायक कितने बड़े और शोहरतमंद हैं?

अपनी सरल गायकी और मखमली आवाज़ के बल पर जगजीत सिंह न केवल खुद जन-जन के प्रिय होते चले गए, अपितु उन्होंने ग़ज़ल को भी अपार लोकप्रियता दिलाई। ग़ज़ल जो कुछ 'एलीट क्लास' की बैठकों के शौकीनों की शोभा मात्र हुआ करती थीं, अब आम लोगों में गुनगुनाने की चीज़ बन गई। बात यहां तक आ गई कि लोकप्रिय फिल्मी गीतों की तुलना में भी जगजीत जी को अधिक शोहरत मिलने लगी।

कुछ वर्षों के इस सफर के बाद जगजीत सिंह को हिंदी सिनेमा में गाने का मौका भी मिल गया। 'तुम इतना जो मुस्करा रहे हो' या फिर 'होठों से छू लो तुम,मेरा गीत अमर कर दो' जैसे अनेक कालजयी फिल्मी गाने जगजीत सिंह की गायकी और उन्हीं की मौसिक़ी से निकले थे। इससे पहले 1967 में जब जगजीत काम ढूंढ रहे थे, तब उनकी मुलाकात चित्रा दत्ता से हुई। चित्रा उस वक्त शादीशुदा थीं। वो मुंबई में जहां रहती थीं। उनके सामने वाले घर में जगजीत का आना-जाना लगा रहता था और यहीं पर दोनों की मुलाकात हुई थी।

धीरे धीरे वे एक-दूसरे को पसंद करने लगे थे और अलग सी बात ये थी कि जगजीत ने उनके पति देबू प्रसाद दत्ता से उन्हे मांग लिया था। दिसंबर 1969 में चित्रा ने अपने पति को तलाक देकर जगजीत सिंह से शादी कर ली। कहते हैं कि देबू दत्ता का भी कहीं और अफेयर था, इसलिए उनको भी तलाक में सुविधा हो गई।

चित्रा-जगजीत दोनों एक साथ एक के बाद एक कॉन्सर्ट लगातार करते जा रहे थे। शोहरत-दौलत दिन-दूनी रात चौगुनी बढ़ती गई। साल 1980 तक जगजीत सिंह गजल किंग बन चुके थे। इसी समय उनके एक मात्र पुत्र विवेक की 1990 में एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। दोनों ने गाना छोड़ दिया। कुछ दिन बाद जगजीत सिंह तो रोमांटिक न सही, लेकिन थोड़े बदले मिज़ाज़ के गीत-गजल गाने लगे, लेकिन चित्रा ने फिर नहीं गाया। **–फेसबुक वॉल से**

सामयिकी

ईयू-यूएस से व्यापारिक समझौता सुनहरा मौका

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के तहत अब भारतीय निर्यातकों को 50 प्रतिशत शुल्क के स्थान पर सिर्फ 18 प्रतिशत शुल्क ही देना होगा, किंतु यह भी सत्य है कि पहले यह शुल्क मात्र 2.9 प्रतिशत ही था। यह दोनों समझौते भारत को विश्व पटल पर मजबूत स्थिति में खड़ा होने का अवसर प्रदान करते हैं। यदि भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौते को सभी समझौतों की जननी कहा जा सकता है, तो भारत-अमेरिका व्यापार समझौता सभी समझौतों का जनक माना जा सकता है। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाया जाने वाला शुल्क अब 18 प्रतिशत रह जाएगा, हालांकि भारतीय यूरोपीय संघ समझौता अपने आप में महत्वपूर्ण है, किन्तु भारत द्वारा अपने सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार अमेरिका से निर्यात को विविधतापूर्ण बनाना भी एक कठिन प्रयास था, जिसमें भारत को अंततः सफलता प्राप्त हुई। यह समझौता

प्रो. रिपुदमन सिंह
शिक्षाविद्

न केवल भारत की व्यापार स्थिति को बहाल करेगा, बल्कि दशकों पुराने भारत-अमेरिका राजनयिक संबंधों को भी मजबूत करेगा, जिनमें हाल ही में तनाव के संकेत दिखाई दिए थे।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते ने भारतीय उद्योगों को राहत की सांस लेने का मौका प्रदान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का यह दावा कि अब भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा भी चुनौतीपूर्ण है, भारत को इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि रूसी तेल पूरी तरह बंद करने पर भारत को अपने एक तिहाई तेल की आपूर्ति के लिए विकल्प तलाशना होगा तथा रूस के साथ भारत के संबंध पर भी असर पड़ेगा। रूस भारत का लंबे समय से मित्र और रक्षा उपकरणों का महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता है। यह कदम भारत के लिए संबंधों को पुनर्गठन करने जैसा होगा। इसी तरह वेनेजुएला से अधिक कच्चा तेल खरीदना शोधन संबंधी चुनौतियां उत्पन्न करेगा।

इसके अतिरिक्त यह भी विचारणीय है कि भारत ने अमेरिका को टैरिफ रियायतों निवेशों और खरीद आदेशों के संदर्भ में क्या प्रतिबद्धतायें निर्धारित की हैं, क्योंकि ट्रंप और उनकी टीम, संवेदनशील कृषि उत्पादों और डेयरी उत्पादों के आदान-प्रदान किए जाने का दावा कर रहे हैं। भारतीय वाणिज्य मंत्री ने ट्रंप के इस दावे पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी है, लेकिन अमेरिकी व्यापार समझौते ने एक उम्मीद की किरण तो दी है, क्योंकि इससे शेयर बाजारों में तेजी आई है, रुपये को मजबूती मिली है और कपड़ा, परिधान, चमड़ा, जूते और इंजीनियरिंग सामान जैसे श्रम प्रधान उद्योगों में उत्साह का माहौल है।

व्यापार के मोर्चे पर भारत के वस्त्र और चमड़ा निर्यातकों को त्वरित लाभ मिलने की संभावना है। वर्तमान में खेल सामग्री, रत्न और आभूषणों के निर्यातकों को उच्च टैरिफ के चलते कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था और यह निर्यातक 10-20 प्रतिशत तक नुकान उठा रहे थे। यह डैडम् क्षेत्र में रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। भारत वस्त्र और परिधान का 28 प्रतिशत निर्यात अमेरिका को करता है, जो भारतीय चमड़े और खेल सामग्री का भी बहुत बड़ा बाजार है। भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौता भारत के इतने बड़े निर्यात को इतनी जल्दी समायोजित करने की स्थिति में संभवतः नहीं था, किंतु एक वैकल्पिक व्यवस्था बनने की स्थिति में जरूर आगे आ सकता है। अमेरिकी रणनीतिकार संभवतः इसी संभावना को भांपने में सफल रहे हैं और भारत-अमेरिका समझौते को अति शीघ्र लागू करने के लिए तत्पर हो गए हैं। भारत-अमेरिका व्यापार समझौता का एक व्यापक रणनीतिक उद्देश्य भी है, यह द्विपक्षीय संबंधों में सामान्य स्थिति बहाल करने में भी मदद करेगा, जो नागरिक परमाणु समझौते के बाद से लगातार मजबूत होते गए हैं।

स्वामी-रुहेलखंड इंटरप्राइजेज के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक हरि ओम गुप्ता द्वारा अमृत विचार प्रकाशन, नवादा जोगियान, चक रोड, रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज के सामने, बरेली (उ.प्र.), पिन कोड-243006 से मुद्रित एवं 932 कटरा चांद खां, भारत पेट्रोल पंप के सामने पीलीभीत बाईपास रोड बरेली (उ.प्र.) पिन कोड-243005 से प्रकाशित। **संपादक- राजेश श्रीनेत, स्थानीय संपादक- नवीन गुप्ता*** 0581-4000222 (कार्यालय), ईमेल- editorschoice@amritvichar.com, आर.एन.आई नं0-UPHIN/2019/78502, *इस अंक में प्रकाशित समाचार के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट की धारा 7 के अंतर्गत उत्तरदायी। (नोट-सभी विवादों का न्यायक्षेत्र बरेली होगा)।

कैम्पस

75% कॉलेज छात्रों को नहीं दे पा रहे जॉब वाली स्किल्स

राजेश जैन
लेखक

भारत में हर साल लाखों युवा बड़े सपनों के साथ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं। परिवार उम्मीद करता है कि चार साल की पढ़ाई के बाद बच्चा अच्छी नौकरी पाएगा, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेगा और समाज में सम्मान पाएगा, लेकिन आज की सच्चाई यह है कि डिग्री मिलने के बाद भी नौकरी मिलना किसी जुए से कम नहीं रह गया है। टीमलीज एडटेक की ताजा रिपोर्ट बताती है कि भारत के करीब 75 प्रतिशत कॉलेज और विश्वविद्यालय अपने छात्रों को जॉब-रेडी स्किल्स देने में नाकाम हो रहे हैं। यानी डिग्री तो मिल रही है, लेकिन नौकरी के लायक नहीं है। यह सिर्फ शिक्षा व्यवस्था की विफलता नहीं, बल्कि देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।

डिग्री की फैक्ट्रियां बनते जा रहे हैं कॉलेज

आज बड़ी संख्या में संस्थान सिर्फ डिग्री बांटने वाली फैक्ट्रियों में बदल चुके हैं। क्लासरूम में थ्योरी पढ़ाई जाती है, पुराने सिलेबस रटाए जाते हैं, लेकिन असली दुनिया की जरूरतों से छात्रों का कोई संपर्क नहीं होता। नतीजा यह होता है कि छात्र पास होकर निकलते हैं, लेकिन उन्हें यह तक नहीं पता होता कि इंडस्ट्री उनसे क्या चाहती है। आज कंपनियों को ऐसे युवा चाहिए जो टेक्नोलॉजी समझते हों, कम्युनिकेशन में मजबूत हों, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकें, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखते हों, लेकिन ज्यादातर कॉलेज इन स्किल्स पर काम ही नहीं करते।

प्लेसमेंट का कड़वा सच

कागजों में कई संस्थान 100 प्रतिशत प्लेसमेंट का दावा करते हैं, लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। रिपोर्ट के अनुसार, सिर्फ 16.67 प्रतिशत संस्थान ही ऐसे हैं, जो अपने 76 प्रतिशत से 100 प्रतिशत छात्रों को छह महीने के भीतर नौकरी दिला पाते हैं। बाकी छात्रों को या तो बहुत कम सैलरी वाली नौकरी मिलती है या फिर वे बेरोजगार घूमते रहते हैं या किसी दूसरे कोर्स की तैयारी करने लगते हैं। यह स्थिति उन माता-पिता के लिए भी चिंता का विषय है, जो भारी फीस भरकर बच्चों को प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ाते हैं। इंडस्ट्री और पढ़ाई के बीच गहरी खाई आज की शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यही है कि पाठ्यक्रम और उद्योग की जरूरतों में तालमेल नहीं है। रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ 8.6 प्रतिशत संस्थानों के कोर्स पूरी तरह इंडस्ट्री-फ्रेंडली हैं, 51 प्रतिशत से ज्यादा संस्थानों का उद्योग से कोई तालमेल ही नहीं। मतलब आधे से ज्यादा कॉलेज ऐसे हैं, जहां पढ़ाया कुछ और जाता है और नौकरी में चाहिए कुछ और।

क्लासरूम में इंडस्ट्री का अनुभव नदारद

अगर कॉलेजों में इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स पढ़ाएं, तो छात्रों को असली दुनिया की समझ मिले, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ 7.56 प्रतिशत संस्थानों में ही 'प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस' जैसे इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को शामिल किया गया है। बाकी जगह वही पुराने प्रोफेसर, वही पुराने नोट्स, वही पुरानी थ्योरी। छात्रों को यह नहीं बताया जाता कि आज जॉब मार्केट कैसे बदल रहा है, नई भूमिकाएं क्या हैं, कंपनियां किस तरह की स्किल्स ढूंढ रही हैं।

सर्टिफिकेट्स से दूरी

आज कंपनियां सिर्फ डिग्री नहीं देखतीं, वे मान्यता प्राप्त इंडस्ट्री सर्टिफिकेट्स को भी महत्व देती हैं। जैसे-एआई और डेटा साइंस सर्टिफिकेट, डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक, 60 प्रतिशत से ज्यादा संस्थानों ने इन सर्टिफिकेट्स को अपने कोर्स में शामिल करने पर कभी सोचा ही नहीं। नतीजा ये हुआ छात्र ऐसे स्किल्स के बिना ग्रेजुएट होते हैं, जिन्हें कंपनियां तुरंत पहचान सकें।

इंटर्नशिप: नाम की, काम की नहीं

नौकरी से पहले इंटर्नशिप सबसे जरूरी कदम होती है। यहीं से छात्र सीखते हैं-ऑफिस कल्चर, टीमवर्क, असली प्रोजेक्ट पर काम, लेकिन भारत में सिर्फ 9.4 प्रतिशत संस्थानों में सभी कोर्स के लिए अनिवार्य इंटर्नशिप होती है और 37.8 प्रतिशत संस्थानों में इंटर्नशिप की कोई व्यवस्था ही नहीं है। यानी लाखों छात्र बिना किसी प्रैक्टिकल अनुभव के सीधे जॉब मार्केट में उतर जाते हैं। फिर कंपनियां कहती हैं-आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है।

लाइव प्रोजेक्ट्स भी गायब

लाइव इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स छात्रों को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाते हैं, लेकिन सिर्फ 9.68 प्रतिशत संस्थानों में ही ऐसे प्रोजेक्ट कराए जाते हैं। बाकी जगह थ्योरी पढ़ाओ, एग्जाम लो, डिग्री दो और मामला खत्म।

एलुमनाई नेटवर्क की कमजोरी

पूर्व छात्र किसी भी संस्थान की ताकत होते हैं। वे मेंटरशिप दे सकते हैं, रेफरल दिला सकते हैं, जॉब के मौके खोल सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ 5.44 प्रतिशत संस्थानों के पास सक्रिय एलुमनाई नेटवर्क है। यानी कॉलेज अपने ही पुराने छात्रों की ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे।

इसका असर सिर्फ छात्रों पर नहीं, देश पर भी-जब युवा बेरोजगार रहते हैं, तो इसका असर सिर्फ परिवार पर नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। उत्पादकता घटती है, मानसिक तनाव बढ़ता है, स्किल गैप बढ़ता है, माइग्रेशन बढ़ता है, डिग्रीधारी बेरोजगारी, देश के लिए सबसे खतरनाक संकेतों में से एक है।

यह है समाधान

रिपोर्ट साफ कहती है कि अब बदलाव विकल्प नहीं, मजबूरी है। इसके लिए इंडस्ट्री-अनुकूल सिलेबस, अनिवार्य इंटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की भागीदारी, सर्टिफिकेट कोर्स, मजबूत एलुमनाई नेटवर्क, कॉलेजों को सिर्फ पढ़ाने की नहीं, रोजगार दिलाने की जिम्मेदारी लेनी होगी।

सरकार की भूमिका भी अहम

नई शिक्षा नीति सही दिशा में कदम है, लेकिन जमीन पर उसका असर अभी सीमित है। सरकार को चाहिए कि कॉलेजों की जवाबदेही तय करे, प्लेसमेंट डेटा पब्लिक करे, स्किल-बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा दे, इंडस्ट्री पार्टनरशिप अनिवार्य बनाए, छात्रों को भी जागरूक होना होगा। आज का छात्र सिर्फ डिग्री पर निर्भर नहीं रह सकता। उसे खुद भी ऑनलाइन स्किल्स सीखनी होंगी, इंटर्नशिप ढूंढनी होगी, नेटवर्क बनाना होगा, इंडस्ट्री ट्रेंड समझना होगा। अगर भारत की हायर एजुकेशन सिस्टम आज नहीं सुधरा तो आने वाले सालों में डिग्रियों की भीड़ होगी, लेकिन नौकरियों की कमी। यह संकट सिर्फ शिक्षा का नहीं, राष्ट्र निर्माण का संकट है। अब वक्त है डिग्री फैक्ट्रियों को रोजगार केंद्रों में बदलने का।

वर्ड स्मिथ

कैसे बना शैंपू शब्द

आज शैंपू हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक सामान्य शब्द बन चुका है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका जन्म भारत में हुआ और यह शब्द हिंदी-उर्दू नहीं, बल्कि संस्कृत मूल से होकर अंग्रेजी तक पहुंचा। 'शैंपू' शब्द की कहानी औपनिवेशिक भारत, आयुर्वेद और पश्चिमी संस्कृति के आपसी संपर्क से जुड़ी है। 'शैंपू' शब्द की जड़ संस्कृत के शब्द 'चम्पू' (Champu) में मिलती है। 'चम्पू' का अर्थ होता है-दबाना, मलना या मालिश करना। प्राचीन भारत में सिर और शरीर की तेल मालिश को 'चम्पू' कहा जाता था। यह केवल सौंदर्य का नहीं, बल्कि स्वास्थ्य का भी महत्वपूर्ण हिस्सा था। आयुर्वेद में सिर की मालिश को तनाव दूर करने, रक्तसंचार बढ़ाने और बालों को स्वस्थ रखने का प्रभावी उपाय माना गया है।

17वीं-18वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश व्यापारी और अधिकारी भारत आए, तो उन्होंने यहां की मालिश और स्नान पद्धतियों को देखा। बंगाल में 'चम्पू' एक प्रचलित प्रक्रिया थी, जिसमें जड़ी-बूटियों और प्राकृतिक तत्वों से सिर की सफाई और मालिश की जाती थी। अंग्रेजों ने इस शब्द को अपने उच्चारण के अनुसार 'Shampoo' कहना शुरू कर दिया। सन 1762 में यह शब्द पहली बार अंग्रेजी शब्दकोश में दर्ज हुआ। शुरुआत में 'शैंपू' का अर्थ केवल सिर की मालिश या शरीर को मलने की क्रिया था, न कि किसी तरल पदार्थ का नाम। बाद में, 19 वीं शताब्दी में जब तरल साबुन और बाल धोने वाले उत्पाद विकसित हुए, तब इस प्रक्रिया से जुड़े उत्पाद को ही 'शैंपू' कहा जाने लगा। इस प्रकार, 'शैंपू' केवल एक कॉस्मेटिक उत्पाद नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की देन है, जो संस्कृत से चलकर औपनिवेशिक रास्तों से होती हुई पूरी दुनिया की भाषाओं में शामिल हो गई। यह शब्द हमें याद दिलाता है कि भारतीय परंपराओं का वैश्विक प्रभाव कितना गहरा और स्थायी रहा है।

नोटिस बोर्ड

- बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उन्हें रोजगार पाने के लिए बहुत जल्द सुनहरा अवसर मिलेगा। जिला सेवा योजन विभाग, अमेठी की ओर से 26 फरवरी को आरआरपीजी कॉलेज में वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 50 से अधिक नामी कंपनियां प्रतिभाग करेंगी। मेले के माध्यम से 2000 से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। मेले में कक्षा आठवीं पास से लेकर स्नातक, परास्नातक, बीटेक, आइटीआइ और पॉलिटेक्निक उत्तीर्ण युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार पाने का अवसर मिलेगा। निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियों के प्रतिनिधि मौके पर ही साक्षात्कार लेकर चयन प्रक्रिया पूरी करेंगे। इच्छुक अभ्यर्थी अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा साथ ले जाएं।

- बरेली कॉलेज के ललितकला विभाग ने बीए प्रथम सेमेस्टर चित्रकला विषय की प्रयोगात्मक परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। विभागीय सूचना के अनुसार बैक और रेगुलर दोनों श्रेणी के विद्यार्थियों की परीक्षा 14 फरवरी को सुबह 10 बजे से आयोजित की जाएगी। परीक्षा ललितकला विभाग में ही संपन्न होगी। विभाग के प्रभारी प्रो. एबीएल. लखटकिया ने छात्रों को निर्देश दिए हैं कि वे परीक्षा के दिन निर्धारित समय से कम से कम आधा घंटा पहले विभाग में उपस्थित रहें, ताकि सभी आवश्यक औपचारिकताएं समय पर पूरी की जा सकें और परीक्षा प्रक्रिया सुचारु रूप से संचालित हो।

कैंपस में पहला दिन

जीवन को सोचने व समझने की यात्रा

कृष्णा चौहान
बीएससी छात्रा, एसएस कॉलेज, शाहजहांपुर

आज भी स्मृतियों में किसी ताजी सुबह की तरह कॉलेज का पहला दिन चमकता है। स्कूल की सुरक्षित और जानी-पहचानी दुनिया से निकलकर बीएससी की छात्रा के रूप में कॉलेज की देहरी पर कदम रखना मेरे लिए उत्साह और संकोच दोनों का मिला-जुला अनुभव था। हाथ में नई फाइल, कंधे पर बैग और मन में अनगिनत सवाल, क्या मैं यहां अपने सपनों के करीब पहुंच पाऊंगी?

कॉलेज का विशाल परिसर देखते ही मन आश्चर्य से भर उठा। ऊंची इमारतें, हरे-भरे पेड़, भागते हुए छात्र, कहीं हंसी की आवाजें तो कहीं गंभीर चेहरों पर किताबों का बोझ, सब कुछ नया था। विभाग की ओर बढ़ते कदमों के साथ दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। बीएससी की छात्रा होने का गर्व तो था, लेकिन साथ ही यह डर भी कि विज्ञान जैसे गंभीर विषय को संभाल पाऊंगी या नहीं। पहली कक्षा का अनुभव कभी नहीं भूल सकती। प्रयोगशाला में रखे चमकते उपकरण, रसायनों की हल्की गंध और दीवारों पर टंगे वैज्ञानिकों के चित्र मुझे एक अलग ही दुनिया में ले गए। जब पहली बार अध्यापक ने अपना परिचय दिया और विषय की महत्ता समझाई, तब महसूस हुआ कि यह सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि जीवन के सोचने और समझने की एक नई यात्रा है। सबसे सुकून देने वाला पल तब आया, जब कुछ अनजान चेहरे मुस्कान में बदल गए। पास बैठी छात्रा से हुई छोटी-सी बातचीत दोस्ती की शुरुआत बन गई। लगा जैसे डर धीरे-धीरे आत्मविश्वास में बदल रहा हो। कैंटीन की पहली चाय और हल्की-फुल्की बातचीत ने उस दिन को और यादगार बना दिया।

शाम को कॉलेज से लौटते समय मन में थकान नहीं, बल्कि एक अजीब-सी खुशी थी। लगा, जैसे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है। आज जब पीछे मुड़कर देखती हूं, तो समझ में आता है कि वह पहला दिन सिर्फ कॉलेज का नहीं था, बल्कि मेरे आत्मनिर्भर बनने की दिशा में पहला कदम था, जो आज भी मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।

करेंट अफेयर्स

- हाल ही में सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में संशोधन को आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दिया है, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए नियम और कड़े हो गए हैं। संशोधित आईटी नियम 2021 के तहत अब एआई-जनित (AI-generated) सामग्री पर "स्पष्ट और प्रमुख" लेबल लगाना अनिवार्य होगा और अवैध सामग्री हटाने की समय-सीमा 36 घंटे से घटाकर केवल तीन घंटे कर दी गई है। ये बदलाव 20 फरवरी 2026 से लागू होंगे।
- भारत और सेशेल्स के द्विपक्षीय संबंध एक नए रणनीतिक स्तर पर पहुंचा गए हैं। हाल ही में सेशेल्स के राष्ट्रपति की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने सततता, आर्थिक विकास और सुरक्षा के लिए सुदृढ़ संपर्कों के माध्यम से संयुक्त दृष्टि (SESEL) की घोषणा की। यह पहल हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका और एक करीबी समुद्री साझेदार के रूप में सेशेल्स के महत्व को रेखांकित करती है, जिसमें सुरक्षा, विकास और जन-केंद्रित सहयोग को केंद्र में रखा गया है।
- हाल ही में नीति आयोग ने आंध्र प्रदेश के लिए एक महत्वाकांक्षी स्वच्छ ऊर्जा योजना पेश की है। इस नीति ब्लूप्रिंट का उद्देश्य वर्ष 2035 तक आंध्र प्रदेश को भारत के प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा हब में बदलना है। घटती बिजली लागत और बड़े क्षमता विस्तार के साथ आंध्र प्रदेश को भविष्य में देश के लिए स्वच्छ ऊर्जा निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित किया जा रहा है।
- हाल ही में वैश्विक खेल प्रशासन के लिए एक ऐतिहासिक घटनाक्रम में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) ने ईरान से अपनी पहली महिला सदस्य का चुनाव किया है। ईरानी बैडमिंटन खिलाड़ी सोरया अघाई हाजिआगहा को 4 फरवरी इटली के मिलान में आयोजित 145 वें IOC सत्र के दौरान निर्वाचित किया गया। इस चुनाव के साथ ही वे IOC की वर्तमान सबसे कम उम्र की सदस्य भी बन गई हैं।
- भारत की स्टार निशानेबाज मनु भाकर ने नई दिल्ली में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। यह उपलब्धि उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में सातवां स्थान हासिल करने के पांच दिन बाद दर्ज की। डबल शूट-ऑफ के बीच मनु ने मानसिक मजबूती दिखाते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। यह 25 मीटर पिस्टल में उनका पहला व्यक्तिगत सिल्वर मेडल है।

जॉब अलर्ट

एम.पी. राज्य सहकारी बैंक

- पद का नाम-कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर (संविदा), सोसायटी मैनेजर, अधिकारी
- पदों की संख्या- (1763 क्लर्क + 313 अधिकारी) 2076 पद
- सैलरी/पे स्केल क्लर्क : लेवल-4 (Rs. 19,500-62,000) 7 वां पे स्केल / लेवल-7 (Rs. 28,700-91,300) / 6 वां पे स्केल (Rs. 5,200-20,200 + 1900 GP)
- शैक्षणिक योग्यता-स्नातक
- आयु सीमा -18 से 35 वर्ष (40 वर्ष छूट के साथ), कंप्यूटर ऑपरेटर (संविदा) : 18 से 55 साल
- आवेदन की अंतिम तिथि- 20 फरवरी 2026
- वेबसाइट-www.apexbankmp.bank.in

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग

- पद का नाम- ग्रुप सी पदों के लिए भर्ती (विभिन्न विभाग / बोर्ड / निगम)
- सीईटी ग्रुप सी पर आधारित- विज्ञापन नंबर 01/2025 क्वॉलिफाइड कैंडिडेट
- पदों कि संख्या -4227
- एप्लीकेशन शुरू होने की तारीख- 9 फरवरी 2026
- आवेदन की अंतिम तिथि- 23 फरवरी 2026
- ऑफिशियल वेबसाइट www.hssc.gov.in

सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

- पद का नाम- डिप्टी जनरल मैनेजर (इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स), डिप्टी जनरल मैनेजर (माइक्रोवेव), दूसरे पोस्ट (डिप्टी इंजीनियर, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, वगैरह
- पदों की संख्या- 34
- विज्ञापन नंबर 118/Pers/1/2026
- सैलरी- Rs.17,500 - 2,20,000/- हर महीने
- क्वालिफिकेशन- B.E./B.Tech / MBA / CA/ ICWA / ग्रेजुएट / 10th
- एज लिमिट- पदानुसार
- आवेदन की अंतिम तिथि- 3 फरवरी 2026
- वेबसाइट- https://www.celindia.co.in

बोर्ड परीक्षा से पहले सफलता का स्मार्ट स्टडी प्लान

डॉ. मनोज कुमार तिवारी
बीएचयू

बीते दिनों परीक्षा पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कुशल मनोवैज्ञानिक की भांति विद्यार्थियों से परीक्षा पर चर्चा की, उन्होंने सीधे परीक्षा तनाव पर चर्चा करने के बजाय छात्रों के जीवन व उनके क्षेत्र से संबंधित विभिन्न आयामों पर चर्चा की, जिससे छात्र उनसे सीधे जुड़ सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर छात्र अद्वितीय हैं, उनकी अपनी क्षमता, विशेषता, जीवनशैली, सोचने-समझने का ढंग अलग-अलग होता है, इसलिए विद्यार्थियों का परीक्षा की तैयारी का तरीका अलग-अलग हो सकता है। उन्होंने छात्रों से कहा कि अपनी परीक्षा की तैयारी अपने ढंग से करनी चाहिए, सभी के सुझाव को सुनना चाहिए, किंतु अपनी तैयारी का पैटर्न अपने अनुभव के अनुसार तय करना चाहिए। यूपी बोर्ड एग्जाम के कुछ दिन ही शेष रह गए हैं।

इन दिनों में परीक्षार्थियों को विशेष ध्यान रखते हुए परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। आइए आज आपको बताते हैं, कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी सुझाव, जिन्हें अपनाकर आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं।

सिलेबस के अनुसार बनाएं स्टडी प्लान

सबसे पहले एक सरल और व्यावहारिक टाइम टेबल तैयार करें। यह बहुत जटिल नहीं होना चाहिए। दिन के अलग-अलग समय के अनुसार विषय तय करें। सुबह का समय पढ़ाई के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, इसलिए इस समय कठिन विषयों का अध्ययन करें। दोपहर में हल्के टॉपिक और शाम के समय रिवीजन पर ध्यान दें।

जरूरी टॉपिक पर करें फोकस

जब बोर्ड परीक्षा में कुछ ही दिन शेष हों, तब नया पाठ्यक्रम शुरू करने के बजाय महत्वपूर्ण अध्यायों पर ध्यान देना समझदारी है। सिलेबस में शामिल मुख्य चैप्टर और पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों का विश्लेषण करें। जिन टॉपिक से बार-बार प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें अच्छी तरह तैयार करें। अगर कोई अध्याय पूरा नहीं आता है, तो उसे छोड़ने के बजाय उसके आसान हिस्सों को जरूर पढ़ लें।

प्रश्नों की लिखकर करें प्रैक्टिस

पढ़ी हुई सामग्री को बार-बार दोहराना बहुत जरूरी है। रोजाना कम से कम एक बार रिवीजन करें। साथ ही लिखकर अभ्यास करने से उत्तर लेखन की गति बढ़ती है और परीक्षा के समय समय-प्रबंधन में मदद मिलती है। गणित, विज्ञान और अकाउंट्स जैसे विषयों में यह तरीका विशेष रूप से लाभकारी होता है।

मॉक टेस्ट देना न भूलें

पुराने प्रश्नपत्र और फुल मॉक टेस्ट बोर्ड परीक्षा की तैयारी का सबसे बेहतर साधन हैं। छात्रों को सप्ताह में कम से कम दो से तीन फुल-लेंथ मॉक टेस्ट देने चाहिए। इससे परीक्षा के माहौल की आदत बनती है। टेस्ट के बाद अपनी गलतियों को समझें और उन्हें सुधारने पर काम करें।

तनाव से दूर रहें, बनाए रखें आत्मविश्वास

परीक्षा से पहले घबराहट होना स्वाभाविक है, लेकिन अत्यधिक तनाव पढ़ाई पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। छात्रों को खुद पर भरोसा रखना चाहिए। पूरे साल की गई मेहनत अंतिम समय में जरूर रंग लाएगी।

बाजार	सेंसेक्स ↓	निफ्टी ↑
बंद हुआ	84,233.64	25,953.85
गिरावट/बढ़त	40.28	18.70
प्रतिशत में	0.05	0.07

सोना 1,61,300 प्रति 10 ग्राम

चांदी 2,68,500 प्रति किलो

अमृत विचार

बरेली, गुरुवार, 12 फरवरी 2026

www.amritvichar.com

कारोबार

बरेली मंडी

वनस्पति तेल तिलहन : तुलसी 2610, राज श्री 1940, फ़ॉर्चून कि. 2425, रविन्द्रा 2515, फॉर्चुन 13 किग्रा 2145, जय जवान 2125, सचिन 2120, सूरज 2125, अवसर 1865, उजाला 1920, गृहणी 13 किग्रा 1975, क्लासिक (किग्रा) 2325, मोर 2320, चक्र टिन 2375, ब्लू 2215, आशीर्वाद मस्टर्ड 2420, स्वास्तिक 2565

किराना : हल्दी निजामाबाद 17000, जीरा 24500, लाल मिर्च 18000-23000, धनिया 9400-12000, अजवायान 13500-20000, मेथी 6000-8000 सौंफ 9000-13000, सोंठ 31000, (प्रतिकि.) लौंग 800-1000, बादाम 780-1080, काजू 2 पीस 840, किसमिस पीली 300-400, मखाना 800-1100

चावल (प्रति कु) : डबल चाबी सेला 9700, स्पाइस 6500, शरबती कच्ची 5250, शर्बती स्टीम 5350, मंसूरी 4000, महबूब सेला 4050, गौरी रॉयल 8400, राजभोग 6850, हरी पत्ती (1 किग्रा, 5 किग्रा) 10100, हरी पति नेचुरल 9100, गौरी स्पेशल 8500, गौरी प्रीमियम 10200, सूमो 4000, गौरी रॉयल 8600, मंसूरी पनघट 4200,लाडली 4200

दाल दलहन : मूंग दाल इंदौर 9800, मूंग धोवा 10000, राजमा चित्रा 11200-12000, राजमा भूटान नया 10100, मलका काली 7250-7450 मलका दाल 7350-9200, मलका छाँटी 7250, दाल उड़द बिलासपुर 8800-9800, मसूर दाल छोटी 10000-11600, दाल उड़द दिल्ली 11200, उड़द साबुत दिल्ली 10500, उड़द धोवा इंदौर 12700, उड़द धोवा 9800-11500,चना काला 7150, दाल चना 7250, दाल चना मोटी 7100, मलका विदेशी 7200, रूपकिशोर बेसन 7500, चना अकोला 6600, डबरा 6800-8400, सच्चा हीरा 8700, मोटा हीरा 10000, अरहर गोला मोटा 8800, अरहर पटका मोटा 9500, अरहर कोरा मोटा 9800, अरहर पटका छोटा 11100-11800, अरहर कोरी छोटी 13100

चीनी : पीलीभीत 4460, बहेड़ी 4300

भारत-अमेरिका समझौते में संवेदनशील क्षेत्र पूरी तरह संरक्षित : वाणिज्य सचिव

दोनों पक्ष संयुक्त बयान को कानूनी समझौते में बदलने पर कर रहे काम

- दोनों देश मार्च के अंत तक समझौते के प्रारूप को देंगे अंतिम रूप, हस्ताक्षर होने की उम्मीद

न्यूर्नबर्ग (जर्मनी), एजेंसी

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि भारत ने व्यापार समझौतों में हमेशा उन क्षेत्रों को लेकर स्पष्ट सोच रखी है जो देश के लिए बेहद संवेदनशील हैं और अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौते में ऐसे सभी प्रमुख क्षेत्रों की पूरी तरह रक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष संयुक्त बयान को कानूनी समझौते में बदलने पर काम कर रहे हैं जिसे मार्च के अंत तक अंतिम रूप देकर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है।

अग्रवाल ने कहा कि भारत ने हमेशा सभी समझौतों पर स्पष्ट सोच के साथ बातचीत की है। जो भी क्षेत्र भारत के लिए बेहद संवेदनशील हैं, जहां हमें लगता है कि हमारे किसान, मछुआरे, दुग्ध क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं, वहां हमने अपने साझेदार देशों को साफ बता दिया है कि भारत ऐसे मामलों में बाजार नहीं खोल सकता या पहुंच नहीं दे सकता।

उन्होंने कहा कि अगर आप पिछले एक साल में किए गए सभी समझौतों को देखें। हमने पांच व्यापार समझौते किए हैं। सभी में संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा की गई है। अमेरिका के साथ भी सभी प्रमुख संवेदनशील क्षेत्रों को सुरक्षित रखा गया है। जहां थोड़ी संवेदनशीलता थी, वहां हमने शुल्क दर कोटा व्यवस्था का इस्तेमाल किया ताकि बाजार तक पहुंच सीमित रहे और हमारे किसानों पर असर न पड़े। इस महीने की शुरुआत में घोषित अंतरिम व्यापार समझौते के तहत भारत ने मक्का, गेहूं, चावल, सोया, पोल्ट्री, दूध, पनीर, एथेनॉल (ईंधन), तंबाकू, कुछ सब्जियों और मांस जैसे संवेदनशील कृषि एवं दुग्ध उत्पादों को पूरी तरह संरक्षित रखा है। इन वस्तुओं पर अमेरिका को कोई शुल्क रियायत नहीं दी गई है। ये उत्पाद संवेदनशील हैं क्योंकि इनका संबंध देश के छोटे एवं सीमांत किसानों की आजीविका से है। अन्य मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) में भी भारत ने संवेदनशील कृषि और दुग्ध उत्पादों पर आयात शुल्क में कोई रियायत नहीं दी है।

देश का निर्यात सकारात्मक रहने की उम्मीद

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद चालू वित्त वर्ष में अब तक भारत के वस्तु एवं सेवा निर्यात में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है और जनवरी में भी इसके सकारात्मक रहने का अनुमान है। जनवरी के आंकड़े इस महीने आधिकारिक रूप से जारी किए जाएंगे। अग्रवाल ने कहा, कुल मिलाकर निर्यात अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। वस्तु निर्यात में हम मजबूती से टिके हुए हैं। सेवाएं हमेशा की तरह बहुत अच्छा कर रही हैं। आप (जनवरी के आंकड़ों) के सकारात्मक रहने की उम्मीद कर सकते हैं। जनवरी के निर्यात आंकड़ों को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने यह बात कही। अग्रवाल यहां बायोफैच 2026 प्रदर्शनी में हिस्सा लेने पहुंचे हैं जहां 100 से अधिक भारतीय प्रदर्शक और करीब 20 राज्य अपने जैविक उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं।

कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़

भारत ने हाल ही में यूरोपीय संघ, ब्रिटेन तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए को अंतिम रूप दिया है। कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियां जैसे पशुपालन भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इनसे 50 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में जहां कृषि अत्यधिक मशीनीकृत और कॉरपोरेट आधारित है, वहीं भारत में यह आजीविका का सवाल है। भारतीय कृषि क्षेत्र को वर्तमान में घरेलू किसानों को अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए मध्यम से उच्च शुल्क एवं नियामकीय उपायों के जरिये संरक्षण दिया गया है। भारत को 2024 में अमेरिका का कृषि निर्यात 1.6 अरब अमेरिकी डॉलर रहा।

समझौते पर संशोधित दस्तावेज से व्हाइट हाउस ने कुछ दालों का जिक्र हटाया

न्यूयॉर्क/वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति के आवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस ने अंतरिम व्यापार समझौते पर जारी संशोधित दस्तावेज में उन अमेरिकी उत्पादों की सूची से दालों का जिक्र हटा दिया है जिन पर भारत के शुल्क समाप्त करने या कम किए जाने की बात कही गई थी। व्हाइट हाउस ने अमेरिका और भारत ने की ऐतिहासिक व्यापार समझौते (अंतरिम समझौता) की घोषणा शीर्षक से एक दस्तावेज (फैक्ट शीट) सोमवार को जारी किया था। भारत और अमेरिका के पारस्परिक एवं लाभकारी व्यापार से संबंधित अंतरिम समझौते के ढांचे की संयुक्त घोषणा के कुछ दिन बाद व्हाइट हाउस ने इसे जारी किया। इसमें समझौते की प्रमुख शर्तों को उल्लेख किया गया है जैसे कि भारत सभी अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं एवं अमेरिकी खाद्य व कृषि उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर शुल्क समाप्त करेगा या घटाएगा। इनमें ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स, रेड सोरघम, ट्री नट्स, ताजे और प्रसंस्कृत फल, कुछ दालें, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट सहित अन्य उत्पाद शामिल हैं। साथ ही यह कहा गया था कि भारत ने अधिक अमेरिकी उत्पाद खरीदने तथा ऊर्जा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, कृषि, कोयला और अन्य क्षेत्रों में 500 अरब डॉलर से अधिक के अमेरिकी उत्पाद खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है। व्हाइट हाउस ने हालांकि मंगलवार को जारी संशोधित दस्तावेज (फैक्ट शीट) में दालों का जिक्र हटा दिया और भारत के लिए प्रयुक्त शब्द प्रतिबद्ध को बदलकर इरादा रखता है (इंटेंड्स) कर दिया गया है। संशोधित दस्तावेज में कहा गया है, भारत सभी अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं व अमेरिकी खाद्य एवं कृषि उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर शुल्क समाप्त या कम करेगा जिनमें ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स (डीडीजी), रेड सोरघम, ट्री नट्स, ताजे व प्रसंस्कृत फल, सोयाबीन तेल, वाइन तथा स्पिरिट और अन्य उत्पाद शामिल हैं। भारत अधिक अमेरिकी उत्पाद खरीदने और 500 अरब डॉलर से अधिक की अमेरिकी ऊर्जा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, कोयला और अन्य उत्पादों की खरीद का इरादा रखता है।

एसएमई की पूंजी बाजार में पहुंच सीमित

- सेबी प्रमुख पांडेय ने कहा- सूचीबद्धता से कंपनियों का संचालन हो सकता बेहतर

मुंबई, एजेंसी

सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय ने बुधवार को कहा कि पिछले कुछ समय में हुए विकास के बावजूद, पूंजी बाजार के नजरिये से लघु एवं मझोले उद्यम (एसएमई) क्षेत्र की पहुंच अभी भी सीमित बनी हुई है। पांडेय ने इंडिया एसएमई वित्तपोषण और निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि सूचीबद्धता से ऐसी छोटी कंपनियों में संचालन व्यवस्था बेहतर हो सकती है।

उन्होंने कहा कि नियामक संस्था को अतीत में इस मोर्चे पर कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। भारत की क्षमता के मुकाबले एसएमई पूंजी बाजार अभी भी सीमित बना हुआ है। कंपनियां पूंजी बाजारों से अपरिचित होने और मर्चेंट बैंकरों तक सीमित पहुंच के कारण बाजार में आने से हिचकिचाती हैं। कुछ वर्षों में सूचीबद्धता में हुई प्रगति का जिक्र करते हुए पांडेय ने कहा कि आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के माध्यम से पूंजी जुटाने की लागत भी एक बाधा हो सकती है। ऐसी कंपनियां खुलासा और अनुपालन को बोझिल मानती हैं और दस्तावेज दाखिल करने संबंधी व्यावहारिक मार्गदर्शन अक्सर अस्पष्ट होता है।

सेबी प्रमुख ने बाजार से पूंजी जुटाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि ऐसा कदम संचालन व्यवस्था को बेहतर बनाता है, जिससे पूंजी की लागत कम हो सकती है क्योंकि बाजार विश्वसनीयता को पुरस्कृत करते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले, बाजार से पूंजी प्राप्त करने में एक और बाधा तब उत्पन्न हुई जब कुछ एसएमई ने एसएमई ढांचे के तहत उपलब्ध रियायतों का दुरुपयोग किया। ऐसे मामलों ने एसएमई आईपीओ में निवेशकों के भरोसे को बुरी तरह प्रभावित किया।

1,400 कंपनियां अलग एसएमई एक्सचेंज पर सूचीबद्ध

पांडेय ने कहा कि ऐसे भी मामले सामने आए जहां कुछ एसएमई ने सकारात्मक माहौल बनाने और निवेशकों को अपने शेयर खरीदने के लिए प्रेरित करने को अनुचित व्यापार गतिविधियों का सहारा लिया। सेबी और शेयर बाजार दोनों ने इस पर सुधार किया है। 1,400 कंपनियां अलग से बनाये गये एसएमई स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हैं और उनका कुल बाजार पूंजीकरण 4.1 लाख करोड़ रुपये है। इनमें से 350 से अधिक कंपनियां मुख्य शेयर बाजार में स्थानांतरित हो चुकी हैं। पिछले वित्त वर्ष में कंपनियों ने 98 आईपीओ के माध्यम से 9,800 करोड़ रुपये जुटाए। 2025-26 में जनवरी तक 232 सूचीबद्धता के साथ बढ़कर 10,500 करोड़ रुपये हो गया है।

ईसी बिना खदान संचालन पर एनएलसी को कैग ने फटकारा

नई दिल्ली। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने वैध पर्यावरणीय मंजूरी के बिना अपनी एक खदान का संचालन करने के लिए एनएलसी इंडिया को फटकार लगाई है। कैग ने कहा कि पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) के पुनः सत्यापन को कंपनी के समय पर आवेदन नहीं करने से एनएलसी इंडिया ने माइन-II का संचालन वैध ईसी के बिना किया।

ऑडिट में सामने आया कि अगस्त, 2017 में उच्चतम न्यायालय के आदेश और अप्रैल, 2018 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना के बाद ईसी पुनः सत्यापन के लिए आवेदन में देरी से खदान में अनधिकृत संचालन हुआ। एनएलसी इंडिया के परिचालन प्रदर्शन पर 2017-18 से 2022-23 की अवधि को शामिल करने वाली ऑडिट रिपोर्ट राज्यसभा और लोकसभा में रखी गई।

देश का प्रत्यक्ष कर संग्रह 9.4% बढ़कर 19.44 लाख करोड़

नई दिल्ली, एजेंसी

- आयकर विभाग के मुताबिक, शुद्ध कॉरपोरेट कर संग्रह 14.51% बढ़कर 8.90 लाख करोड़ पहुंचा

चालू वित्त वर्ष में 10 फरवरी तक प्रत्यक्ष कर संग्रह 9.4% बढ़कर 19.44 लाख करोड़ रुपये हो गया। यह बढ़ोतरी कॉरपोरेट कर की बेहतर वसूली और कर रिफंड की धीमी गति का परिणाम है।

आयकर विभाग से बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, शुद्ध कॉरपोरेट कर संग्रह 14.51% बढ़कर 8.90 लाख करोड़ पहुंच गया। वहीं गैर-कॉरपोरेट कर संग्रह, जिसमें व्यक्तिगत आयकर और हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) से मिले कर शामिल हैं, 5.91% बढ़कर 10.03 लाख करोड़ रुपये रहा। शेयरों एवं अन्य प्रतिभूतियों के लेनदेन पर लगाया जाने वाला प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) का संग्रह 1 अप्रैल, 2025 से 10 फरवरी, 2026 के दौरान 50,279 करोड़ रहा। कर रिफंड जारी करने में 18.82% की गिरावट आई और यह घटकर 3.34 लाख करोड़ रहा। रिफंड में कमी से कर संग्रह वृद्धि दर को सहारा मिला।

देश का सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 4.09% बढ़कर 22.78 लाख करोड़ रुपये हो गया। इसमें 10.88 लाख करोड़ का सकल कॉरपोरेट कर और 11.39 लाख करोड़ रुपये का सकल गैर-कॉरपोरेट कर शामिल हैं। सरकार ने संशोधित अनुमान (आरई) में कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह 24.84 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान जताया है।

सरकार ने केंद्रीय करों की हिस्सेदारी में से किसी राज्य का हिस्सा नहीं घटाया : सीतारमण

नई दिल्ली, एजेंसी

- केंद्रीय वित्त मंत्री ने लोकसभा में बजट पर हुई चर्चा का दिया जवाब

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों को केंद्र से उनकी कर हिस्सेदारी का हस्तांतरण नहीं होने संबंधी कुछ विपक्षी सांसदों के आरोपों को खारिज करते हुए बुधवार को कहा कि सरकार ने केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में से किसी राज्य का हिस्सा नहीं घटाया है। सीतारमण ने लोकसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने बजट में पांच मेडिकल क्लस्टर, पांच मेगा औद्योगिक पार्क, बुजुर्गों के देखभाल के लिए पेशेवरों को तैयार करने जैसी कई घोषणाएं की हैं जिनसे लाखों रोजगारों का सृजन होगा।

उन्होंने कहा, हम पर आरोप है कि हम राज्यों की 41% कर हिस्सेदारी का हस्तांतरण नहीं करते। मैं आश्वासन देती हूं कि हमने केंद्रीय करों में राज्यों को मिलने वाली हिस्सेदारी में से किसी राज्य का हिस्सा नहीं घटाया है। 16वें वित्त आयोग ने 2018-19 से 2022-23 तक राज्यों की कर हिस्सेदारी का विश्लेषण किया और निष्कर्ष निकाला कि केंद्र से राज्यों को मिलने वाला धन आयोग की सिफारिश से मेल खाता है और इसमें कोई कमी नहीं है। अगले वित्त वर्ष में राज्यों को कुल कर हस्तांतरण 25.44 लाख करोड़ होने का अनुमान है जो चालू वित्त वर्ष की तुलना में 2.07 लाख करोड़ रुपये अधिक होगा।

सीतारमण ने कहा कि संविधान ने केंद्र को उपकर और अधिशेष लगाने का अधिकार दिया है और विभाज्य पूल में वह शामिल नहीं होता है, इसलिए राज्यों की कुल कर हिस्सेदारी की बात करते समय उपकर और अधिशेष संबंधी आरोप अनुचित हैं। केंद्र जो उपकर वसूलता है उसमें से भी राज्यों को अस्पताल, स्कूल और सड़क आदि के लिए सहायता देता है। सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए 53.47 लाख करोड़ के व्यय का अनुमान लगाया है, जो 31 मार्च को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष की तुलना में 7.7% अधिक है। संशोधित अनुमान के अनुसार, चालू वित्त वर्ष का बजट 49.64 लाख करोड़ है, जो फरवरी, 2025 में अनुमानित 50.65 लाख करोड़ से कम है। 2024-25 का बजट 46.52 लाख करोड़ का था।

वित्त मंत्री ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में कुल व्यय 53.47 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, जो कर राजस्व से कहीं अधिक है। सरकार का लक्ष्य 44.04 लाख करोड़ का राजस्व प्राप्त करना है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8% अधिक है। सरकार ने 12.2 लाख करोड़ का सबसे अधिक आवंटन किया है, जो जीडीपी का 4.4% है।

गलत बिक्री रोकने के लिए बैंकों में प्रोत्साहन समाप्त करने का प्रस्ताव

मुंबई। बैंकों को किसी भी ऐसे प्रोत्साहन से बचना चाहिए, जिससे किसी उत्पाद या सेवा की गलत बिक्री हो सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को यह प्रस्ताव किया।

केंद्रीय बैंक ने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के विज्ञापन, विपणन और बिक्री के लिए अपने मसौदा संशोधन निर्देशों में यह भी प्रस्ताव दिया कि बैंक ग्राहकों से उनकी सहमति प्राप्त करने के बाद ही संपर्क करें और ऐसा केवल कार्यालय समय के दौरान ही किया जाए। आरबीआई ने कहा, बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी नीतियां और कार्यप्रणाली न तो गलत बिक्री के लिए प्रोत्साहन ढांचा तैयार करें और न ही कर्मचारियों/डीएसए को उत्पादों/सेवाओं की बिक्री को बढ़ाने को प्रोत्साहित करें। केंद्रीय बैंक के अनुसार, यह सुनिश्चित होगा कि तृतीय-पक्ष उत्पादों/सेवाओं के विपणन/बिक्री में लगे कर्मचारियों को तृतीय-पक्ष से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई प्रोत्साहन प्राप्त न हो।

दुबई हवाई अड्डे से 9.52 करोड़ यात्रियों ने किया सफर

दुबई। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2025 में भी सबसे व्यस्त हवाई अड्डा रहा। अधिकारियों ने बताया कि 2025 में रिकॉर्ड 9.52 करोड़ यात्रियों ने टर्मिनल से सफर किया, जो अमीरात की आर्थिक तेजी को दर्शाता है। वैश्विक महामारी के बाद हवाई अड्डे की गतिविधियों में तेज उछाल आया है। इसे वैश्विक यात्रा रुचि के साथ-साथ संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के सबसे बड़े शहर दुबई में बढ़ते पर्यटन, व्यापार एवं रियल एस्टेट अवसरों से बल मिला है।

एनपीएस : निवेशक निकाल सकते हैं 100% फंड

नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) देश में रिटायरमेंट प्लानिंग का लोकप्रिय माध्यम है। सुरक्षित भविष्य और नियमित पेंशन की सुविधा के कारण बड़ी संख्या में लोग इस योजना से जुड़ रहे हैं। हाल के वर्षों में पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) ने एनपीएस से निकासी के नियमों में कुछ अहम बदलाव किए हैं, जिससे सब्सक्राइबर्स को अधिक लचीलापन मिला है। खास परिस्थितियों में अब निवेशक अपना 100 प्रतिशत फंड भी निकाल सकते हैं। पहले जहां निकासी की सीमा कम थी, वहीं अब इसे बढ़ाकर निवेशकों को राहत दी गई है।

60 की उम्र में पूरे फंड की निकासी का नियम

यदि किसी एनपीएस सब्सक्राइबर की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है और उसके खाते में कुल फंड 8 लाख रुपये तक है, तो वह पूरा पैसा एकमुश्त निकाल सकता है। पहले यह सीमा 5 लाख रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया गया है। यह बदलाव छोटे निवेशकों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि अब उन्हें कम फंड होने की स्थिति में अनिवार्य रूप से एन्युटी (वित्तीय अनुबंध) खरीदने की जरूरत नहीं होगी।

100% निकासी की शर्तें

- **पहली शर्त :** एनपीएस खाता 5 साल पुराना होना चाहिए।
- **दूसरी शर्त :** खाते में कुल फंड 5 लाख तक होना चाहिए।

मृत्यु की स्थिति में नियम

यदि किसी एनपीएस सब्सक्राइबर का निधन हो जाता है, तो उसके खाते में जमा पूरी राशि नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को दे दी जाती है। इस स्थिति में फंड की कोई सीमा लागू नहीं होती। यानी चाहे खाते में कितनी भी राशि हो, पूरा पैसा उत्तराधिकारी को मिलता है।

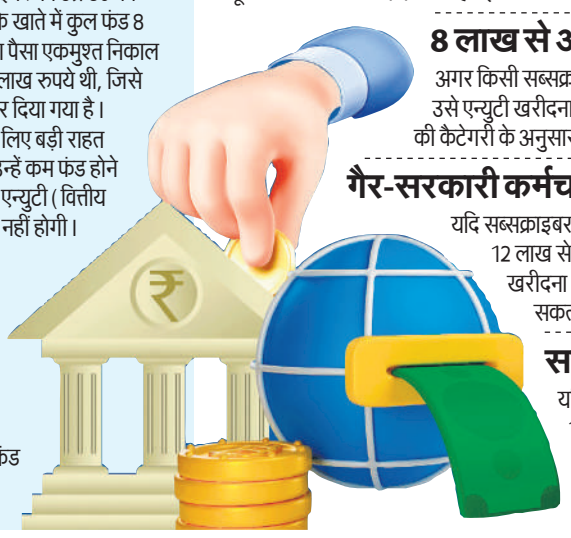

8 लाख से अधिक फंड होने पर नियम

अगर किसी सब्सक्राइबर का एनपीएस फंड 8 लाख रुपये से अधिक है, तो उसे एन्युटी खरीदना अनिवार्य होता है। हालांकि, यह नियम सब्सक्राइबर की कैटेगरी के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।

गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए

यदि सब्सक्राइबर सरकारी कर्मचारी नहीं है और उसका एनपीएस फंड 12 लाख से अधिक है, तो कम से कम 20% राशि से एन्युटी खरीदना अनिवार्य है। शेष 80% राशि एकमुश्त निकाली जा सकती है, जिसमें से 60% हिस्सा टैक्स-फ्री होता है।

सरकारी कर्मचारी

यदि सब्सक्राइबर सरकारी कर्मचारी है और उसका फंड 12 लाख रुपये से अधिक है, तो उसे 60% राशि के लिए एन्युटी खरीदनी होती है। ऐसे में वह 60% राशि एकमुश्त निकाल सकता है, जबकि शेष हिस्सा पेंशन के रूप में मिलता है।

उपभोक्ता आयोग | उच्चतम न्यायालय ने अपने विशेष शक्तियों का प्रयोग कर दिया महत्वपूर्ण आदेश

एससीडीआरसी में लंबित उपभोक्ता मामलों की सुनवाई करें हाईकोर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को महत्वपूर्ण आदेश में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कुछ उच्च न्यायालयों से कहा कि वे राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों (एससीडीआरसी) में लंबित उपभोक्ता शिकायतों और अपीलों की सुनवाई करें। अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार देता है कि वह अपने समक्ष लंबित मामलों में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आदेश पारित कर सके।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता विवादों के त्वरित निपटारे के लिए तीन-स्तरीय व्यवस्था है, जिसमें जिला आयोग, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एससीडीआरसी) और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) शामिल है। राज्य आयोग एक करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक के दावों वाले मामलों की सुनवाई करता है और जिला आयोगों के आदेशों के खिलाफ अपीलें भी सुनता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने उन राज्यों की याचिकाओं पर सुनवाई की, जहां उपभोक्ता आयोगों में लंबित मामलों की संख्या बेहद कम है। कुछ राज्यों ने बताया कि उनके उपभोक्ता आयोग एक साल से अधिक समय से निष्क्रिय पड़े हैं। उच्चतम न्यायालय ने संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को निर्देश दिया कि वे उपभोक्ता मामलों के निपटारे के लिए अनुभवी एकल न्यायाधीश नियुक्त करें।

संपत्ति खरीदारों की टीडीएस देनदारी पर दायर याचिका खारिज

- 50 लाख से अधिक की संपत्ति की खरीद से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इन्कार

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 50 लाख रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति की खरीद पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की देनदारी के बारे में जागरूक करने वाली व्यवस्था न होने का मुद्दा उठाया गया था। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई से इन्कार करते हुए अपने संक्षिप्त आदेश में इसे खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने कहा कि याचिका आयकर अधिनियम के उस प्रावधान के लागू होने से जुड़ी है, जिसके तहत 50 लाख रुपये से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति की खरीद पर खरीदार को एक प्रतिशत टीडीएस काटकर सरकार के पास जमा करना होता है। उन्होंने दलील दी कि मौजूदा व्यवस्था में टीडीएस जमा करने की पूरी जवाबदेही केवल खरीदार पर डाल दी गई है और इसके लिए यह आधार बनाया गया है कि हर संपत्ति खरीदार को आयकर कानून की पर्याप्त जानकारी है। याचिकाकर्ता ने कहा कि संपत्ति के पंजीकरण के समय टीडीएस अनुपालन की जांच के लिए कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं होने से पहली बार घर खरीदने वाले या सामान्य खरीदार अनजाने में चूक कर बैठते हैं और बाद में उन्हें जुर्माने एवं ब्याज का सामना करना पड़ता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह कर देनदारी या आयकर अधिनियम के प्रावधानों की वैधता को चुनौती नहीं दे रहे हैं, बल्कि केवल संस्थागत सुरक्षा उपायों के लिए सीमित निर्देश चाहते हैं। याचिकाकर्ता के मुताबिक, अगर ऐसे उपाय कर दिए जाते हैं तो नागरिकों की सुरक्षा होगी, स्वैच्छिक अनुपालन बढ़ेगा और सरकार के राजस्व की भी रक्षा होगी।

एफडीटीएल मानकों के पालन के लिए सभी इंतजाम किए गए पूरे : इंडिगो

- डीजीसीए ने कंपनी की प्रगति रिपोर्ट एवं आश्वासन की दी जानकारी

नई दिल्ली, एजेंसी

इंडिगो ने विमानन नियामक डीजीसीए को बताया है कि संशोधित पायलट ड्यूटी मानकों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक परिचालन, रोस्टरिंग और निगरानी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। विमान कंपनी इंडिगो को दिसंबर में बड़े पैमाने पर परिचालन संबंधी व्यवधान के बाद नियामकीय कार्रवाई का सामना करना पड़ा था।

विमानन कंपनी को नए उड़ान ड्यूटी समय सीमा (एफडीटीएल) मानकों पर मिली अस्थायी छूट मंगलवार को समाप्त होने के बाद, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने बुधवार को बयान जारी कर कंपनी की ओर से दी गई प्रगति रिपोर्ट एवं आश्वासन की जानकारी दी। इंडिगो में परिचालन का अनुकूलन, अपर्याप्त नियामक तैयारी, सिस्टम सॉफ्टवेयर समर्थन में कमियां एवं प्रबंधन संरचना और परिचालन नियंत्रण में खामियां उन प्रमुख कारणों में से थीं जिनसे व्यवधान उत्पन्न हुए। डीजीसीए ने तय उड़ानों में 10% की कटौती की थी। इंडिगो के 2,507 उड़ानें रद्द किए जाने पर डीजीसीए ने एफडीटीएल मानकों के क्रियान्वयन में ढील देने के लिए विमानन कंपनी को 10 फरवरी तक का समय दिया था।

चालक दल के विश्राम मानक वैश्विक मानकों से भी कड़े

इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइसजेट एयरलाइन ने चालक दल के लिए प्रस्तावित विश्राम मानकों को वैश्विक मानकों की तुलना में अधिक निषेधात्मक बताते हुए कहा कि इससे एयरलाइंस को परिचालन में सीमित लचीलापन मिल पाता है। डीजीसीए ने अक्टूबर, 2025 में चालक दल की उड़ान ड्यूटी समयसीमा (एफडीटीएल) से संबंधित नागर विमानन शर्तों (सीएआर) का मसौदा जारी किया था। इन तीनों एयरलाइन का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय एयरलाइंस महासंघ (एफआईए) ने 12 जनवरी को डीजीसीए को भेजे पत्र में वैश्विक रूप से सामंजस्यपूर्ण, साक्ष्य-आधारित और परिचालन रूप से व्यावहारिक प्रावधान लागू करने की सिफारिश की है। एफआईए का तर्क है कि चालक दल सदस्यों के थकान प्रबंधन के लिए उड़ान अवधि के बजाय ड्यूटी की कुल अवधि को प्राथमिक नियंत्रण मानक बनाया जाए।

वर्ल्ड ब्रीफ

फिलीपींस में जहाज डूबने से मरने वालों की संख्या 52 हुई

फिलीपींस। फिलीपींस के बेसिलन प्रांत के पास यात्री-मालवाहक जहाज 'त्रिशा कर्स्टन 3' के डूबने से 52 लोगों की मौत हो गई है। फिलीपीन कोस्ट गार्ड (पीसीजी) ने तकनीकी गोताखोर टीमों के चल रहे प्रयासों का हवाला देते हुए बताया कि गोताखोरों ने मंगलवार तड़के बालुक-बालुक द्वीप के पास खोज और बचाव अभियान के दौरान एक और शव बरामद किया। कुल मिलाकर 316 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि बचाव दल अभी भी शेष पीड़ितों की तलाश में जुटे हैं। यह जहाज 26 जनवरी की रात बेसिलन से लगभग एक समुद्री मील की दूरी पर डूब गया था, जिसमें 332 यात्री और चालक दल के 27 सदस्य सवार थे। अधिकारियों ने कहा कि डूबने का संभावित कारण तकनीकी खामी थी।

धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने में सिंगापुर में भारतीय को सजा

सिंगापुर। सिंगापुर की एक अदालत ने बुधवार को भारतीय मूल के एक व्यक्ति को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और एक सार्वजनिक अधिकारी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करने के आरोप में 14 सप्ताह की जेल की सजा सुनाई। चैनल न्यूज एशिया (सीएनए) की रिपोर्ट के अनुसार 36 वर्षीय विकनेस्वरन वी मोगनावल ने धार्मिक सद्भाव बनाए रखने के अधिनियम के तहत एक आरोप और एक लोक सेवक के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करने के दूसरे आरोप में दोषी होने की बात स्वीकार कर ली है। वह इसलिए नाराज था क्योंकि उसके पड़ोसी के बच्चे अक्सर उसके अपार्टमेंट के पास वाले साझा गलियारे में खेलते थे। उसकी पड़ोसी अपने पति, तीन बच्चों, सास, बहन और एक नौकरानी के साथ वहीं रहती थी।

तनाव कम करने के लिए यूनान और तुर्किए के नेता करेंगे वार्ता

अंकारा। यूनान के प्रधानमंत्री क्यारियाकोस मित्सोताकिस बुधवार को तुर्किए की यात्रा के लिए रवाना हुए, जहां दोनों देशों के बीच वार्ता होने की उम्मीद है। यह यात्रा ऐसे समय में संवाद बनाए रखने के प्रयासों का हिस्सा है जब दोनों प्रतिद्वंद्वी देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। वरिष्ठ मंत्रियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ आने वाले मित्सोताकिस तुर्किए के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन से मुलाकात करेंगे। यह वार्ता उच्च स्तरीय सहयोग परिषद के तहत एक पहल है जिसे नाटो के दोनों सहयोगियों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया था। यूनान और तुर्किये के बीच समुद्री सीमाओं, साइप्रस और पूर्वी भूमध्य सागर में 'ड्रिलिंग' अधिकारों सहित कई मुद्दों पर मतभेद बना हुआ है।

श्रीलंकाई सांसद की हत्या के मामले में 12 को मौत की सजा

कोलंबो, एजेंसी

● बेगमपुर इलाके में हुआ हादसा पुलिस ने दर्ज किया मामला

श्रीलंका की गम्पाहा हाईकोर्ट ने बुधवार को वर्ष 2022 में तत्कालीन सांसद अमरकीर्ति अथुकोराला और उनके सुरक्षा अधिकारी की हत्या के मामले में 12 व्यक्तियों को दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई। यह फैसला एक लंबी सुनवाई के बाद आया है, जिसमें इन हत्याओं के संबंध में कुल 42 लोगों को आरोपित किया गया था।

मौत की सजा के अलावा, अदालत ने चार अन्य व्यक्तियों को छह महीने की जेल की सजा सुनाई है। अन्य 23 आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया। रिपोर्टों के अनुसार, मई 2022 में देशव्यापी अशांति के दौरान सांसद और उनके सुरक्षा अधिकारी ने प्रदर्शनकारियों की एक आक्रोशित भीड़ पर उस समय गोलियां चला दी थीं, जब वे उनके वाहन को रोक रहे थे। इस घटना में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उसी दिन बाद में सांसद और उनके सुरक्षाकर्मी पास की एक इमारत के अंदर मृत पाए गए थे।

साइबर ठगों को सिस्टम का साथ

डिजिटल 'डकैती'

डिजिटल अरेस्ट के जरिए 54,000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की ठगी को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने डकैती करार दिया है। यह निराशाजनक ही है कि साइबर ठगी यह तरीका कई वर्षों से इस्तेमाल किया जा रहा है लेकिन देश का गृह विभाग इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है। रिकॉर्ड के अनुसार देश में डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं का इतिहास करीब पांच साल पुराना हो चुका है। साल दर साल इन घटनाओं में बेहद तेज वृद्धि हुई है। इस बीच सबसे ज्यादा चिंताजनक यह है कि ठगी के कुछ मामलों में बैंक और टेलीकॉम अफसरों की साठगांठ भी सामने आई है। डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं में अपराधियों तक पहुंचने में पुलिस की कामयाबी की दर भी बेहद मामूली है। इसके साथ यह भी सवाल उठने लगे हैं कि देश में डिजिटल क्रांति पर जोर देने के साथ लोगों को ठगी से बचाने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए गए हैं।

डिजिटल अरेस्ट की शुरुआत

- लोगों को वीडियो कॉल कर डिजिटल अरेस्ट के जरिए ठगी के मामले 2021 में आने शुरू हुए और बाद में तेजी से इनकी संख्या बढ़ी।
- डिजिटल अरेस्ट में मनोवैज्ञानिक दबाव और वीडियो विजुअल्स की मदद ली गई जो जामतारा जैसे ठगी के केंद्रों से विकसित हुआ।
- भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2022 में 40,000 केस दर्ज किए गए थे जो 2024 तक बढ़कर 1.23 लाख से अधिक हो गए।
- नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के अनुसार 2024 में तीन गुना वृद्धि हुई, शुरू के 4 महीनों में ही 120.30 करोड़ की ठगी हुई।

अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क और तकनीक

- जांच में पाया गया कि ठग गिरोहों के तार दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों जैसे कंबोडिया, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड से जुड़े हैं।
- हाल के वर्षों में अपराधियों ने एआई का उपयोग करके पुलिस अधिकारियों की आवाज और चेहरे की नकल करनी शुरू की है।

बैंक अधिकारियों की साठगांठ

- दिल्ली में येस बैंक के दो अफसर गिरफ्तार किए गए, जिन्होंने फर्जी खाते खोले ताकि पैसे को लाउंडर किया जा सके।
- कमीशन लेकर फर्जी खाते खोलने पर हैदराबाद और बेंगलुरु में एयू स्मॉल फाइनेंस, बंधन बैंक शाखा प्रबंधक पकड़े गए।
- तेलंगाना में ऑपरेशन इनसाइडर के तहत कई बैंक अफसर पकड़े गए जो खाते खोलकर अपराधियों की मदद कर रहे थे।
- वोडाफोन के एरिया सेल्स मैनेजर ने साइबर ठगों को 21,000 सिम मुहैया कराए, जिसे दिल्ली में सीबीआई ने गिरफ्तार किया।

हैरतअंगेज मामले

- चेन्नई में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पूर्व केंद्रीय सचिव पद्म भूषण सम्मानित टी. रामासामी को डिजिटल अरेस्ट कर ठगों ने 57 लाख की ठगी की।
- अगस्त 2024 में ठगों ने पद्म भूषण से सम्मानित वर्धमान ग्रुप के एसपी ओसवाल को सीबीआई अफसर बनकर डिजिटल अरेस्ट किया और 7 करोड़ ठग लिए।
- चंडीगढ़ में रिटायर्ड कर्नल और उनकी पत्नी से 3.4 करोड़ रुपये की ठगी हुई।

डिजिटल क्रांति में सुरक्षा की कमी

- भारत का पहला व्यापक डिजिटल कानून डिजिटल क्रांति के कई वर्षों बाद आया। इसके नियम अभी भी पूरी तरह लागू होने की प्रक्रिया में हैं। इस देरी ने ठगों को बड़ा अवसर मुहैया कराया।
- टेलीकॉम और बैंकिंग कर्मचारी ही सुरक्षा प्रोटोकॉल को दरकिनार कर रहे हैं, जो सिस्टम की बड़ी कमजोरी है। रिजर्व बैंक ने भी स्वीकार किया है कि म्यूल खाते खोलने के पीछे साठगांठ है।
- ठग अत्याधुनिक एआई और डीपफेक उपयोग कर रहे हैं जबकि देश के कई राज्यों में साइबर पुलिस के पास पुराना बुनियादी ढांचा है और वह विशेषज्ञों की भारी कमी से जूझ रही है।

आपसी मतभेदों को रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखे भारत

दोनों देशों के बीच विदेश सचिव स्तर की वार्ता के बाद चीन ने दिया जोर

बीजिंग, एजेंसी

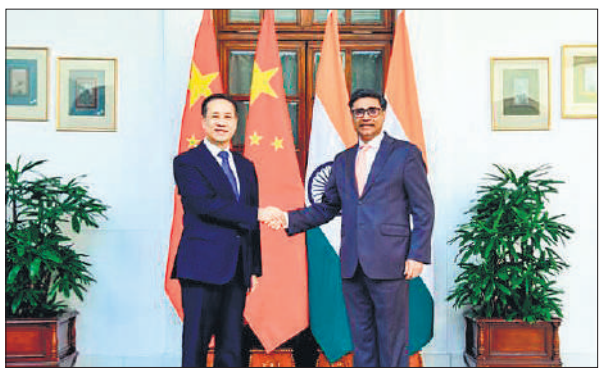

भारत ने संवेदनशील मुद्दों पर चिंता जताई

इस वार्ता पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति की समीक्षा की और लोगों के बीच आदान-प्रदान को बढ़ाकर तथा संवेदनशील मुद्दों पर चिंताओं को दूर करके संबंधों को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। जायसवाल ने संवेदनशील मुद्दों के बारे में विस्तार से नहीं बताया, लेकिन समझा जाता है कि भारतीय पक्ष दुर्लभ पृथ्वी खनिजों से संबंधित चीन के निर्यात नियंत्रण उपायों को लेकर चिंतित है। मिसरी और झाओक्सू की वार्ता पर भारतीय पक्ष की ओर से जारी बयान में कहा गया कि चर्चा मुख्य रूप से द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने और पुनर्निर्माण में हालिया प्रगति तथा आगे संपर्क बढ़ाने के उपायों पर केंद्रित रही। दोनों पक्षों ने इस बात पर जोर दिया कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता द्विपक्षीय संबंधों की समग्र प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है।

चीन के विदेश मंत्रालय ने नR दिल्ली में भारत के साथ मंगलवार को हुई रणनीतिक वार्ता पर मंगलवार को कहा कि दोनों देशों को अपने संबंधों को रणनीतिक एवं दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, साथ ही मतभेदों को उचित तरीके से सुलझाना चाहिए और सहयोग बढ़ाना चाहिए। विदेश सचिव विक्रम मिसरी और उनके चीनी समकक्ष मा झाओक्सू ने भारत-चीन रणनीतिक वार्ता की, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई।मा झाओक्सू भारत में 'ब्रिक्स' शेरपा बैठक में भाग लेने आए हैं।

चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से मिसरी और झाओक्सू के बीच बातचीत पर कहा गया कि दोनों पक्षों ने अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्थिति, दोनों देशों की आंतरिक एवं बाहरी नीतियों, साझा हितों से जुड़े क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों तथा चीन-भारत संबंधों पर मित्रतापूर्ण, स्पष्ट और गहन संवाद किया। दोनों पक्षों ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्थिति में जटिल और गहरे बदलावों को देखते हुए भारत और चीन को मिलकर काम करना चाहिए तथा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बनी महत्वपूर्ण समझ को गंभीरता से लागू करना चाहिए। बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं के बीच बनी समझ के अनुसार, दोनों देशों को यह रणनीतिक धारणा बनाए रखनी चाहिए कि भारत और चीन प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि सहयोगी साझेदार हैं और दोनों एक-दूसरे के लिए विकास का अवसर हैं, खतरा नहीं।

चीन ने कहा कि दोनों देशों को आपसी विश्वास को मजबूत करना चाहिए, सहयोग बढ़ाना चाहिए, मतभेदों को सही तरीके से सुलझाना चाहिए और संबंधों को स्थिर एवं सही दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। दोनों पक्षों ने 2026 और 2027 में ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान एक-दूसरे के कार्यों का समर्थन करने पर सहमति जताई। इसके अलावा दोनों पक्षों ने बहुपक्षवाद, संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका, 'ग्लोबल साउथ' में एकता एवं सहयोग को मजबूत करने, अंतरराष्ट्रीय न्याय एवं निष्पक्षता की रक्षा करने, बहुध्रुवीय विश्व के लिए मिलकर काम करने तथा एशिया और विश्व में शांति एवं विकास में योगदान देने पर सहमति जताई।

बीजिंग में भारत और अमेरिका के राजदूतों की मुलाकात

बीजिंग। चीन में भारत के राजदूत प्रदीप रावत और उनके अमेरिकी समकक्ष डेविड पर्ड्यू ने बीजिंग में मुलाकात की और अमेरिका-भारत संबंधों एवं साझा हितों पर चर्चा की। पर्ड्यू ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, रक्षा, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों पर घनिष्ठ सहयोग और क्वाड की भागीदारी के माध्यम से अमेरिका-भारत संबंध वास्तविक परिणाम देते हैं। उन्होंने कहा, अपने मित्र राजदूत रावत से मिलकर हमारी साझा रुचियों पर चर्चा करना हमेशा ही बहुत अच्छा अनुभव रहता है। दिसंबर के बाद से यह उनकी दूसरी बैठक है। रावत, पर्ड्यू और चीन में जापानी राजदूत केंजी कानासुगी ने पिछले साल दिसंबर में अमेरिकी दूतावास में मुलाकात की थी।

बांग्लादेश में आम चुनाव आज, 50% से ज्यादा मतदान केंद्र संवेदनशील

● सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, बॉडी कैमरे से लैस पुलिसकर्मी तैनात

ढाका, एजेंसी

बांग्लादेश में बृहस्पतिवार को होने जा रहे आम चुनाव के लिए आधे से अधिक मतदान केंद्रों को संवेदनशील के रूप में चिह्नित किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक इनमें से 90 प्रतिशत मतदान केंद्र सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहेंगे। राजधानी ढाका में बॉडी कैमरों से लैस पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि निर्वाचन आयोग की सुरक्षा प्रणाली जोखिम मूल्यांकन पर आधारित है। निर्वाचन आयुक्त अबुल फजल मोहम्मद सनाउल्लाह ने मंगलवार देर रात संवाददाता सम्मेलन में कहा, स्थानीय स्तर पर संवेदनशीलता के आकलन के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने कहा कि इन चुनाव में देश के चुनावी इतिहास में कानून प्रवर्तन कर्मियों की अब तक की सबसे बड़ी तैनाती और प्रौद्योगिकी का सबसे व्यापक उपयोग देखने को मिलेगा। सनाउल्लाह ने कहा कि निर्वाचन आयोग को उम्मीद है कि कानून प्रवर्तन एजेंसी मतदान के दौरान और चुनाव के बाद मतदाताओं के लिए शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करेंगी।

उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग कानून-व्यवस्था की मौजूदा स्थिति से काफी हद तक संतुष्ट है और पहले की तुलना में हम अब बेहतर स्थिति में हैं। उनकी यह टिप्पणी पुलिस महानिरीक्षक बहारुल आलम के उस बयान के कुछ देर बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि देश भर में लगभग 43,000 मतदान केंद्रों में से 24,000 मतदान केंद्र उच्च या मध्यम जोखिम वाले मतदान केंद्र पाए गए हैं।

आम चुनाव की पूर्व संध्या पर ढाका में मतपेटियां तैयार करता एक कर्मचारी।

मुख्य मुकाबला बीएनपी और जमात के बीच

बांग्लादेश में एक जटिल 84 सूत्री सुधार पैकेज पर जनमत संग्रह के साथ आम चुनाव हो रहे हैं। मुख्य मुकाबला बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) और उसके पूर्व सहयोगी जमात-ए-इस्लामी के बीच है। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग को पिछले साल भंग कर दिया था और पार्टी के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। बांग्लादेश में बृहस्पतिवार को संसदीय चुनाव होंगे।

भारत-पाकिस्तान के बीच मार गिराए गए थे 10 विमान : ट्रंप

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यह दावा दोहराया कि उन्होंने पिछले साल भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव को टैरिफ की धमकी देकर रोक दिया था जो परमाणु युद्ध में बदल सकता था। उन्होंने कहा, इस संघर्ष में उनके हस्तक्षेप करने तक 10 विमान मार गिराए गए थे।

ट्रंप ने मंगलवार को एक साक्षात्कार में कहा, मैंने आठ युद्ध रुकवाए। इनमें से छह टैरिफ के कारण सुलझे। जैसे भारत और पाकिस्तान। मैंने कहा कि अगर आप यह युद्ध नहीं रोकते हैं तो मैं आप पर टैरिफ लगा दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग मारे जाएं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, उन्होंने पूछा कि युद्ध का टैरिफ से क्या लेना-देना। ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था, ट्रंप ने हमें लड़ाई रोकने के लिए राजी करके कम से कम एक करोड़ लोगों की जान बचाई।

पेजेश्कियान ने प्रदर्शनों पर खूनी कार्रवाई के पीड़ितों से माफी मांगी

दुबई, एजेंसी

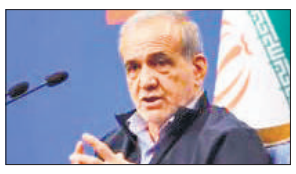

● देशव्यापी प्रदर्शनों पर पश्चिमी देशों के दुष्प्रचार की निंदा की

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने देशव्यापी प्रदर्शनों और उसके बाद हुई खूनी कार्रवाई से पीड़ित सभी लोगों से बुधवार को माफी मांगी। हालांकि, राष्ट्रपति ने प्रदर्शनों को लेकर फैलाए कथित पश्चिमी दुष्प्रचार की भी निंदा की।

पेजेश्कियान ने कहा कि वह प्रदर्शनों और उनके खिलाफ कार्रवाई के दौरान हुए लोगों के गहरे दुख को समझते हैं लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर यह स्वीकार नहीं किया कि इस रक्तपात में ईरानी सुरक्षा बलों की भूमिका थी। उन्होंने कहा, हम जनता के सामने शर्मिंदा हैं और इन घटनाओं में जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है, उनकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। हम जनता से टकराव नहीं चाहते। पेजेश्कियान ने यह भी जोर देकर कहा कि उनका देश परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा और वह किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हैं।

उनकी यह टिप्पणी ईरान की 1979 की इस्लामी क्रांति की वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में आई। ईरान इस समय अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका के साथ बातचीत के दौर में है। हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि कोई परमाणु समझौता हो पाएगा या नहीं। ट्रंप ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए एक और विमानवाहक पोत भेजने की धमकी दी है। इस बीच, संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कई महीनों से ईरान के परमाणु भंडार का निरीक्षण और सत्यापन करने में असमर्थ रही है।

ट्रंप के अलावा किसी ने नहीं कहा रूस से तेल खरीदना बंद करेगा भारत

● लावरोव ने कहा- रूस भारत के साथ संबंधों को लेकर हरसंभव प्रयास करने को तैयार

मास्को। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अलावा किसी ने भी यह नहीं कहा है कि भारत, रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बुधवार को देश की संसद में यह बात कही। रूस ने अमेरिका पर भारत और अन्य देशों को उससे तेल खरीदने से रोकने का प्रयास करने का आरोप लगाया था, जिसके दो दिन बाद लावरोव की यह टिप्पणी आई है।

रूस का कहना है कि वाशिंगटन टैरिफ, प्रतिबंध और सीधे रोक सहित कई तरह के दबावपूर्ण कदम उठा रहा है। लावरोव ने बुधवार को स्टेट ड्यूमा (निचले सदन) में एक सांसद के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, आपने उल्लेख किया कि ट्रंप ने भारत की रूस से तेल न खरीदने की सहमति की घोषणा की है। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या किसी अन्य भारतीय नेता से ऐसा कोई बयान नहीं सुना है। लावरोव ने उल्लेख किया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में शेरपाओं की पहली बैठक में कहा था कि ऊर्जा सुरक्षा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के प्रमुख मुद्दों में से एक होगी, जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शामिल होने की उम्मीद है। भारत 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा।

लावरोव ने कहा कि दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा ने मॉस्को और नई दिल्ली के बीच संबंधों को समृद्ध किया है।

गलत बाल काटने पर मुआवजा राशि दो करोड़ से घटाकर 25 लाख की

● सुप्रीम कोर्ट ने पलटा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का फैसला

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के आईटीसी मौर्या होटल के सैलून में गलत बाल काटने पर एक महिला को दी जाने वाली मुआवजा राशि को दो करोड़ रुपये से घटाकर 25 लाख रुपये कर दिया है। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा, बेशक सेवा में खामी सिद्ध हुई है, फिर भी उपभोक्ता विवादों में मुआवजा सिर्फ शिकायतकर्ता की मांग या हठ पर तय नहीं किया जा सकता।

न्यायमूर्ति बिंदल ने फैसले में कहा, दावा जब करोड़ों रुपये का हो तो मुआवजा देने के लिए कुछ ठोस सबूत पेश करना जरूरी है। मुआवजे का दावा करोड़ों रुपये का था, जिसके लिए यह साबित करना आवश्यक था कि सेवा में कमी के कारण प्रतिवादी को कुछ आर्थिक नुकसान हुआ। इसे केवल दस्तावेजों की फोटोकॉपी पेश करके साबित नहीं किया जा सकता।

यह था मामला

अप्रैल 2018 में प्रबंधन पेशेवर अशना रॉय दिल्ली के आईटीसी मौर्या होटल के सैलून गई थीं। रॉय ने आरोप लगाया कि हेयर स्टाइलिस्ट ने उनके कहने के विपरीत बाल छोटे काट दिए, जिससे उन्हें मानसिक आघात लगा और करियर के अवसरों से हाथ धोना पड़ा। एनसीडीआरसी ने शुरू में उन्हें दो करोड़ रुपये दिए जाने का फैसला सुनाया था।

आज का भविष्यफल

-पं. मनोज कुमार द्विवेदी

आज की ग्रह स्थिति : 12 फरवरी, गुरुवार 2026 संवत-2082, शक संवत 1947 मास-फाल्गुन, पक्ष-कृष्ण पक्ष, दशमी 12.22 तक तत्पश्चात एकादशी।

आज का पंचांग

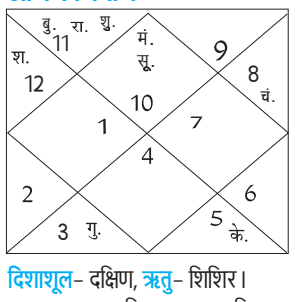

दिशाशूल- दक्षिण, **ऋतु**- शिशिर।
चन्द्रबल- वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर, कुंभ।
ताराबल- अश्विनी, भरणी, रोहिणी, आर्द्रा, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, हस्त, स्वाति, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, श्रवण, शतभिषा, उत्तराभाद्रपद, रेवती।
नक्षत्र-ज्येष्ठा 13.42 तक तत्पश्चात मूल।

मेष — आज महिलाओं को अपना व्यवहार संयमित रखना चाहिए। मन में अनेक प्रकार के विचार एक साथ आएंगे। गूढ़ विषयों के अध्ययन के लिये प्रेरित हो सकते हैं। लोगों से अधिक सलाह न लें वरना अनावश्यक भ्रमित हो जाएंगे।

वृष — आज आपके रुके हुए कार्य गतिशील होने की संभावना है। नई तकनीक के प्रति जिज्ञासु रहेंगे। परिश्रम का बेहतरीन परिणाम प्राप्त होगा। आंखों में परेशानी और सिरदर्द की समस्या हो सकती है। जीवनसाथी की भावनाओं को समझें।

मिथुन — आज आपकी सलाह से लोगों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। अचल संपत्ति की खरीदी का विचार मन में आएगा। कार्यक्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। सरकारी जॉब कर रहे लोगों को पदोन्नति मिल सकती है।

कर्क — आज दोपहर के बाद का समय आपके लिए अत्यंत सुखद रहने वाला है। आप लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। अटके हुए धन का लाभ आपको मिलेगा। आपकी दिनचर्या अव्यवस्थित रहने वाली है। कार्यक्षेत्र में आपको सुधार करना पड़ेगा।

सिंह — आज मन में साहसिक कार्य करने की इच्छाशक्ति जागृत होगी। अपनी कमियों को लेकर थोड़े कुंठित हो सकते हैं। अहंकारी व्यवहार के कारण स्वजन आपसे नाराज हो सकते हैं। अधिकारी वर्ग से अपना व्यवहार अच्छा रखें।

कन्या — आज अधीनस्थ कर्मचारी आपसे अत्यधिक प्रसन्न रहने वाले हैं। दूर के स्थानों की यात्रा करने के योग बन रहे हैं। नए कारोबार में आप निवेश कर सकते हैं। मीडिया और प्रकाशन समूह से जुड़े लोगों को आर्थिक लाभ प्राप्त होगा।

तुला — आज विवाहेतर संबंधों से दूरी बनाकर रखें। क्रोध पर नियंत्रण रखें। आपको कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। लोगों के लिए आप प्रेरणा का केन्द्र बनेंगे। घर का वातावरण बहुत ही सुखमय रहेगा। कड़वी भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं है।

वृश्चिक — आज रचनात्मक कार्यों में आप रुचि लेंगे। परिवार में सभी आपसे अत्यंत प्रसन्न रहेंगे। किसी मांगलिक कार्यक्रम की योजना बना सकते हैं। आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। कार्यक्षेत्र में आपके प्रदर्शन की प्रशंसा होगी।

धनु — आज पहले की गई गलती का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आर्थिक मामलों को लेकर आप थोड़े परेशान रहेंगे। अपना मन सदैव शान्त रखें। घरेलू खर्च को लेकर आपका बजट गड़बड़ा सकता है। स्वार्थी लोग आपके संपर्क में रहेंगे।

मकर — आज दिन की शुरुआत किसी शुभ खबर से होगी। आपके कार्य की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। प्रेमीजन के साथ मतभेद दूर होंगे। गलत बातों में अपना समय बर्बाद न करें। व्यवसाय में आपको अपेक्षा से अधिक धन लाभ होगा। प्रेम संबंधों को पर्याप्त समय देंगे।

कुंभ — आज सरकारी नौकरी कर रहे लोगों का मन काम में नहीं लगेगा। कारोबार में आपको बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी होने के कारण मौसमी बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। अपने काम के प्रति निष्ठावान रहें। मन में संतुष्टि का भाव रहेगा।

मीन — आज अनर्गल कार्यों में अधिक ध्यान न लगाएं। सहकर्मी आपकी अत्यधिक सहायता करेंगे। व्यवसाय में आकस्मिक धन हानि झेलनी पड़ सकती है। धार्मिक कार्यों में आपका मन नहीं लगेगा। पिता के किसी निर्णय से आप नाराज हो सकते हैं।

सुडोकू-59

सुडोकू एक तरह का तर्क वाला खेल है, जो एक वर्ग पहेली की तरह होता है। जब आप इस खेल को खेलना सीख जाते हैं तो यह बहुत ही सरलता से खेला जा सकता है। सुडोकू खेल में बॉक्स में 1 नंबर से 9 नंबर तक आने वाले अंक दिए हैं। इसमें कुछ बॉक्स खाली हैं, जिन्हें आपको भरना है। कोई भी अंक दोबारा नहीं आना चाहिए। एक सीधी लाइन और एक खड़ी लाइन तथा बॉक्स में नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए।

		1			4		7	
				3				5
2					9			
6	5			7			8	
			1		8			
	1			6			9	2
			7					8
9				4		3		
	8		3			1		

सुडोकू - 58 का हल

6	1	9	2	5	4	7	3	8
7	2	4	3	8	6	1	9	5
3	5	8	1	9	7	6	2	4
1	6	7	5	3	9	4	8	2
2	4	3	6	7	8	9	5	1
8	9	5	4	2	1	3	6	7
4	3	6	8	1	2	5	7	9
9	8	1	7	6	5	2	4	3
5	7	2	9	4	3	8	1	6

भारतीय टीम 15 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए उत्साहित हैं। हम खेलने के लिए तैयार हैं। हम सभी टीमों पर नजर रखे हैं। हम गेंदबाजों को और बल्लेबाजों को देख रहे हैं।
–तिलक वर्मा

स्टेडियम

बरेली, गुरुवार, 12 फरवरी 2026

अमृत विचार

www.amritvichar.com

अभिषेक की तबीयत खराब होने से मेजबान टीम चिंतित

नई दिल्ली, एजेंसी

मौजूदा चैंपियन भारत को गुरुवार को यहां होने वाले टी20 विश्व कप मैच में नामीबिया से किसी तरह का खतरा नहीं है लेकिन सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के पेट के संक्रमण के कारण मुख्य कोच गौतम गंभीर सहित टीम प्रबंधन चिंतित होगा क्योंकि इससे उसकी योजनाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।

अमेरिका के खिलाफ पहले मैच में वानखेड़े की चिपचिपी पिच पर बल्लेबाज अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। अब उन्हें फिरोज शाह कोटला की पिच पर आक्रामक खेल दिखाना चाहेगा, जिसे बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन पिच कहा जा सकता है। नामीबिया के खिलाफ भारत का पलड़ा बहुत भारी है जिसकी टीम इसी मैदान पर नीदरलैंड्स के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। इस तरह से देखा जाए तो भारत के लिए पाकिस्तान के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले महत्वपूर्ण मैच से पहले यह मैच अभ्यास मैच की तरह है। वहीं, खराब फॉर्म से जूझ रहे संजू सैमसन के लिए लय में लौटने का एक सुनहरा मौका साबित हो सकता है।

टीम

भारत : सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह।

नामीबिया : गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), जान बाल्ट, ज़ेन ग्रीन (विकेटकीपर), मालन क्रूगर, डायलन लीचर, लॉरेन स्टीनकैंप, जान फ्राइलिनक, जान निकोल लोफ्टी-ईटन, विलियम मायबर्ग, जे जे स्मिट, जैक ब्रासेल, मैक्स हेंगो, बर्नार्ड शोल्ट्ज़, बेन शिकोंगो, रूबेन ट्रम्पेलमैन।

दो दिन बाद अस्पताल से मिली छुट्टी, नामीबिया से खेलने पर संदेह

नई दिल्ली। भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को पेट में संक्रमण के कारण दो दिन अस्पताल रहने के बाद छुट्टी मिल गई है, लेकिन नामीबिया के खिलाफ बृहस्पतिवार को यहां होने वाले टी20 विश्व कप क्रिकेट मैच में उनका खेलना संदिग्ध है। मैच से पूर्व प्रेस कांफ्रेंस में भारतीय क्रिकेटर तिलक वर्मा ने कहा कि अभिषेक के कल खेलने को लेकर अभी फैसला नहीं लिया गया है। तिलक ने पत्रकारों से कहा जब हम दिल्ली पहुंचे तो वह चेकअप के लिए अस्पताल गया था। उसे आज छुट्टी मिल गई है और वह ठीक है। मैच में अभी भी एक दिन का समय है। उम्मीद है कि कल इस पर फैसला लेंगे।

- संजू सैमसन के लिए लय में लौटने का एक सुनहरा मौका

बुमराह का यॉर्कर किशन के पैर पर लगा

नई दिल्ली। ईशान किशन ने बुधवार को नेट अभ्यास पर अपना जबर्दस्त फॉर्म बरकरार रखा लेकिन बाद में जसप्रीत बुमराह का यॉर्कर उनके बायें पैर पर लगा। बुमराह ने लगातार दूसरे दिन जमकर गेंदबाजी का अभ्यास किया। वह अमेरिका के खिलाफ पहला मैच नहीं खेले थे। किशन गेंद लगने के बाद नेट्स से चले गए। वह बाद में बल्लेबाजी के लिए आए लेकिन ज्यादा देर बल्लेबाजी नहीं की। नामीबिया के खिलाफ बृहस्पतिवार को बुमराह का खेलना तय लग रहा है। सूर्यकुमार यादव के साथ डीडीसीए अधिकारियों ने खूब सेल्फी खिंचवाई।

अभ्यास सत्र के दौरान कप्तान सूर्यकुमार यादव। एजेंसी

आज के मैच

टीम	समय
श्रीलंका-ओमान	पूर्वाह्न 11 बजे
इटली-नेपाल	दोपहर 3 बजे
भारत-नामीबिया	शाम 7 बजे

हाईलाइट

बांगड़ ने कहा- बेखौफ होकर खेलना जारी रखे भारत

नई दिल्ली। पूर्व बल्लेबाजी कोच संजय बांगड़ ने कहा कि भारत को टी20 विश्व कप के अपने पहले मैच में अमेरिका के खिलाफ बल्लेबाजों की नाकामी का ज्यादा विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है और उसे अपना बेखौफ रवैया जारी रखना चाहिए जिसके कारण उसने काफी सफलता हासिल की हैं। वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए अपने पहले मैच में भारत 13वें ओवर में 77 रन पर छह विकेट खो बैठा था, लेकिन फिर भी उसने अमेरिका पर 29 रन से जीत हासिल की। बांगड़ ने जिओ हॉटस्टार के एक कार्यक्रम में कहा मुझे नहीं लगता कि भारतीय बल्लेबाजों को वानखेड़े में अमेरिका के खिलाफ जो हुआ उसका बहुत अधिक विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि टी20 क्रिकेट में आजकल जिस तरह से भारतीय बल्लेबाज खेल रहे हैं उसमें निश्चित तौर पर जोखिम भरा हुआ है।

अनीश ने रैपिड फायर पिस्टल में कांस्य जीता

नई दिल्ली। विश्व चैम्पियनशिप रजत पदक विजेता अनीश भानवाला ने एशियाई निशानेबाजी चैम्पियनशिप में पुरूषों की 25 मीटर रैपिड फायर स्पर्धा में कांस्य पदक जीता जबकि आठवें दिन कजाखस्तान का दबदबा रहा। अनीश का एशियाई चैम्पियनशिप में यह तीसरा पदक है। एड्रियन कर्माकर ने 50 मीटर राइफल प्रोन जूनियर पुरूष वर्ग में और जूनियर पुरूष 25 मीटर आरएफपी में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता। भारत के अब 41 स्वर्ण, 19 रजत और 15 कांस्य पदक हो गए हैं जबकि स्पर्धा के दो दिन बाकी हैं। अनीश और आदर्श सिंह क्वालीफाइंग दौर में सातवें और आठवें स्थान पर रहे थे। कजाखस्तान के पूर्व चैम्पियन निकिता चिरयुकिन क्वालीफायर में शीर्ष रहे। फाइनल में आदर्श चौथी सीरिज के बाद बाहर हो गए जबकि अनीश, निकिता व जापान के योशिओका संयुक्त बढ़त पर थे।

दूसरे सुपर ओवर में दक्षिण अफ्रीका की अफगानिस्तान पर रोमांचक जीत

टी-20 विश्व कप : पहले 187 और 17 रनों पर टाई हो गया था मुकाबला

अहमदाबाद, एजेंसी

सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज के साहसिक खेल के बावजूद अफगानिस्तान को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बुधवार को यहां रोमांच की पराकाष्ठा तक पहुंचे मैच में दूसरे सुपर ओवर में हार का सामना करना पड़ा जिससे उसकी सुपर आठ में पहुंचने की उम्मीदों को करारा झटका लगा।

दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद छह विकेट पर 187 रन बनाए। इसके जवाब में अफगानिस्तान की टीम 19.4 ओवर में 187 रन पर आउट हो गई। फिर पहला सुपर ओवर भी टाई रहा। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से लुंगी एनगिडी ने सुपर ओवर किया जिसमें अफगानिस्तान ने 17 रन बनाए। इसमें अजमतुल्लाह उमरजई का एक छक्का और दो चौके शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका ने फजलहक फारुकी के ओवर में एक विकेट पर 17 रन बनाए। ट्रिस्टन स्टब्स ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर स्कोर बराबर किया। उमरजई दूसरा सुपर ओवर करने के लिए आए जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने डेविड मिलर के दो छक्कों की मदद से 23 रन बनाए। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर केशव महाराज ने पहली दो गेंद पर कोई रन नहीं दिया और मोहम्मद नबी को आउट किया। गुरबाज ने इसके बाद लगातार तीन छक्के लगाए लेकिन आखिरी गेंद पर वह आउट हो गए।

इस जीत से दक्षिण अफ्रीका के दो मैच में चार अंक हो गए हैं जबकि अफगानिस्तान की यह लगातार दूसरी हार है। उसे अगले चरण में जाने के लिए न सिर्फ अपने बाकी बचे दोनों मैच जीतने होंगे बल्कि अन्य मैच के परिणाम भी अनुकूल रहने के लिए दुआ करनी होगी। अफगानिस्तान इससे पहला लक्ष्य हासिल करने की स्थिति में था लेकिन लगातार विकेट गंवाने के कारण उसे नुकसान हुआ। उसकी तरफ से गुरबाज ने 42 गेंद पर 84 रन बनाए जिसमें चार चौके और सात छक्के शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका के लिए एनगिडी ने 26 रन देकर तीन विकेट लिए। इससे पहले रयान रिकेल्टन ने 28 गेंद पर 61 रन की तूफानी पारी खेली जिसमें पांच चौके और चार छक्के शामिल हैं। क्विंटन डीकॉक ने 41 गेंद पर पांच चौकों और तीन छक्कों की मदद से 59 रन बनाए। कप्तान एडन मार्करम (05) के जल्दी आउट होने के बाद 114 रन की साझेदारी की।

सुपर ओवर में अफगानिस्तान पर जीत दर्ज करने के बाद जश्न मनाते दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी। एजेंसी

संक्षिप्त स्कोर

दक्षिण अफ्रीका 187/6 (20 ओवर)
- मार्क रयान रिकलेटन 61
- क्विंटन डी कॉक 59

गेंदबाजी : अजमतुल्लाह उमरजई 3-41, राशिद खान 2-28

अफगानिस्तान 187/10 (19.4 ओवर)
- रहमानुल्लाह गुरबाज़ 84
- अज़मतुल्लाह उमरज़ई 22

गेंदबाजी : लुंगी एनगिडी 3-26, केशव महाराज 1-27

पहला सुपर ओवर : टाई

अफगानिस्तान - 6 बॉल में 17/0

दक्षिण अफ्रीका - 6 बॉल में 17/1

दूसरा सुपर ओवर: द. अफ्रीका 4 रन से जीता

दक्षिण अफ्रीका - 6 बॉल में 23/0

अफगानिस्तान - 6 बॉल में 19/2

खिलाड़ियों से कहा था कि आखिर तक लड़ना होगा

दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम ने टीम के साथी खिलाड़ियों से कहा था कि उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ 'चुनौती' के लिए तैयार रहना होगा और बुधवार को यहां खेला गया यह मैच टी20 विश्व कप के इतिहास के सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक साबित हुआ। इसे शब्दों में बयां करना काफी मुश्किल है। जीत और अंक मिलने के लिए शुक्रगुजार हूं। मार्करम ने कहा आखिरकार सुपर ओवर में आप अपने बेहतर, सबसे आत्मविश्वास से भरे खिलाड़ी को चुनते हैं। पहले ओवर में लुंगी से ज्यादा गलती नहीं हुई, लेकिन फिर उन्होंने अच्छा स्कोर बना लिया। केशव के साथ भी यही कहानी रही। स्पिनर के लिए यह मुश्किल होता है, फिर भी हमने उन पर भरोसा किया। उन्होंने कहा मैंने लड़कों से कहा था कि लक्ष्य ठीक है, लेकिन हमें चुनौती का सामना करना होगा।

वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को 30 रनों से परास्त किया

मुंबई, एजेंसी

- शेरफेन रदरफोर्ड की विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद गुडाकेश मोती ने की घातक गेंदबाजी

शेरफेन रदरफोर्ड के नाबाद 76 रन और गुडाकेश मोती के तीन विकेट की मदद से वेस्टइंडीज ने बुधवार को टी20 विश्व कप के ग्रुप सी के अहम मुकाबले में इंग्लैंड को 30 रन से हरा दिया।

रदरफोर्ड ने चिर परिचित कैरेबियाई अंदाज में खेलते हुए 42 गेंद में पांच छक्कों और दो चौकों की मदद से नाबाद 76 रन बनाकर वानखेड़े स्टेडियम पर मौजूद करीब 21000 दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। वहीं मोती ने गेंदबाजी में 32 रन देकर तीन विकेट चटकाए। जीत के लिए 197 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम 19 ओवर में 166 रन पर आउट हो गई। सैम कुरेन ने सर्वाधिक 43 रन की नाबाद पारी खेली। फिल साल्ट ने 14 गेंद में 30 रन बनाये जिसमें चार चौके और दो छक्के शामिल थे। उन्होंने जैसन होल्डर के दूसरे ओवर में 24 रन निकाले। साल्ट को रोमारियो शेफर्ड ने कवर में रदरफोर्ड के हाथों लपकवाया। पावरप्ले के बाद इंग्लैंड का स्कोर एक विकेट पर 67 रन था। जोस बटलर (21) भी ज्यादा देर टिक नहीं सके। वह रोस्टन चेस की गेंद पर लांग आन में पॉवेल को कैच देकर लौटे। इसके बाद मोती ने इंग्लैंड को दोहरे झटके दिए। पहले उन्होंने टॉम बेंटोन (दो) को कवर में कैच आउट कराया और इसके बाद जैकब बेथेल (33) को चाइनामैन गेंद पर आउट किया। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक (17) मोती को रिटर्न कैच देकर लौटे। इससे पहले रदरफोर्ड के नाबाद 76 रन की मदद से वेस्टइंडीज ने खराब शुरूआत से उबरते हुए छह विकेट पर 196 रन बनाए। वेस्टइंडीज ने दस ओवर के बाद 79 रन पर चार विकेट गंवा दिए थे। पर आखिरी दस ओवर में 117 रन बने। रदरफोर्ड ने पांचवें विकेट के लिये रोवमैन पॉवेल (14) के साथ 51 रन की साझेदारी की। इसके बाद पूर्व कप्तान जैसन होल्डर (17 गेंद में चार छक्कों, एक चौके की मदद से 33 रन) के साथ छठे विकेट के लिये 32 रन जोड़े। टेस्ट कप्तान रोस्टन चेस ने चौथे नंबर पर उतरकर 34 रन बनाए। होल्डर ने आखिरी ओवरों में सैम कुरेन को एक ही ओवर में तीन छक्के लगाए। रदरफोर्ड को 18वें ओवर में आदिल रशीद ने जीवनदान दिया था। होल्डर ने आतिशी पारी खेलकर रदरफोर्ड पर से दबाव कम किया। पिछले मैच में नेपाल के बल्लेबाजों से नसीहत पाने वाले रशीद ने मजबूती से वापिस की और 16 रन देकर दो विकेट चटकाए।

टीम के साथ जश्न मनाते वेस्टइंडीज के गुडाकेश मोती। एजेंसी

इस तरह की हार लंबे समय तक चुभती है : अफगानिस्तान के कोच ट्रॉट

अहमदाबाद। अफगानिस्तान के कोच जोनाथन ट्रॉट ने टी20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका से दूसरे सुपर ओवर में मिली हार के बाद कहा कि इस तरह की हार लंबे समय तक चुभती है लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि दक्षिण अफ्रीका ने क्षेत्ररक्षण में उनकी टीम को कमजोर साबित किया। टी20 विश्व कप के इतिहास के सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक में दक्षिण अफ्रीका ने दो सुपर ओवर के बाद अफगानिस्तान को हराया। ट्रॉट ने मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा इससे साबित होता है कि हमारे पास कितनी शानदार टीम है। हमारे पास कुछ बेहतरीन खिलाड़ी हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ कुछ दिन पहले मिली हार के बाद दक्षिण अफ्रीका से करीबी मुकाबला हारना दिल तोड़ने वाला है। हमें कठिन ग्रुप भी मिला है। दक्षिण अफ्रीका में जन्मे इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ट्रॉट ने कहा कि इस तरह की हार लंबे समय तक चुभती है। उन्होंने कहा टीम को अपने प्रदर्शन पर गर्व होना चाहिये लेकिन कई बार इस तरह की हार लंबे समय तक चुभती है। अब अहम यह है कि हम इसके सकारात्मक पहलुओं को देखें और यह भी प्रयास करें कि जहां गलतियां हुई हैं, उनमें सुधार हो। ट्रॉट ने कहा दक्षिण अफ्रीका की फील्डिंग बहुत अच्छी थी। रन आउट, सीमा पर कैच और रन बचाने के प्रयास। जबर्दस्त फील्डिंग और शायद यही फर्क था। ट्रॉट के कोच रहते अफगानिस्तान पिछले टी20 विश्व कप सेमीफाइनल और 2023 वनडे विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी। इस विश्व कप के बाद वह टीम से विदा ले रहे हैं लेकिन अभी इस बारे में उन्होंने कुछ कहने से इनकार किया। उन्होंने कहा टूर्नामेंट खत्म होने के बाद इस पर बात करेंगे। अभी दो अहम मैच खेलने हैं। अभी कुछ और बात करने का समय नहीं है। मैं अभी भी कोच हूं और मुझे यह सुनिश्चित करना है कि दिल्ली में यूएई के खिलाफ हम अच्छा खेलें।

एलिस-जम्पा की मारक गेंदबाजी ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को हराया

कोलंबो, एजेंसी

ऑस्ट्रेलिया ने तेज गेंदबाज नाथन एलिस (12 रन देकर चार विकेट) और लेग स्पिनर एडम जम्पा (23 रन देकर चार विकेट) के शानदार प्रदर्शन से बुधवार को यहां ग्रुप बी मैच में आयरलैंड पर 67 रन की जीत के साथ आईसीसी टी20 विश्व कप में अपना अभियान शुरू किया। एलिस ने अपने शुरूआती स्पैल में तीन विकेट झटककर जीत की लय तय की। उन्होंने शीर्ष क्रम को पवेलियन भेजा तो वहीं जम्पा ने मध्य और निचले क्रम पर कहर बरपाया जिससे आयरलैंड की पारी 183 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 16.5 ओवर में नौ विकेट 115 रन पर खत्म हुई।

आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग एक गेंद खेलने के बाद रिटायर्ड हर्ट हो गए और फिर बल्लेबाजी करने नहीं उतरे।

ऑस्ट्रेलिया ने तेज गेंदबाज नाथन एलिस।

आयरलैंड के लिए जॉर्ज डॉकरेल ने सर्वाधिक 41 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने धीमी पिच पर टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए हरफनमौला मार्कस स्टोइनिस (45 रन) और मैथ्यू रेनशॉ (37 रन) के बीच पांचवें विकेट के लिए 61 रन की अहम साझेदारी की मदद से छह विकेट पर 182 रन का प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया। आयरलैंड की टीम ने लक्ष्य का पीछा करते हुए पावरप्ले में चार विकेट गंवा दिए थे। मिचेल मार्श ग्रोइन चोट के कारण टूर्नामेंट से लगभग बाहर हो गए हैं। पैट कमिंस और जोश हेजलवुड भी चोट के कारण बाहर हैं जबकि मिचेल स्टार्क संन्यास ले चुके हैं तो एलिस ने मुख्य तेज गेंदबाज के तौर पर जिम्मेदारी बखूबी निभाई। एलिस ने इस तरह तीन ओवर के शुरूआती स्पैल में नौ रन देकर तीन विकेट लिए। उन्होंने रोस एडेयर (12), कर्टिस कैम्फर (04), बेन कालिट्ज (02) को आउट किया। फिर जम्पा ने गेरेथ डेलानी (11), लोरकान टकर (24), डॉकरेल और मार्क एडेयर (12) के विकेट झटके। आयरलैंड हालांकि 100 रन का स्कोर पार करने में कामयाब रहा। आखिर में एलिस अपना अंतिम ओवर करने के लिए आए और बैरी मैकार्थी (02) को आउट करके मैच खत्म किया।

ग्रीनपार्क या इकाना में होगा रणजी ट्रॉफी का सेमीफाइनल

देहरादून। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के पिच क्यूरेटर ने उत्तराखंड में देहरादून के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का दौरा करने के बाद मंगलवार को अपनी रिपोर्ट में यहां के मैदान की हालत को बेहद निराशाजनक बताया है। इससे यहां रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल की मेजबानी को लेकर झटका लगा है।

क्यूरेटर राकेश कुमार ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा कि स्टेडियम की पिच और आउटफील्ड का स्तर इतना खराब है कि यहां सेमीफाइनल जैसा महत्वपूर्ण मुकाबला आयोजित नहीं किया जा सकता। निरीक्षण टीम के अनुसार, ग्राउंड का रखरखाव मानकों के अनुरूप नहीं है। सूत्रों की मानें तो बीसीसीआई अब इस सेमीफाइनल को कानपुर के ग्रीनपार्क या लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आयोजित करने पर विचार कर रहा है।

तैयारी पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने कहा- मुकाबले के प्रति टीम बेहद गंभीर

भारत के खिलाफ अलग मानसिकता के साथ खेलेंगे

कोलंबो, एजेंसी

पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने अपने चिर प्रतिद्वंद्वी भारत के खिलाफ रविवार को यहां होने वाले टी20 विश्व कप मैच को एक आम मैच करार दिया। लेकिन इसके साथ ही कहा कि इस बार उनकी टीम इस मुकाबले में अलग मानसिकता के साथ उतरेगी। पाकिस्तान की टीम नीदरलैंड और अमेरिका को हराने के बाद ग्रुप ए में शीर्ष पर काबिज हो गई है। नीदरलैंड को हराने में उसे संघर्ष करना पड़ा था लेकिन अमेरिका को उसने आसानी से 32 रन से हराया जिसमें फरहान ने एक 41 गेंद में 73 रन की शानदार पारी खेली।

मैच के बाद संवाददाता सम्मेलन में फरहान से भारत के खिलाफ होने वाले मैच के बारे में पूछा गया जो पाकिस्तान सरकार द्वारा बहिष्कार की अपील वापस लेने के बाद अपने

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 15 फरवरी को खेला जाएगा।

फरहान ने कहा लगातार दो मैच जीतने और तालिका में शीर्ष पर काबिज होने से आत्मविश्वास मिलता है। अगला मैच भी एक आम मैच जैसा ही होगा। यह पहला अवसर नहीं है जबकि हम उनके खिलाफ खेलेंगे। उन्होंने कहा हम पहले भी उनके खिलाफ खेल चुके हैं लेकिन इस बार हमारी मानसिकता अलग होगी। आपने देखा ही होगा कि शादाब (खान) रन बना रहे हैं, (मोहम्मद) नवाज़ रन बना रहे हैं। उम्मीद है कि आपको उनके खिलाफ हमारा खेल पसंद आएगा। फरहान ने कहा यह एक सामान्य मैच होगा और हम इसे एक अन्य मैच की तरह ही लेंगे। हम यह नहीं सोचेंगे कि यह भारत और पाकिस्तान का मैच है। हम इसे एक सामान्य मैच की तरह ही खेलेंगे।

भारत का पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड शानदार रहा है। उसने हाल में एशिया कप में पाकिस्तान को सभी मैच में हराया था। तब भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा था कि हाल के वर्षों में उनकी टीम के दबदबे को देखते हुए वह अब पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिद्वंद्विता को बराबरी का नहीं मानते हैं। फरहान हालांकि इससे सहमत नहीं हैं। उन्होंने कहा मैं ऐसा नहीं मानता।

मेरा आत्मविश्वास और भी बढ़ गया

फरहान से जब पूछा गया कि क्या उनके पास भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का सामना करने के लिए कोई विशेष योजना है, तो उन्होंने कहा मुझे लगता है कि जब आप रन बनाते हैं तो आप आत्मविश्वास से भर जाते हैं। मैं भी बहुत आत्मविश्वास से भरा हूं और जिस तरह से मैंने पिछली दो पारियां खेली हैं, उससे मेरा आत्मविश्वास और भी बढ़ गया है। उन्होंने कहा मैं ऐसा नहीं मानता। एशिया कप में हमने जिस तरह से प्रदर्शन किया उसे देखते हुए मुकाबले एकतरफा नहीं थे। हमने आखिर तक डटकर मुकाबला किया था। उम्मीद है कि इस बार भी हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। पाकिस्तान के लगातार दो मैच जीतने से फरहान काफी उत्साहित हैं।